3 | राजधानी
बरसात से कई क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम

6 | अभिमत
एमएसएमई हेतु आयकर संशोधन

11 | विदेश
ब्रिटेन में सैनिक पर हथियार से हमला

12 | स्पोर्ट्स
फिर आईओसी सदस्य चुनी गईं नीता अंबानी

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 12 अंक 256
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

शहरों में एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए धन का आवंटन

राष्ट्रीय-10

बजट पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन

बजट में किसी भी राज्य की उपेक्षा नहीं हुई : सीतारमण

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद के अंदर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गुट से जुड़े सांसदों ने दिन के दौरान संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और राज्यसभा से भी वॉकआउट किया, जबकि अनुच्छेद 356 की तरह, आपातकाल लागू होने पर सत्तारूढ़ बेंच के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों के आरोपों को 'अपमानजनक' बताया और कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले बजटों सहित सभी राज्यों का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट 'भारत के संघीय ढांचे की पवित्रता पर हमला' है। सत्तारूढ़ भाजपा ने केंद्रीय बजट के विपक्षी शासित राज्यों के प्रति 'भेदभावपूर्ण' होने के कांग्रेस के आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि मोदी सरकार ने हर राज्य और वर्ग का ख्याल रखा है।

नई दिल्ली में सोमवार को बजट में कथित भेदभाव के विरोध में इंडिया गुट के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वाम दलों के कई सांसद शामिल हुए। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, आज इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ, संसद भवन परिसर में एनडीए के 'कुर्सी बचाओ बजट' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, विरोध जारी रखने के लिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों के गैर-भाजपा नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा नियम 267 के तहत नोटिस को खारिज करने के बाद, जिसमें इस मुद्दे को उठाने के लिए सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित करने का आह्वान किया गया था। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लिए केंद्रीय बजट केवल दो राज्यों - बिहार और आंध्र प्रदेश - के लिए धन और योजनाएँ प्रदान की गईं। जैसे ही धनखड़ ने सीतारमण को जवाब देने के लिए मंच दिया, खड़गे ने विपक्षी दल को यह कहते हुए सदन से बाहर कर दिया कि वे विरोध स्वरूप बहिर्गमन कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उन्होंने आम चुनाव से पहले फरवरी में पेश (शेष पेज 9)

केंद्र का सख्त संदेश, आतंकियों का अंतिम ठिकाना जेल या जहन्नुम

उत्तर कश्मीर के सोपोर स्थित त्रिमुखा इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठबेड़ के दौरान सुरक्षा में तैनात जवान।

उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा में मुठभेड़ में एक दहशतगर्द ढेर, एक जवान शहीद

मोहित कंडारी। जम्मू/नई दिल्ली

केंद्र ने बुधवार को एक सख्त संदेश भेजा कि जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को या तो जेल में डाल दिया जाएगा या 'जहन्नुम' (नरक) में भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी रक्षा कोर टीम द्वारा हाल के दिनों में लगातार जम्मू आतंकी हमलों के लिए समीक्षा बैठक की श्रृंखला के कुछ दिनों बाद, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार की जीरो टालरेंस की नीति है। इस बीच, बुधवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ चल रही मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया, जबकि भारतीय सेना के एक और जवान ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहादुर की पहचान नायक (जीएनआर) दिलवर खान के रूप में की गई है। जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों में आतंकवादी हिंसा की यह तीसरी घटना है। सोमवार को राजौरी की खवास तहसील में आतंकवादियों ने शौर्य चक्र विजेता के घर को निशाना बनाया, जबकि मंगलवार को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए सेना के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी।.

राय ने संसद में कहा, 'मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करती। हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। वे (आतंकवादी) या तो जेल में होंगे या जहन्नुम में... मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। हाल ही में देखी गई आतंकवादी गतिविधियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। वे (आतंकवादी) सफल नहीं होंगे। राजौरी ताजा घटना में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया और एक सैनिक घायल हो गया, जिसने बाद में दम तोड़ दिया। चिनार कोर के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर 23 जुलाई को कुपवाड़ा के कोवुत के सामान्य क्षेत्र में भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था। 24 जुलाई को, संदिग्ध गतिविधि देखी गई और सतर्क सैनिकों द्वारा चुनौती दी गई। जिसके जवाब में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले कुछ (शेष पेज 9)

बिहार विधानसभा में पेपर लीक रोकने संबंधी विधेयक पारित

पायनियर समाचार सेवा। पटना

बिहार विधानसभा ने बुधवार को राज्य द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया। बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए कानून का लक्ष्य राज्य में प्रश्नपत्रों के लीक होने सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार पर अंकुश लगाना है, जो संयोग से, नीट 2024 पेपर लीक विवाद के केंद्र में भी रहा है। विधेयक में ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। चौधरी ने सदन को बताया कि सेवा प्रदाता, इस तरह के परीक्षण करने वाली एजेंसियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने (शेष पेज 9)

शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें: सुप्रीम कोर्ट

पीएनएस। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की एमएसपी को कानूनी रूप देने सहित विभिन्न मांगों का समाधान तलाशने के लिए उनसे बातचीत करने के वास्ते प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक स्वतंत्र समिति गठित करने का बुधवार को प्रस्ताव दिया और कहा कि किसानों तथा सरकार के बीच विश्वास की कमी है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को समिति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही शंभू बॉर्डर पर एक सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि एक तटस्थ अंपायर की आवश्यकता है जो किसानों तथा सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल

भुइयां भी शामिल रहे। इसने कहा, आपको किसानों से बातचीत करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अन्यथा वे दिल्ली क्यों आएंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनके नेक इरादों के बावजूद विश्वास की कमी है। न्यायालय ने कहा, एक सप्ताह के अंदर उचित निर्देश दिए जाएं। तब तक शंभू बॉर्डर पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी पक्षकारों को प्रदर्शन स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने दें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले स्पताह तक के लिए टाल दी। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधकों को हटाने का निर्देश दिया था, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कें अवरुद्ध की गईं और अब उनकी नई मांगें हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को कल्याणकारी राज्य के रूप में किसानों की मांगों की पर विचार करना होगा। पीठ ने कहा, कुछ मांगें वाजिब हो सकती हैं, (शेष पेज 9)

काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राहत और बचाव कार्य।

काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान हादसे में 18 लोगों की मौत

पायलट गंभीर रूप से घायल, मृतकों में एक विदेशी भी

पीटीआई। काठमांडू

काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे में एक विदेशी समेत 18 यात्रियों की मौत हो गई तथा उसका पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। सौर्य एयरलाइंस का नेपाल का घरेलू विमान एन9एएमई नियमित रखरखाव कार्य के लिए पोखरा जा रहा था जब पूर्वाह्न 11 बजकर 11 मिनट पर यह हादसा हुआ। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के खोज व बचाव केंद्र ने एक बयान में बताया कि बमबॉर्डियर सीआरजे-200 विमान रनवे पर फिसल गया और उसमें तुरंत आग लग गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में विमान में आग लगते और धुआं उठते देखा जा सकता है। हादसे के बाद दमकल की गाड़ियों और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया। मृतकों की पहचान सह-पायलट एस. कतुवाल और सौर्य एयरलाइंस के 17 कर्मचारियों के रूप में की गई है जिनमें नेपाल की एक महिला और यमन का एक नागरिक शामिल है। पायलट कैप्टन मनीष शाक्य (37) का काठमांडू मॉडल हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है। प्राधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार लोगों में से 15 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीन की एक स्थानीय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद काठमांडू हवाई अड्डे पर सेवाएं थोड़ी देर के लिए रोक दी गईं लेकिन बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। (शेष पेज 9)

बाधा मुक्त टोलिंग के लिए लाएंगे जीएनएसएस

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर निर्बाध और बाधा मुक्त टोलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए, सड़क और परिवहन मंत्रालय ने वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस)-आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। जहां फास्टैग वाले वाहनों की लंबी कतारों की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं, शुरुआत के लिए जीपीएस पर आधारित प्रणाली का उपयोग पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया जाएगा।

आमतौर पर सिस्टम फास्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर को जियो फेंस करेगा और लागू होने वाले टोल टैरिफ को डेबिट किया जाएगा, जिससे टोल प्लाजा के माध्यम से आसान पहुंच हो

जाएगी। इससे समय और वाहन बैकलॉग की बचत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में पायलट अध्ययन कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर किया गया है। नितिन गडकरी के नेतृत्व वाले सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से एक हितधारक परामर्श आयोजित किया था, जिसके लिए इस संबंध में व्यापक औद्योगिक परामर्श के लिए वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोलिंग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की एक बाधा मुक्त विधि है जिसमें सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल राजमार्ग पर तय की गई दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाता है। एनएचएआई ने मौजूदा फास्टैग पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीएनएसएस-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में एक हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा जहां आरएफआईडी-आधारित (शेष पेज 9)

आईएनएस ब्रह्मपुत्र हादसे में लापता नाविक का शव मिला

पीटीआई। नई दिल्ली

मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में भारत के प्रमुख युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी भीषण आग के बाद लापता हुए मुख्य नाविक सितेन्द्र सिंह का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार शाम को आग लगने के बाद युद्धपोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक ओर झुक गया। नौसेना के

आईएनएस ब्रह्मपुत्र हादसे की फाइल फोटो

प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, गहन अभियान के बाद आज मुख्य नाविक सितेन्द्र सिंह का शव बरामद कर लिया गया। उन्होंने कहा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी और भारतीय नौसेना के सभी कर्मी सिंह के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मधवाल ने कहा कि नौसेना प्रमुख ने आईएनएस ब्रह्मपुत्र को फिर से समुद्री अभियानों में सक्षम बनाने और लड़ाकू भूमिका के लिए तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि एडमिरल त्रिपाठी ने आईएनएस ब्रह्मपुत्र के चालक दल से पोत के शीघ्र परिचालन की दिशा में काम करने का आह्वान किया। नौसेना ने एक बयान में कहा, नौसेना प्रमुख ने निर्देश दिया है कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र को समुद्री अभियानों के लिए समक्ष बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के वास्ते कमान और नौसेना मुख्यालय द्वारा सभी कार्वाई तत्काल शुरू की जाए। (शेष पेज 9)

कार के बोनट पर स्टंट कर रहा था स्पाइडरमैन, हजारों का कटा चालान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सोशल मीडिया के दौर में रील बनाकर मिनटों में शोहरत पाने की चाह का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई युवा इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने फॉलोअर्स को लुभाने के लिए खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन कर खुद के साथ दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी कड़ी में स्पाइडरमैन की पोशाक पहनकर स्कार्पियो कार के बोनट पर बैठकर दिल्ली में घूमना एक युवक को महंगा पड़ा। यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर उसका 26 हजार रुपए का चालान किया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए शिकायत मिली कि द्वारका की सड़कों पर एक युवक स्पाइडरमैन की वेशभूषा में स्कॉर्पियो कार के बोनट पर बैठकर घूम रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कार का पीछा किया और द्वारका के रामफल चौक के नजदीक उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि स्पाइडरमैन की वेशभूषा वाले व्यक्ति की पहचान नजफगढ़ निवासी आदित्य के रूप में हुई जबकि कार महावीर एन्क्लेव निवासी गौरव सिंह चला रहा था।

अधिकारी ने बताया कि वाहन के मालिक और चालक को खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने, सीट बेल्ट लगाए बिना वाहन चलाने के आरोप में चालान काटा गिया है जिसमें अधिकतम 26 हजार रुपए जुर्माना या कारावास या दोनों सजा का प्रावधान है। दिल्ली यातायात पुलिस सभी नागरिकों के लिए सड़क पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। अधिकारी

पुलिस की गिरफ्त में स्पाइडरमैन बना युवक।

ने कहा कि सड़क पर इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस युवक ने सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के मकसद से इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है। इससे पहले, उसे दक्षिण पश्चि दिल्ली के द्वारका में बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर रील के वायरल होने के बाद, ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया और उसे स्पाइडरवुमन की पोशाक पहने एक अन्य महिला के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान जारी किया। खुद को नजफगढ़ का स्पाइडरमैन कहने वाला यह युवक कई बार सुपरहीरो की पोशाक पहनकर दिल्ली की सड़कों पर निकल चुका है। वह इंडियन स्पाइडी ऑफिशियल नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है, जहां वह अपने स्टंट के वीडियो पोस्ट करता है।

लड़के के डीपी में लिखा है योर फ्रेंडली नेबरहुड इंडियन स्पाइडी और अकाउंट के 12,500 से ज्यादा फॉलोअर हैं। वायरल वीडियो को एक लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। उसके इंस्टाग्राम पेज पर एक सरसरी नजर डालने पर इंडियन स्पाइडी बैडमिंटन खेलता, ट्रैक्टर चलाता और ट्रेंडिंग गानों पर नाचता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से सड़कों पर इस तरह से खतरनाक स्टंट नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई इस तरह की हरकत करना पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने नागरिकों से खतरनाक ड्राइविंग या यातायात नियमों के किसी तरह के उल्लंघन करने की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा बनाए रखने और शहर में यातायात के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है।

एक्सप्रेसवे पर बनेगा 749 मी. लंबा अंडरपास

● 131 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 10 सेक्टर के लोगों को होगा फायदा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अंडर पास बनाया जाएगा। ये अंडर पास 131 करोड़ में तैयार होगा।

सैद्धांतिक मंजूरी के बाद इस अंडर पास वैरिफिकेशन के लिए आईआईटी दिल्ली भेजा गया है। वहां से आने के बाद टेंडर जारी कर निर्माण शुरू कराया जाएगा। अंडर पास के एक तरफ सेक्टर-145, 146 और दूसरी तरफ सेक्टर-155, 159 सेक्टर हैं।

इसके सामने झट्टा गांव है। यहां पर भी छोटा अंडर पास बना हुआ है। पिछले एक साल में एक्सप्रेस वे पर सेक्टर-96, 142 और 152 के सामने नए अंडर पास शुरू हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि अंडर पास की लंबाई 749 मीटर का होगा। 4 लेन का होगा। इसमें आने जाने के लिए 2-2 लेन होगी। साथ 75 मीटर की टनल या बाक्स लैंथ होगी। ये अंडर पास एक्सप्रेस वे के नीचे बनाया जाएगा। जिससे सेक्टर-145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 को फायदा होगा। ये सभी सेक्टर रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल है। ऐसे में एक्सप्रेस वे तक इनकी सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथ ये अंडर पास सीधे ग्रेटरनोएडा को भी जोड़ेगा। अंडर पास बनाने में नोएडा प्राधिकरण ने तकनीक में बदलाव करने की योजना बनाई है।

2020 के बाद एक्सप्रेस वे पर कोंडली, एडवंट और सेक्टर-96 अंडर पास बॉक्स पुशिंग तकनीक पर बनवाए गए थे। इसमें लगातार एक्सप्रेस वे की सड़क धंसने की समस्याएं सामने आई थीं। इसलिए अबकी बार झट्टा व सुल्तानपुर अंडर पास के लिए प्राधिकरण डायाफ्राम तकनीक का सिलेक्शन किया है। इसमें बगैर खुदाई के डायाफ्राम वॉल कास्ट की जाएगी।

इसके बाद दो तरफ जमीन के अंदर यह दीवार बनाकर उसके ऊपर अंडर पास की छत ढाल दी जाएगी। नीचे दोनों दीवारों व छत के बीच की मिट्टी खुदाई कर निकाली जाएगी। इसके बाद नीचे की सड़क का काम शुरू होगा। इसी तरह से दोनों लेन का काम प्राधिकरण करवाएगी। इसके कारण कुछ दिनों तक ट्रैफिक का संचालन प्रभावित रहेगा। बीते एक साल के अंदर एक्सप्रेस वे पर तीन अंडर पास वाहनों के लिए खोले भी जा चुके हैं।

इसमें सेक्टर-96, कोंडली और एडवंट अंडर पास शामिल है। इनको बनाने में कई बार एक्सप्रेस वे की सड़क धंस गई थी। ऐसे में इस बार डायाफ्राम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इन तीनों अंडर पास से एक्सप्रेस से जुड़े सेक्टरों में कनेक्टिविटी बढ़ गई।

विदेश भेजने और ठगी करने वाला गिरफ्तार

नोएडा। सेंट्रल नोएडा की बिसरख थाना पुलिस, आईटी सेल और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विदेश में बैठकर भारत के लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के फरार चल रहे एक सदस्य को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। यह पिछले कई महीने से लगातार फरार चल रहा था। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन व एक लैपटॉप बरामद किए गए हैं। दरसअल थाना बिसरख पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से शातिर ठग राहुल सिन्हा को कलकत्ता पंश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। बिसरख थाना प्रभारी अरविंद कुमार के द्वारा बताया गया कि पकड़े गए आरोपी राहुल सिन्हा के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ में मिलकर विदेशों (कम्बोडिया, होंगकांग) में बैठकर भारतीय सिम पर व्हाट्सएप अकाउन्ट तैयार कर भारतीय नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी कर पैसे की ठगी करते थे।

बजट ने घर खरीदारों की बढ़ाई परेशानी रियल एस्टेट कारोबारियों ने की सराहना

● मोदी सरकार बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर दे रही : बिल्डर ग्रुप

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

केंद्रीय बजट 2024-25 कल पेश किया जिसमें गृह ऋण पर उच्च ब्याज दर और स्टांप ड्यूटी में वार्षिक वृद्धि जैसे आम आदमी से जुड़े मामले पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से घर खरीदार निराश हैं वहीं रियल एस्टेट से जुड़े करोबारी बजट से खुश हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का मानना है कि संपत्ति सौदे में इंडेक्सेशन लाभ को हटाना घर खरीदारों के लिए एक बड़ा झटका होगा।

सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने और मुद्रास्फीति के समायोजन (इंडेक्सेशन) से जुड़े लाभ हटाने का प्रस्ताव रखा है। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एनईएफओडब्ल्यूए) के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा, इस बजट ने घर खरीदने वालों को निराश किया है, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान या राहत की पेशकश नहीं की गई है। नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एनओएफएए) के अध्यक्ष राजीव सिंह का मानना है कि यह बजट घर खरीदारों के लिए एक बड़ा झटका होगा। सिंह ने कहा, इंडेक्सेशन लाभ को हटाना उन लोगों के लिए काफी हद तक नकारात्मक है जो अपनी पुरानी संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं। इस नई नीति से उनके पूंजीगत लाभ में काफी कमी आएगी।

इस बीच बिल्डरों ने बजट की सराहना की। ऐस ग्रुप के सीएमडी अजय चौधरी ने कहा, मोदी सरकार बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर दे रही है। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भूटानी समूह के सीईओ आशीष भूटानी ने कहा कि एक करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य वाली प्रधानमंत्री आवास योजना निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घर खरीदना अधिक सुलभ बनाएगी।

तालाब ओवर फ्लो होने पर घरों में घुसा पानी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● थोड़ी देर की बारिश में कई इलाकों में जलभराव की मिली शिकायतें

तहसील दादरी क्षेत्र के आनंदपुर गांव में मानसून की बरसात होने के चलते गांव का तालाब बरसात के पानी से ओवर फ्लो हो गया है, जिससे आसपास के घरों एवं मंदिर में पानी भर गया। पानी भरने के चलते जहरीले की कीटों का खतरा बना हुआ है तथा जलभराव को लेकर ग्रामीण बेहद परेशान है ।

बुधवार को सुबह के समय मानसून की बरसात होने के चलते तहसील दादरी क्षेत्र के आनंदपुर गांव का तालाब में बरसात का पानी अधिक होने के चलते ओवर फ्लो हो गया है। ओवर फ्लो होने के चलते बरसात का पानी आसपास के घरों में भर गया है तथा तालाब के पास बने मंदिर में भी पानी का जलभराव हो गया।

तालाब में जलभराव का ओवर फ्लो होने के चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी को कई बार शिकायत की गई है। लेकिन प्राधिकरण अधिकारी एवं प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई । जिससे ग्रामीणों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है । तालाब में बरसात के पानी का ओवर फ्लो होने के चलते घरों में पानी घुसने पर जहरीले कीटों का खतरा बना हुआ है । साथ ही मंदिर में पानी भर जाने के चलते ग्रामीण जहां पूजा अर्चना करने को लेकर परेशान है। वहीं मंदिर के पुजारी भी जहरीले कीट जल भराव में आने से बेहद परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्राम प्रधान कपिल कुमार ने बताया कि कई बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा जिलाधिकारी को गांव के तालाब की सफाई करने एवं जल भराव से ओवरफ्लो की समस्या का समाधान के लिए शिकायत कर चुके हैं । लेकिन इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया । जिसके चलते ग्रामीणों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पानी में जहरीले कीड़े आने के चलते डर सता रहा है नोएडा में हवा में नमी की मात्रा 97 प्रतिशत और हवा की रफ्तार 10 किमी प्रतिघंटा रिकार्ड की गई। सुबह बारिश के दौरान तापमान 28 डिग्री रिकार्ड किया गया।

मासूम बच्चे के साथ आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही महिला

नोएडा। थाना बिसरख क्षेत्र में स्थित वैलेंसिया होम्स सोसाइटी के टावर आई की लिफ्ट में मासूम बच्ची केयर टेकर के साथ 25 मिनट तक फंसी रही। अंधेरा और गर्मी होने के कारण मासूम का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकला गया।

घटना के बाद से निवासियों में रोष हैं। आरोप है कि अलार्म बजाया गया, लेकिन तब सुरक्षाकर्मी टावर पर मौजूद नहीं था। सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि अजय वर्मा अपने परिवार के साथ टावर आई की 13वीं मंजिल पर रहते हैं। रोजाना शाम के समय केयरटेकर उनके एक वर्ष के बच्चे को नीचे टहलाने के लिए ले जाती हैं। केयर टेकर बच्चे को लेकर लिफ्ट से नीचे जा रही थी। शाम 4:48 बजे जब लिफ्ट 9वीं मंजिल पर पहुंची तो अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इसके साथ ही लिफ्ट अटक गई। केयर टेकर ने अलार्म बटन दबाया, लेकिन काम नहीं किया।

पत्नी की मौत से दुखी युवक ने की आत्महत्या

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● तीन दिन पूर्व हुई थी महिला की मौत

नोएडा में पहले पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। उसके तीन दिन बाद पति ने भी फांसी लगा ली। उसकी भी मौत हो गई। घटना 23 जुलाई देर रात की है। पुलिस को जानकारी मिली। मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि दोनों की तीन साल पहले लव मैरिज हुई थी।

दंपती की डेढ़ साल का बेटा है। वो परिजनों के पास है। इस मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। एसीपी -2 अरविंद कुमार ने बताया कि सेक्टर 22 में झोलू पंडित के मकान में 23 साल के कृष्ण कुमार अपनी पत्नी तारा कुमारी के साथ किराए पर रहता था। दोनों ने तीन साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों मूल रूप से हरदोई जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को तारा कुमारी ने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके दो दिन बाद ही कृष्ण कुमार ने फांसी लगा ली। कृष्ण कुमार तनाव में था और काफी दुखी था। 21 जुलाई को जब पत्नी तारा ने फांसी लगाई। उसके बाद उसे कृष्ण कुमार सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल लेकर गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तारा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की जानकारी दी। इसके दो दिन बाद ही कृष्ण कुमार ने फांसी लगा ली। वो सेक्टर-22 में ही किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि दंपती के एक डेढ़ साल का बेटा है। 3 दिन में इस बच्चे के सिर से मां और बाप का साया उठ गया। घटना के बाद से दोनों के परिजन बच्चे को गोद में लेकर रो रहे हैं। परिजनों का कहना है कि दोनों को ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार बच्चे के बारे में भी सोचना था।

गाजियाबाद में रैपिड रेल पैसेंजर के लिए होगा म्यूजिकल प्रोग्राम

गाजियाबाद। गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन के यात्रियों का सफर अब और रोमांचक होगा। एनसीआरटीसी 26 जुलाई से नमो भारत अनप्लग्ड लाइव म्यूजिकल फ्राइडेज कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है।

इस कार्यक्रम में हर शुक्रवार की शाम आर्टिस्ट और म्यूजिकल बैंड्स अपनी लाइव परफॉर्मेंस देंगे। इस इवेंट का आयोजन गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट नंबर-4 के कॉनकोर्स लेवल पर अनपेड एरिया में किया जाएगा। पहला आयोजन 26 जुलाई को होगा।

म्यूजिक आर्टिस्ट, म्यूजिकल बैंड्स को उनका टेलेंट दिखाने के लिए प्लेटफार्म दिया जा रहा है। गाजियाबाद स्टेशन पर म्यूजिक की बानगी का यह सिलसिला हर शुक्रवार की शाम संगीत के दीवानों और संगीत के हुनरमनदों के नाम रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्टेशन परिसर में एक खास संगीतमय वातावरण तैयार होगा। जिससे स्टेशन में आने-जाने वाले सभी यात्रियों को इस मौके का मुफ्त लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा।

यात्रियों के मनोरंजन के लिए संगीत की दुनिया के उभरते सितारे रॉक, पॉप और फ्यूजन म्यूजिक जैसी विविध शैलियों की प्रस्तुतियों की पेशकश से दर्शकों का दिल लुभाएंगे। यूजिक फ्राइडेज़ में भाग लेने के लिए हुनरमंद सोलो आर्टिस्ट, म्यूजिक बैंड / म्यूजिक समूह चैनलों और ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **AVARNA GOENKA** having address at **20-A PRITHVIRAJ ROAD, NEW DELHI, DL, 110011, India**with **Kotak Mahindra Bank Ltd A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **AVARNA GOENKA** calling upon her to clear dues and to operate the locker has returned unserved and she is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **AVARNA GOENKA** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **PRAMOD JAIN** having address at **C-469 DEFENCE COLONY, NEW DELHI, DL, 110024, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **PRAMOD JAIN** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **PRAMOD JAIN** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Lockers Hired by **RAJ KUMAR JAIN** having address at **G-89 2ND FLOOR, SAKET, NEW DELHI, DL, 110017, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **RAJ KUMAR JAIN** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **RAJ KUMAR JAIN** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **AMITA KALRA** having address at **G-10-12 MALVIYA NAGAR, NEW DELHI, DL, 110017, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **AMITA KALRA** calling upon her to clear dues and to operate the locker has returned unserved and she is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **AMITA KALRA** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **KRISHNA SACHDEV** having address at **A-323 DEFENCE CLY, NEW DELHI, DL, 110024, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **KRISHNA SACHDEV** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **KRISHNA SACHDEV** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **POOJA MALHOTRA** having address at **A-453 DEFENCE CLY NEW DELHI, DL ,110024, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **POOJA MALHOTRA** calling upon her to clear dues and to operate the locker has returned unserved and she is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **POOJA MALHOTRA** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **BHHANU JAIN** having address at **C-469 DEFENCE COLONY, DELHI, DL, 110092, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **BHHANU JAIN** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **BHHANU JAIN** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **RAJESHWAR SINGH GILL** having address at **B-38 BASEMENT B BLOCK, DEFENCE COLONY, NEW DELHI, DL, 110024, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **RAJESHWAR SINGH GILL** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **RAJESHWAR SINGH GILL** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **SAURABH AGRAWAL** having address at **E 20 LAJPAT NAGAR 3 MOOCHAND, HOSPITAL, NEWDELHI, DL, 110024, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **SAURABH AGRAWAL** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **SAURABH AGRAWAL** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **JASPER SAHNI** having address at **MOLKOMSBACKEN 24 ,FARSTA, STOCKHOLM, 12333, Sweden** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **JASPER SAHNI** calling upon her to clear dues and to operate the locker has returned unserved and she is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **JASPER SAHNI** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **MAN MOHAN KAPOOR** having address at **DOOR NO 43 UDAY PARK AUGUST, KRANTI MARG ANDREWS GANJ, NEWDELHI, DL, 110049, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **MAN MOHAN KAPOOR** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **MAN MOHAN KAPOOR** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **VCA CAPITAL SERVICES PVT LTD** having address at **A-366 BASEMENT DEFENCE COLONY, NEWDELHI, DL, 110024, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **VCA CAPITAL SERVICES PVT LTD** calling upon it to clear dues and to operate the locker has returned unserved and it is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **VCA CAPITAL SERVICES PVT LTD** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **PRASHANT KUMAR** having address at **W-21 F F HUDCO PLACE ANDREWJ, GANJ, NEW DELHI, DL, 110049, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **PRASHANT KUMAR** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **PRASHANT KUMAR** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **VIKRAM KUKREJA** having address at **H NO 1627 SECTOR 18-D, CHANDIGARH, CH, 160018, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **VIKRAM KUKREJA** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **VIKRAM KUKREJA** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Geetanjali Dagar D/o Late Shri I.S. Dagar R/o C-2/2523 First Floor, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 is the sole owner-in-possession of DDA Flat No. 2523, SFS Cat-|||, First Floor, Sector C, Pocket 2, Vasant Kunj New Delhi-110070 along with scooter garage by virtue of Gift Deed executed by Sh. Baljit Singh S/o Late Sh. Zile Singh, registered with the Sub-Registrar IX, New Delhi, vide Document No. 8707 in Book No. 1 Vol No. 7235 on 02.08.2013.
The original documents i.e. Allocation Letter, Fifth and Final Demand Letter, DDA Possession Letter, Possession Slip, NOC for Water and Electricity, Conveyance Deed, General Power of Attorney, Agreement to Sell & Receipt, Gift Deed etc has been lost/ misplaced. An FIR of this has been lodged in Police Station Crime Branch, Delhi vide LR No. 1445770/2024 dated 14.02.2024. Any person (s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents, may write/ contact me at 8826546380 within a period of 14 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to me on WhatsApp at 8826546380.

Sd/-
Geetanjali Dagar

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **TEK CHAND** having address at **T-498-2 KHAIRPUR VILLAGE KOTLA, MUBARAKPUR, NEW DELHI, DL, 110003, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **TEK CHAND** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **TEK CHAND** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

3 Lockers Hired by **IREO PRIVATE LIMITED** having address at **IREO CAMPUS SECTOR 59, NEAR BEHRAMPUR, GURGAON, HA, 122101, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **IREO PRIVATE LIMITED** calling upon it to clear dues and to operate the locker has returned unserved and it is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **IREO PRIVATE LIMITED** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **KUNAL KHULLAR** having address at **H NO 877 SECTOR A POCKET B C, VASANT KUNT, NEW DELHI, DL, 110070, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **KUNAL KHULLAR** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **KUNAL KHULLAR** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **RAKESH KUMAR GUJRAL** having address at **107 MEHER CHAND MARKET LODHI, COLONY, NEWDELHI, DL, 110003, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **RAKESH KUMAR GUJRAL** calling upon him to clear dues and to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **RAKESH KUMAR GUJRAL** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **SMRITI MALHOTRA NANDA** having address at **B 53 DEFENCE COLONY, NEW DELHI, DL, 110024, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **SMRITI MALHOTRA NANDA** calling upon her to clear dues and to operate the locker has returned unserved and she is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **SMRITI MALHOTRA NANDA** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker Hired by **NEERA SRIVASTAVA** having address at **FLAT NO F-29 8TH FLOOR, HYDERABAD ESTATE, NEPEANSEA ROAD, MUMBAI, MH,400006, India** with **Kotak Mahindra Bank Ltd – A - 266 BHISHM PITAMAH MARG DEFENCE COLONY DELHI – 110024** remains un-operated.

All the 3 letters earlier sent to **NEERA SRIVASTAVA** calling upon her to clear dues and to operate the locker has returned unserved and she is not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by **NEERA SRIVASTAVA** within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on **October 23, 2024** at around **12p.m.**

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that We (1) Mohan Lal, (2) Baldev Raj, (3) Anil Kumar, (4) Ashok Kumar, (5) Ms. Suman, and (6) Ms. Seema, are filing application in L&DO for substitution/ mutation of the Property No. 49, Block-D, Old Double Storey, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024 in the name of (1) Mohan Lal, (2) Baldev Raj, (3) Anil Kumar, (4) Ashok Kumar, (5) Ms. Suman, and (6) Ms. Seema, on the grounds of being the only legal heirs of our deceased mother Late Smt. Dharam Devi. If there are any objections/ claims from the general public on this application, the same shall be communicated to L&DO with supporting documents through registered post or by visiting L&DO at Nirman Bhawan, New Delhi or through an email at ldo@nic.in, within 30 days of publication of this notice.
Name : Mohan Lal
Address: D-2, Old Double Storey, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024
Phone : 9811016897

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित करना है कि आवासीय भूखण्ड संख्या–2, ब्लॉक–ए, सैक्टर–30 नोएडा (उ0प्र0) जिसकी मूल आवटी श्रीमती कुसुम अग्रवाल पत्नी श्री एस. एम. अग्रवाल निवासी–15, बनारसी दास स्टेट, लखनऊ रोड, दिल्ली–07, जिनके द्वारा श्री ओम प्रकाश रकवाल पुत्र श्री राम राखा निवासी ए–2, सैक्टर–30, नोएडा (उ0प्र0) के पक्ष में जी.पी.ए. पंजीकृत करायी गयी थी जो उप निबन्धक कार्यालय सब डिविजन, दिल्ली, में दिनांक 17.03.1994 को पंजीकृत है। तथा विक्रय संविदा पंजीकृत नही है।
अतः अब उपरोक्त आवासीय भूखण्ड संख्या–2, ब्लॉक–ए, सैक्टर–30 नोएडा का अंतरण जीपीए के आधार पर श्री दीपक डढ्वाल पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह डढ्वाल, एवं कवंर बुद्धिश्वर सिंह पुत्र श्री दिगम्बर सिंह, एवं श्रीमती मीरा रकवाल पत्नी श्री ओम प्रकाश रकवाल, निवासीगण ए–2, सैक्टर–30, नोएडा (उ0प्र0) के पक्ष में अंतरण होने के लिए प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति है, तो कृपया अपनी आपत्ति साक्ष्य सहित नौएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल कर दें। **श्री ओम प्रकाश रकवाल**

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the Public Notice at large, that i Himanshu Agarwal is Purchasing the property from Notarized GPA dated 12/01/2012, through these owners name is Mrs. Anita Sharma executed to, Ms. Manisha Rathi (25% share), Praveen Rathi (15%. Share) Mr. Harsh Sejwal (12.5%), share, Mr. Sandeep Dahiya (12.5%) Mr. Kamal Goel (12.5% Share), Mr. Gaurav Goel (12.5%) and Joginder Singh Tokas (10% Share), they are the owner from Conveyance deed (PM-udan) dated 17/01/24 dated by DDA on behalf of all POI (As Authority). I am Purchase uperground Floor (RHS) House No- 23/2 Area 200 sqyds out of Khasra No 0/113/0, situated at Rajpur Khurd Ext (South). I am going to given the News Publication If any Person having any type of claim/night / right / title interest over the said property may inform in writing within free from all 7 days from today. Said Property is free from all type of Encumbrance lien etc.

Basukee Nath Jha (Advocate)
Plot No 714, A/A, A Block Inder Enclave
Ph-2, Kirari Suleman Nagar, ND-86

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024

बारिश से भरा पानी, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम

मौसम विभाग ने 28 तक बारिश जारी रहने की जताई संभावना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में बुधवार को सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है लेकिन बारिश से सड़कों पर जलभराव से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी जमा होने से यातायात जाम हो गया जिसके चलते जगह-जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बृहस्तपतिवार तक एलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ राजधानी में 28 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग देश में मौसम संबंधी अलर्ट जारी करने के लिए चार रंगों का उपयोग करता है। ये अलर्ट हैं ग्रीन (किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं), एलो (नजर रखें और निगरानी करते रहें), ऑरेंज (कार्रवाई के लिए तैयार रहें) और रेड (कार्रवाई सहायता की जरूरत है)। यलो अलर्ट का मतलब छह से 11 सेमी के बीच भारी बारिश है। रेड अलर्ट 24 घंटों में 20 सेमी से अधिक, भारी से अत्यधिक भारी बारिश को इंगित करता है, जबकि आरेंज अलर्ट का मतलब छह से 20 सेमी तक बहुत भारी बारिश है।

यातायात पुलिस ने जलभराव से प्रभावित सड़कों के बारे में यात्रियों को परामर्श और अलर्ट जारी कर वाहना चालकों को तदनुसार अपनी यात्रा तय करने के लिए कहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के सबसे पुराने श्मशान घाट निगमबोध घाट पर जलभराव के कारण यातायात में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने बताया कि रानी बाग स्थित हरियाणा मैत्री भवन में बरगद का एक विशाल पेड़ उखड़ जाने से इलाके में यातायात जाम हो गया। मूसलाधार बारिश से उत्तरी दिल्ली के जखीरा अंडरपास में पानी भर गया जिसमें एक ट्रक फंस गया है। अंडरपास में भारी जलभराव होने से ट्रैफिक को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने निगम बोध घाट पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर परामर्श जारी लोगों से वैकल्पिक मार्ग पर चलने की सलाह दी।

अंडरपास में जलभराव के चलते वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारिश संग बच्चों की मस्ती। सभी फोटो: रंजन डिमरी

आईएसबीटी पर वाहनों की कतारें

इन इलाकों में लगा जाम

बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सुल्तापुरी का अंडरपास बरसात के बाद जलमग्न हो गया। जिसके बाद लोगों को आने-जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अशोक पार्क एक्सटेंशन, ईस्ट पंजाबी बाग, पंजाबी बाग, वेस्ट पटेल नगर, लोक विहार, पीतमपुरा, कीर्ति नगर, सेक्टर-24 पूर्वी पीतमपुरा, ओखला औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम विहार, सरोजनी नगर, शास्त्री नगर, करम पुरा, वेस्ट पंजाबी बाग और सोनिया विहार में भी जलभराव से लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

हवा और बारिश से रोहिणी सेक्टर, 16, हरियाणा मैत्री भवन पीतमपुरा, वेस्ट पटेल नगर, यमुना विहार, शाहदरा, रोहिणी सेक्टर-7, निमड़ी कालोनी और अशोक विहार में पेड़ गिरने की शिकायत मिली थी। जिससे वाहनों को आने-जाने में पेरशानी का सामना करना पड़ा।

8 आईएएस अफसरों का तबादला चंचल यादव बनीं गृह सचिव

- उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में कार्यरत अधिकारियों का किया ट्रांसफर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में तैनात आठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। आईएएस चंचल यादव को गृह सचिव के पद पर तैनात किया है।

खास बात है कि इन आठ अधिकारियों में से छह आईएएस अधिकारी वे हैं जो दिल्ली सरकार में तबादला होकर तो आ गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक किसी विभाग में नियुक्ति नहीं मिली थी। दिल्ली सरकार में 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनबरसु को लोक निर्माण विभाग में प्रधान सचिव के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड में सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निखिल कुमार भूमि एवं संपदा विभाग में सचिव पद पर तैनात होंगे। इसी तरह चंचल यादव गृह सचिव की जिम्मेदारी संभालेगी। 2010 बैच की आरती लाल शर्मा की दिल्ली विकास प्राधिकरण में पोस्टिंग हुई है। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र यादव को एमसीडी में अतिरिक्त एडिशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रवि झा नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर की भूमिका निभाएंगे। दानिक्स अधिकारी मराठे ओंकार गोपाल की एमसीडी में तैनाती की गई है।

इसके अलावा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे कृष्ण मोहन उप्पू जो 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह एक्साइज कमिश्नर के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें इससे मुक्त कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी

नई दिल्ली। दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार नए पीयूसी जांच केंद्र स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थानों को चिन्हित कर रही है। इस सिलसिले में परिवहन विभाग ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) से अपनी साइटों पर नए पीयूसी जांच केंद्र खोलने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग ने हाल ही में पाया कि पेट्रोल पंपों पर कई पीयूसी जांच केंद्र काम नहीं कर रहे थे जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या में वृद्धि करके हम वाहनों के प्रदूषण जाँच को आसान बनाना चाह रहे हैं। हम इस प्रयास में डीएमआरसी और आईजीएल के सहयोग की सराहना करते हैं। वर्तमान में, दिल्ली में 900 से अधिक पीयूसी जांच केंद्र हैं, जिनमें 700 से अधिक पेट्रोल पंपों पर स्थित हैं।

कश्मीरी गेट पर बना देश का सबसे बड़ा शिविर, रूक सकेंगे 20 हजार कांवड़िये

- राजस्व मंत्री आतिशी ने तैयारियों का लिया जायजा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कश्मीरी गेट स्थित कांवड़ शिविर का दौरा करतीं मंत्री आतिशी।

केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि कश्मीरी गेट पर बना कांवड़ शिविर देश में सबसे बड़ा शिविरों में से एक है। सभी सुविधाओं से लैस से यहाँ पर 20,000 कावंड़ियों के रुकने का इंतजाम किया गया है। शिविर में वाटर प्रूफ टेंट, फर्नीचर, पानी, चिकित्सा समेत अन्य जरुरी सुविधाएँ मौजूद हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा का भी ख्यास ध्यान रखा जाएगा। राजस्व मंत्री आतिशी ने बुधवार को कश्मीरी गेट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क के कांवड़ शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारीयों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली सरकार के सभी शिविरों में उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सुनिश्चित करें हर जरुरी कदम।

केजरीवाल सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए पूरी दिल्ली में 185 कांवड़ शिविर लगा रही है। कश्मीरी गेट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में महिला-पुरुष कांवड़ियों के विश्राम के लिए अलग-अलग हॉल व कांवड़ियों के प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल भी तैयार किया गया है। निरीक्षण के दौरान आतिशी ने अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि, कांवड़ शिविरों में कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए सभी जरुरी सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

सावन के पवित्र महीने में शिवभक्तों की सेवा करना पुण्य और आस्था का काम है। इस दिशा में कांवड़ियों को तमाम सुविधाएँ मुहैया कर केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आतिशी ने कहा कि, पिछले 9 सालों से सावन के पवित्र महीने में केजरीवाल सरकार कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए शिविर लगाती है। इस साल भी 185 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे है जहाँ कांवड़ियों के लिए तमाम सुविधाएँ मौजूद रहेंगी। कांवड़ियों के कांवड़ रखने के लिए विशेष स्टैंड मुहैया करवाए जाते है। साथ ही हर शिविर में मेडिकल सुविधाएँ होती है। इस साल भी सभी शिविरों में चौबीस घंटे मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे ताकि लंबी दूरी तय कर आ रहे कांवड़ियों का जरुरत पड़ने पर तुरंत उपचार दिया जा सकें और कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए स्थानीय डिस्पेंसरियों को शिविरों से जोड़ा गया है। किसी भी आपात स्थिति के लिए कैट्स एंबुलेंस को जोड़ा गया है। अस्पतालों को कांवड़िये के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व मंत्री ने अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि, कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन अलर्ट पर रहे ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े साथ ही शिविर में कांवड़ियों को हर जरुरी सुविधाएँ मिले।

एमए उर्दू के छात्र को पढ़ाये जा सकते हैं कबीर के दोहे

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद अगर पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव को मंजूरी दे देती है तो विश्वविद्यालय में उर्दू विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी आध्यात्मिक संत कबीर दास के दोहे पढ़ते नजर आएंगे।

अधिकारियों ने कहा कि कला संकाय की ओर से प्रस्तावित संशोधन को यदि मंजूरी मिलती है तो एमए उर्दू के पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को कबीर वाणी के दोहे पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य से कला संकाय ने एम.ए. उर्दू के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में दो पाठ्यपुस्तकें शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

छठे दिल्ली वित्त आयोग का नहीं किया गठन: विजेंद्र

- उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं होने पर दिल्ली सरकार के संविधान उल्लंघन के खिलाफ उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। गुप्ता ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को एलजी पत्र भी लिखा है। भाजपा नेता का दावा है कि अप्रैल 2021 से लंबित होने के बावजूद छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है।

पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशें केवल मार्च 2021 तक लागू थीं। तब से, दिल्ली सरकार द्वारा कोई नई सिफारिशें जारी नहीं की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, सरकार अभी भी नगर निगम को पांचवें डीएफसी की पुरानी सिफारिशों के आधार पर धन प्रदान कर रही है। जो असंवैधानिक है और दिल्ली वालों के प्रति नाइंसाफी है। पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर फंड दिए जाने की प्रथा न केवल असंवैधानिक है अपितु अपर्याप्त भी है। क्योंकि पाँचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश 3 विभाजित नगर निगमों के लिये थी जो वर्तमान एकीकृत दिल्ली नगर निगम की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न है।

गुप्ता ने कहा कि यह अराजकता की स्थिति आम आदमी पार्टी सरकार की अक्षमता को दर्शाती है। पहले, आप सरकार ने दिल्ली नगर निगम को वित्तीय कुप्रबंधन के लिए दोषी ठहराया और इसे वित्तीय संकट का कारण बताया। हाल ही में, केजरीवाल सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के केंद्र सरकार पर दोषारोपण किया, जबकि केंद्र सरकार का नगर निगमों से सीधा लेन देन का कोई प्रावधान ही नहीं है।

दिल्ली सरकार ने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था लेकिन उन्हें लागू नहीं किया और तीसरे डीएफसी की सिफारिश के आधार पर धन आवंटन जारी रखा। यह भी आप सरकार द्वारा किया गया एक संवैधानिक उल्लंघन था।

जिम मालिक की हत्या के मामले में दो महिला समेत चार गिरफ्तार

- मुख्य आरोपी फरार, हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश का शक

पायनियर समचार सेवा। नई दिल्ली

भजनपुरा इलाके में जिम मालिक की चाकू घोंपकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार मामले में अन्य आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

पुलिस के अनुसार, जिम और टूर एंड ट्रैवल का कारोबार करने वाले सुमित चौधरी उर्फ प्रेम पर 10 जुलाई को गामड़ी एक्सटेंशन स्थित उनके घर के बाहर हमला किया गया था। उन पर कम से कम 17 बार चाकू से वार किया गया, जिससे अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्वी) जॉय टिर्की ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को इस मामले में दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टिर्की ने बताया कि आरोपियों में से एक की पहचान करतार सिंह (33) के रूप में हुई है जिस पर पहले से ही हत्या का एक मामला दर्ज है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक अन्य आरोपी की पहचान हुसैन अली (20) के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि भागने में आरोपियों की मदद करने वाली दो महिलाओं की पहचान शायना (36) और आशु (38) के रूप में हुई है। अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपी भजनपुरा निवासी हैं। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश होने का संदेह है, हालांकि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है।

अधिकारी ने बताया कि सलमान उर्फ सल्लू (21) को पकड़ने के प्रयास जारी हैं, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसने कथित तौर पर चौधरी पर चाकू से हमला किया था। उन्होंने बताया कि हमले में जान गंवाने वाले जिम मालिक पर भी हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम सहित तीन आपराधिक मामले दर्ज थे।

संक्षिप्त समाचार

उमर खालिद की जमानत याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को पुलिस का रुख जानना चाहा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की है। इसके साथ ही मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम सहित अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले सुनवाई अदालत के हालिया आदेश की आलोचना की है।

बाइक को टक्कर मारकर फरार होने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने टक्कर मारकर फरार होने के एक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान धीरज तलवार के रूप में हुई है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) रोहित मीणा ने बताया, 22 जुलाई को पीसीआर को राष्ट्रीय राजमार्ग-आठ पर पिलर संख्या 163 के पास एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना देने वाले व्यक्ति ने हमें बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार चार लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली छावनी थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और सड़क पर खून पड़ा हुआ देखा। उपायुक्त ने बताया, घायलों को पहले ही एंबुलेंस से एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था। नसरीन (35) और उसके बेटे अजीम (13) को मृत घोषित कर दिया गया। नसरीन के पति महबूब (37) और बेटी आयशा (छह) का इलाज जारी है।

कैलाश गहलोत ने आंगनवाड़ी केंद्र का किया दौरा

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोपाल नगर में आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया। इस दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना, जिसे पहले आईसीडीएस योजना के रूप में जाना जाता था, के तहत विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं सहित सभी मां और बच्चों को आवश्यक सुविधाएं एवं पोषक आहार मिल सके। जमीनी स्तर पर योजनाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने में लाभार्थियों का फीडबैक अमूल्य है

हुमायूं मकबरे में बना देश का पहला भूमिगत संग्रहालय

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- उद्घाटन 29 जुलाई को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे
- इसका डिजाइन मध्ययुगीन बावली या पानी की पारंपरिक टंकियों से प्रेरित है

भाजपा अक्सर मुगलों पर हमलावर रहती है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक धरोहर हुमायूं के मकबरे में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का निर्माण कराया है। इस संग्रहालय का डिजाइन मुगलकालीन शिल्प कौशल के साथ-साथ आधुनिक 21वीं सदी की वास्तुकला से मेल खाता है। निजामुद्दीन इलाके में स्थित 16वीं सदी का, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है।

इस संग्रहालय का उद्घाटन 29 जुलाई को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। इसका डिजाइन मध्ययुगीन बावली या पानी की पारंपरिक टंकियों से प्रेरित है। संयोग से, इसका उद्घाटन ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक हो रही है। भारत पहली बार यूनेस्को के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक प्रतिष्ठित आगा खां परिवार का एक सदस्य भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित हो सकता है। आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से इस संग्रहालय का निर्माण कर रहा है। एकेटीसी के अनुसार, संग्रहालय का निर्माण विश्व धरोहर परिसर के प्रवेश क्षेत्र में किया गया है और यह निजामुद्दीन, सुंदर नर्सरी और 16वीं शताब्दी के मकबरे के तीन स्थलों के बीच एक पुल के रूप में काम करेगा। यह संग्रहालय पिछली सात शताब्दियों में निजामुद्दीन क्षेत्र की विरासत को प्रदर्शित करेगा। एकेटीसी के एक शीर्ष अधिकारी ने पहले बताया था कि संग्रहालय में गैलरी, एक पुस्तकालय, सेमिनार हॉल, एक शिल्प केंद्र और एक जलपानगृह सहित अन्य चीजें शामिल होंगी। उन्होंने कहा था कि मुगल स्मारक (हुमायूं का मकबरा) का अंतिम हिस्सा, जो वर्ष 2014 के तूफान में ढह गया था, इसका केंद्र होगा। उत्तर भारत की मध्ययुगीन बावलियों (पानी की टंकियों) से प्रेरित, 10,000 वर्ग मीटर में निर्मित यह भूमिगत संग्रहालय अपने डिजाइन में मुगलकालीन शिल्प कौशल के साथ आधुनिक 21वीं सदी की वास्तुकला से मेल खाता है। मकबरे में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय के निर्माण पर काम अप्रैल 2015 में शुरू हुआ था।

करंट से मौत: सीसीटीवी की जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। पटेल नगर इलाके में करंट लगने से सिविल सेवा परीक्षा के एक अभ्यर्थी की मौत के बाद घटनाक्रम का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बिजली वितरण कंपनियों से संपर्क कर रही है।

गाजीपुर निवासी नीलेश राय की मौत के दो दिन बाद, टाटा पावर डिस्कॉम (विद्युत वितरण कंपनी) के एक अधिकारी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि एक ग्राहक के क्षतिग्रस्त मोटर वायरिंग में करंट आने के कारण यह हादसा हुआ। यह मोटर लोहे के गेट के संपर्क में आ गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बताया कि राय अपने पीजी आवास की ओर लौट रहे थे, तभी सड़क पर उनका पैर फिसल गया उन्होंने लोहे के गेट को पकड़ लिया, जिससे उन्हें करंट लग गया।

गुरुग्राम की 4 विधानसभाओं में बने 234 नए बूथ

जिले में मतदान केंद्रों के रेशनालाइजेशन की प्रक्रिया पूरी, डीसी ने आपत्तियां दर्ज कराने को कहा

● विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए बढ़ाई गई बूथों की संख्या

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम स्थित लघु सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते डीसी निशांत कुमार यादव।

जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1400 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों के साथ कुल 234 नए सहायक बूथ बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए बूथों की संख्या बढ़ाई गई।

डीसी निशांत कुमार यादव बुधवार को लघु सचिवालय में मान्य प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। डीसी निशांत कुमार यादव ने बैठक में बताया कि सहायक बूथ बनाने की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वे मुख्य बूथ से दो किलोमीटर की ज्यादा दूरी पर स्थित ना हो। साथ ही उक्त स्थान पर आयोग की निर्धारित नियमावली के तहत सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध रहे। उन्होंने विधानसभावार सहायक मतदान केंद्रों की जानकारी देते हुए बताया कि पटौदी विधानसभा में 12, बादशाहपुर विधानसभा में 90, गुड़गांव विधानसभा में 84 व सोहना विधानसभा में 48 बूथ बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नए सहायक बूथ बनने के बाद अब पटौदी विधानसभा में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 259, बादशाहपुर में 518, गुड़गांव में 435 व सोहना में 292 हो गई है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त पूरी प्रक्रिया में किसी भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को कोई आपत्ति है तो संबंधित विधानसभा के एसडीएम के पास अपनी आपत्तियां व सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

डीसी ने कहा कि जिला में पुनरीक्षण अभियान के तहत 25 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य मतदाता सूची के संशोधन लिए दावे व आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं। बैठक में डीसी ने सभी राजनीतिक दलों को आपत्ति और सुझाव को लेकर ससमय प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर जांच एवं निस्तारण किया जा सके।

बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम विश्वजीत चौधरी, सोहना के एसडीएम सोनू भट्ट, गुड़गांव के एसडीएम रविन्द्र कुमार, चुनाव तहसीलदार राजेन्द्र सिंह, संत लाल इत्यादि मौजूद रहे।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई : अतिरिक्त उपायुक्त

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. आनंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से ब्लैक स्पॉट, जहां दुर्घटना होने का अंदेशा हो, की पहचान करके उन बिंदुओं को ठीक करने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने बुधवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

अतिरिक्त उपायुक्त ने एजेंडे में शामिल 15 विषयों पर क्रमवार विस्तारपूर्वक चर्चा करके फीडबैक ली और संबंधित अधिकारियों को समस्या निराकरण के निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सबसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभी संबंधित विभाग इस विषय पर गंभीरता से कार्य करें। जिला में जहां भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उन सबको चिन्हित करके सड़क सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए जाएं ताकि होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रोडवेज बस स्टैण्ड के पास पुल पर सवारियां उतारने एवं बिठाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये एवं नो पार्किंग जोन के बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करें।

स्कूलों में छात्रों को साइबर अपराध के प्रति करें जागरूक : विकास अरोड़ा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

स्कूलों में बच्चों व स्टाफ को साइबर अपराधों के प्रति जागरुकता से ठगी के मामलों में कमी लायी जा सकती है। यह बात पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा गुरुग्राम के विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल्स/फैकेल्टी सदस्यों के साथ मीटिंग में कही।

उन्होंने कहा कि मादक व नशीले पदार्थों का सेवन करना घातक है। हमें विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के सेवन करने के दुष्प्रभाव/ दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराकर उन्हें नशीले/मादक पदार्थों के खिलाफ खड़ा करना है, ताकि समाज नशा मुक्त बने। इस मीटिंग के दौरान विद्यालयों की परिवहन प्रणाली को सुरक्षित करने, उनकी सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बच्चों मानसिक तथा शारीरिक शोषण ना हो पाए इसके लिए विशेष कदम उठाने होंगे, जिसके लिए स्कूल के स्टॉफ को ट्रेनिंग दें।

आईटीआई में 26 को लगेगा रोजगार मेला

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के आदेश अनुसार हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय आईटीआई में रोजगार मेलों व अप्रेंटिस मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फ़रीदाबाद में आगामी 26 जुलाई शुक्रवार को अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मेले में फरीदाबाद व पलवल के औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योग भाग ले रहे हैं। विभिन्न उद्योगों ने अपनी मांग आईटीआई फरीदाबाद की शिक्षुता एवं प्लेसमेंट सेल को दी है।

आईटीआई फरीदाबाद के प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया है कि इस मांग में उनको अधिकतर आईटीआई पास फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इत्यादि ट्रेडों के अभ्यर्थियों की रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के लिए जरूरत है। जिन उद्यो गों ने अपनी डिमांड आईटीआई फरीदाबाद को भेजी है, उनमें मुख्यत: बीसीएच इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, रेवा ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, हेक्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ्रीक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिदवाल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्राउन क्लोजर प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, राणे एनएसके स्टीयरिंग, साटा विकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्णकार एंटरप्राइजेज, यूनो मिंडा लिमिटेड, न्यू क्राफ्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, ताज फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड, एवॉन ट्यूब टेक प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि शामिल हैं।

पचंगाव से फर्रूखनगर टावर लाइन का कार्य होगा

गुरुग्राम। गुरुग्राम 25 जुलाई को एचवीपीएन द्वारा 220 केवी पचंगाव पावर हाउस के पीछे नई टावर लाईन पचंगाव से फर्रूखनगर का कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण 33 केवी पचंगाव पावर हाउस से चलने वाले सभी 11 केवी फिडर की सप्लाई सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बन्द रहेगी। इस दौरान 33 केवी पचंगाव पावर हाउस से चलने वाले सभी गांव कुकडोला, फाजलवास, ग्वालियर, खेड़ी, बाघनकी, चादंला डुगंरवास, पुखरपुर, मोकलवास, राजा की ढाणी व इस एरिया की अन्य ढाणियों की सप्लाई बाधित रहेंगी। दोपहर 12 बजे के बाद बिजली व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी।

'हिट-एंड-रन में मौत पर परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजा'

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

● गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपए की दी जाती है सहायता राशि

जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि हिट-एंड-रन दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को हिट-एंड-रन दुर्घटना मुआवजा स्कीम-2022 के तहत दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए पीड़ित परिवार को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा करवानी आवश्यक होती है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि हिट एंड रन मामले में मृत्यु हो जाने पर उसके पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर पीड़ित को इलाज के लिए 50 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। हिट एंड रन में सड़क हादसे के पीड़ितों में ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें गाड़ी चालक का पता नहीं चल पाता है। ऐसे मामलों में किसी की मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी पीड़ित को इलाज के लिए 50 हजार रुपए दिए जाते हैं।

सरकारी स्कूल से कब्जा हटवाने के निर्देश

● समाधान शिविर में रखी गई 69 शिकायतें, 33 का निपटारा किया

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गांव हरिनगर डूमा में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने के लिए डीसी निशांत कुमार यादव ने निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम पटौदी को कहा कि स्कूल की जमीन पर जितने नाजायज कब्जे किए हुए हैं, उन सबको तत्काल हटवाया जाए।

डीसी बुधवार को समाधान शिविर में आमजन की शिकायतों को सुन रहे थे। गांव हरिनगर डूमा के कुछ लोगों ने सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायत की थी, जिस पर डीसी ने ये निर्देश दिए। शिविर में अशोक विहार निवासी प्रकाश चंद ने शिकायत दी कि तीन दिन पहले वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीताराम मंदिर में जा रहा था। रास्ते में सड़क पर खड़े कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसका चालान काट दिया तथा स्कूटी भी जब्त कर ली। वह मायूस होकर अपने घर पर आ गया। डीसी ने कहा कि इस मामले को कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखवाया जाए। शिविर में 60 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें से 32 का मौके पर ही निपटारा किया गया। उपमंडल स्तर पर 9 शिकायतें आई थीं, जिनमें से एक का मौके पर निवारण किया गया। आज कुल 69 शिकायतों में से 33 का निपटारा कर दिया गया। शेष 36 शिकायतों में तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए।

समाधान शिविर में 22 शिकायतों में से 19 का निस्तारण

पलवल। जिला उपायुक्त नेहा सिंह के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर विभिन्न विभागों से संबंधित 22 शिकायतें आई। इन शिकायतों में से संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा 19 का मौके पर ही समाधान करवा दिया गया। इनके अलावा लंबित रही शिकायतों का भी जल्द निवारण का आश्वासन दिया गया। जिला स्तर पर लगाए गए समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त डा. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकतर का मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा समाधान करवा दिया। इन मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला व उपमंडल स्तर पर हर कार्यदिवस पर सुबह 9 से 11 बजे तक लघु सचिवालय में समाधान शिविर लगाएं जा रहे हैं।

मासूम से रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा

● स्पेशल पोस्को कोर्ट गुरुग्राम ने सुनाई सजा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

नाबालिग बच्ची से रेप के तीन साल पुराने एक केस में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपये की राशि देने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2021 को मानेसर थाना क्षेत्र में कंपनी में लेबर का काम करने वाले परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप किया था। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। फरिश्ते ग्रुप संस्था से एडवोकेट डॉ. अंजू रावत नेगी, कुलभूषण भारद्वाज व पंकज वर्मा परिजनों से मिले। जांच अधिकारी पूनम हुड्डा ने दोषी के खिलाफ सूबूत जुटाए। गुरुग्राम की स्पेशल पोस्को अदालत में न्यायाधीश एके मेहता ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।

हाईवे पर बघौला में फिर लगा जाम, पुलिस के छूटे पसीने

दयाराम वशिष्ठ। फरीदाबाद

हाईवे एनएच 19 पर बघौला में निर्माणाधीन पुल के चलते लगने वाले जाम में बुधवार को कांवड़ियों को निकलवाने पहुंची पुलिस के पसीने छूट रहे। इस दौरान पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। कांवड़ियों के जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। उधर, दूसरी ओर पलवल एसपी आईपीएस चंद्र मोहन ने हाईवे के जाम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि वह तुरंत जाम का समाधान करें।

दरअसल, अभी हरिद्वार की ओर से गंगा का जल लेकर कांवड़ियों का पहुंचना शुरू नहीं हुआ है लेकिन बुधवार सुबह बघोला पुलिस चौकी को सूचना मिली कि एक डाक कावड़ पलवल की ओर जा रही है। इस सूचना के बाद चौकी इंचार्ज सुनील के नेतृत्व में पुलिसकर्मी हाईवे पर पहुंचे। उस समय करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात व्यवस्था सम्भलते हुए वाहनों को तेजी से आगे बढ़ने का इशारा करते हुए रवाना किया।

निर्माणाधीन पुल के ऊपर से जाएंगे कांवड़िये

जाम को लेकर गंभीर पलवल एसपी चंद्र मोहन ने कांवड़ियों को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। कर रही कंपनी के इंजीनियरों से हाईवे की मैन कैरिज वे पर बन चुके अंडर पास के उपर से रास्ता बनाने की बात कही, ताकि कावड़िया गंतव्य तक आसानी से जा सकें।

संक्षिप्त समाचार

हरियाणा जूनियर पुरुष फुटबॉल टीम असम के लिए रवाना

गुरुग्राम। हरियाणा फुटबाल एसोसिएशन द्वारा अंडर-17 आयु वर्ग में जूनियर ब्वॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर डा. बी.सी. रॉय ट्रॉफी 2024-25 असम के नागोन में होने वाली चैंपियनशिप के लिए हरियाणा की टीम रवाना हो गई। हरियाणा फुटबॉल संघ के प्रधान सूरज पाल अम्मू ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की एवं टीम को शुभकामनायें दी।

बाटा रेहड़ी पटरी वालो ने उद्योग मंत्री का पुतला फूंका

फरीदाबाद। बाटा चौक पर गैर कानूनी रूप से रेहड़ी पटरी की दुकानों को तुड़वाने बाटा तथा सर्विस रोड को सीमेंट ईट लगाकर व एक बड़ा लोहे का खोखा सीमेंट का चबूतरा बनाकर रखने आम रास्ते को बंद करने के खिलाफ बुधवार को दीनदयाल गौतम के नेतृत्व में रेहड़ी पटरी विकास संघ के लोगों ने बाटा चौक अंग्रेजी व देसी शराब के ठेके के सामने प्रर्दशन किया तथा उद्योगमंत्री मूलचन्द शर्मा का पुतला फूंका।

शूटिंग को लेकर सीएम से मिले विधायक और खिलाड़ी

फरीदाबाद। ओलंपियन शूटर सिंहराज अधाना ने विधायक राजेश नागर की उपस्थिति में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीएम को बताया कि खेल विभाग हरियाणा शूटिंग खेल की अनदेखी कर रहा है। जिस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। अधाना ने बताया कि हमारे बच्चों को पिछले 3 वर्षों से नगद इनाम नहीं दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को खेल आगे जारी रखने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बल्लभगढ़ में ग्राम न्यायालय के लिए छह पदों को मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में ग्राम न्यायालय को चालू करने के लिए छह पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से 4 मार्च, 2024 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में ग्राम न्यायालय को अधिसूचित किया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के अनुसार स्वीकृत पदों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, रीडर ग्रेड-2, अहलमद, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, चपरासी और एक अतिरिक्त चपरासी शामिल हैं, जिनका कुल मासिक वित्तीय भार तीन लाख 95 हजार 128 रुपये और वार्षिक लागत 47 लाख 41 हजार 536 रुपये है।

अवैध संबंध में युवक की हत्या करने वाले 2 गिरफ्तार

गुरुग्राम। अवैध संबंध के संदेह में युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम टीम, फिंगर प्रिंट टीम, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। मृतक के शव को पहचान के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। 21 जलाई 2024 को थाना खेड़ी दौला में एक सूचना गांव शिकोहपुर की पहाड़ी में एक व्यक्ति का शव पड़े होने के बारे में मिली। सूचना पाकर थाना खेड़ी दौला की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर एक व्यक्ति का शव पड़ा था, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। 23 जुलाई को मृतक के भाई ने मृतक की पहचान सनोज निवासी सिमरी जिला सहरसा उम्र-24 वर्ष के रूप में की। उसका भाई 6-7 महीने पहले ही गुरुग्राम में काम करने के लिए आया था।

तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

● एक अन्य रेप में काट चुका है 10 साल की सजा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सीआईए सोहना व महिला थाना पूर्व गुरुग्राम की टीमों ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 50 वर्षीय आरोपी इससे पहले पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के केस में 10 साल की सजा काट चुका है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का ईनाम रखा था।

26 अप्रैल 2024 को एक महिला ने महिला थाना पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीम को शिकायत में कहा था कि उसका पति एक ठेकेदार का पास काम करता है। ठेकेदार ने परिवार को रहने के लिए गांव रिठोज में कमरा दिया हुआ था। एक व्यक्ति ठेकेदार के यहां काम करने आया। वह 25-26 अप्रैल की रात को उनके कमरे की बाहर ही सोया था। रात को उनकी 3 साल की बेटी कमरे में नहीं थी और बाहर व्यक्ति भी नहीं था। अगले दिन सुबह बच्ची कमरे से थोड़ी दूरी पर बेहोशी की हालत में मिली। बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे।

होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करेगी संस्था

गुरुग्राम। समाज उत्थान न्यास संस्था द्वारा गत वर्षों की भांति इस बार भी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2024 में 10वीं और 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्र एवं छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए यह प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। जिसके लिए बुधवार को संस्था की मीटिंग जिला कार्यालय में की गयी।

संस्था के अध्यक्ष गगन दीप ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 25 अगस्त 2024 को अग्रवाल धर्मशाला सिविल लाइन गुरुग्राम में किया जाएगा। कार्यक्रम में कार्यों की रूप-रेखा बना ली गयी है।

खुशियां साथ मनानी चाहिए : बोधराज सीकरी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

समाजसेवी दलीप लूथरा के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते लोग।

दशहरा ग्राउंड न्यू कॉलोनी आरडब्ल्यूए के प्रधान दलीप लूथरा का जन्मदिन श्याम वाटिका न्यू कॉलोनी में शुभचिंतकों ने मनाया।

इस आयोजन में भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल यादव और भाजपा के प्रदेश संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ एवं पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्रधान बोधराज सीकरी ने शिरकत की। बोधराज सीकरी ने कहा कि हमें खुशियां मिल-जुलकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। समाजसेवी धर्मेन्द्र बजाज, रमेश कामरा, रमेश मुंजाल, द्वारका नाथ, मनमोहन सिंह, हरीश कुमार, नितिन मलिक भी आयोजन में उपस्थित हुए। बोधराज सीकरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान बलदेव राज गंभीर, गोविंद लाल आहूजा, डॉ. परमेश्वर अरोड़ा, सतपाल मनचंदा, पी.डी. भुरानी, राजकुमार नारंग, लक्ष्मण पाहुजा, देवेंद्र मलिक, मोहित गोगिया, राजेश चांदना, सरदार जगतार सिंह, देवेंद्र गोयल,चरणजीत कुकरेजा, सुशील चौहान, सुंदर लाल खटाना, ऋषि खन्ना, चुन्नीलाल, राजेश गिरधर, संजय मक्कड़, राजकुमार डुडेजा, गौरव डाबर मौजूद रहे।

गुरुग्राम विश्वविद्यालय में वॉल ऑफ हीरोज बना कारगिल शहीदों को किया नमन

● विजय दिवस समारोह का किया गया आयोजन, बलिदानियों के परिवारजनों को किया गया सम्मानित

संजय मेहरा। गुरुग्राम

गुरुग्राम विश्व विद्यालय में बनाई गई वॉल ऑफ हीरोज के साथ अतिथि।

गुरुग्राम विश्वविद्यालय एवं जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर सेक्टर-51 में कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर,कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में गुरुग्राम विवि के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार, मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम की पूर्व सांसद सुधा यादव, विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार और पूर्व सैन्य अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप तथा विशेषज्ञ वक्ता के रूप में मेजर जनरल अजय सेठ, कुलसचिव डॉ. राजीव सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यकम की शुरुआत में कारगिल युद्ध के दौरान वीरगति पाने वाले भारत के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बलिदानियों को नमन किया किया। इस दौरान कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में बनाए गए वॉल ऑफ हीरोज का भी अतिथियों द्वारा उद्घाटन किया गया। अतिथियों ने वीर बलिदानियों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया।

मुख्य वक्ता आशुतोष भटनागर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के बलिदान और वीरता की गाथा को जान सके। कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल में अपने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, वह अविस्मरणीय है। हरियाणा केंद्रीय विवि के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। मुख्य अतिथि सुधा यादव ने छात्रों को वीर सैनिकों के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही।

कैदियों के लिए दवा खरीद को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

प्रवक्ता ने बताया, रोहतक जेल में 34 करोड़ से मजबूत होगी सुरक्षा

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की जेलों के लिए 2.84 करोड़ रुपये की आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है।

सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की मांग हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (एचएमएससीएल) को भेजी जा रही है, जो ऐसी खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्रोत है। इस फैसले से सभी जेल कैदियों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना है, जिससे उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार को बरकरार रखा जा सके।

इस बीच सीएम ने रोहतक में 34.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल में 'एडवांसड फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन' स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्तावित सुरक्षा उपायों में अत्याधुनिक परिधि सुरक्षा प्रणालियां, उन्नत प्रवेश नियंत्रण तंत्र, व्यापक निगरानी प्रणालियां और कमांड एवं नियंत्रण केंद्र में एकीकृत अन्य उन्नत आईटी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इन संवर्द्धनों का उद्देश्य रोहतक उच्च सुरक्षा जेल में मजबूत और अभेद्य सुरक्षा वातावरण बनाना है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय 1 दिसंबर और 12 दिसंबर, 2023 को जेल विभाग और हरियाणा पुलिस आवास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हुई सिफारिशों के बाद लिया गया है। इन बैठकों में जिला जेल नूंह की तरह नवीनतम एवं आधुनिक सुरक्षा तकनीकी उपकरणों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। (फाइल फोटो)

भ्रष्टाचार में निकाय विभाग के तीन अधिकारी निलंबित

चंडीगढ़। स्थानीय निकायों से आ रही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सभी निकायों से ड्रेनेज व्यवस्था तथा विकास कार्यों को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट मांग ली है। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बुधवार को बताया कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रदेश भर से आ रही शिकायतों का रिव्यू किया गया है। आम नागरिकों के लिए एनडीसी की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी शहरों से ड्रेनेज व्यवस्था पर भी रिपोर्ट तलब की गई। कई निकायों में बरसात से पहले ड्रेनेज का काम पूरा हो चुका है कई जगह ड्रेनेज सफाई का काम अभी जारी है। जिलों से आने वाली रिपोर्ट का निदेशालय के स्तर पर रिव्यू करके अगले निर्देश दिए जाएंगे। जिन जिलों में पिछले साल बाढ़ आई थी उन जिलों में पहले के आधार पर ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार का काम करवाया गया है।

नॉन स्टॉप और फुल स्टॉप पर आमने-सामने हुए सैनी व हुड्डा

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

● पूर्व सीएम के दावों को नायब सैनी ने किया खारिज, बोले प्रदेश पर नहीं आपकी राजनीति पर लगा है फुल स्टॉप

एक तरफ हरियाणा सरकार ने इस बार चुनाव प्रचार अभियान को नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से शुरू किया है वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इसके जवाब में फुल स्टॉप का नारा दिए जाने के बाद प्रदेश में सियासी विवाद शुरू हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए सवालों पर बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब दिया।

हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव में इस बार नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से प्रचार अभियान चला रही है। जिसके माध्यम से सरकार पिछले साढ़े नौ साल की उपलब्धियां गिना रही है। दो दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर पलटवार करते हुए नॉन स्टॉप हरियाणा के मुकाबले फुल स्टॉप हरियाणा का नारा दिया था। जिसमें हुड्डा ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना कर मौजूदा सरकार को घेरा था। हरियाणा कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर अभियान चलाया हुआ था।

बुधवार को दोनों नेताओं के बीच यह विवाद और गहरा हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने एक्स पर कहा कि आज का हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है। फुल स्टॉप लगा है कांग्रेस द्वारा पोषित गुंडागर्दी और दबंगई पर।

प्रदेश के सभी विधानसभा हलकों का दौरा करेंगे सीएम व भाजपा अध्यक्ष

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

● पहले चरण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू, कार्यकर्ताओं की मांग पर होंगे रात्रि ठहराव कार्यक्रम

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री तथा प्रदेशाध्यक्ष के कार्यक्रमों को हाईकमान की स्वीकृति मिल चुकी है। जिसके बाद भाजपा अध्यक्ष इसी सप्ताह तो मुख्यमंत्री अगले सप्ताह से फील्ड में उतर रहे हैं। इससे पहले मंत्रियों तथा विधायकों के हलकों में प्रवास कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बैठक के बाद अब भाजपा के दोनो शीर्ष नेता फील्ड में दिखाई देंगे। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब बड़ौली कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष 28 जुलाई से हरियाणा के सभी जिलों का दौरा शुरू करेंगे। बड़ौली के चार दिन बाद 2 अगस्त से मुख्यमंत्री नायब सैनी का जिला प्रवास कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के यह कार्यक्रम अलग-अलग जिलों में होगे, ताकि कार्यकर्ताओं व स्थानीय नेताओं के साथ दो बार रूबरू हो सकें। इसके बाद दोनों नेता विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकों को संबोधित करते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारेंगे। यह दौरे अगस्त माह के भीतर पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद सितंबर माह में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा केंद्रीय नेताओं के हरियाणा दौरे होंगे।

मुख्यमंत्री व भाजपा अध्यक्ष के दौरे के दौरान संबंधित क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं से जहां स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी वहीं पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों का भी फीडबैक लिया जाएगा। जिन हलकों में इस समय भाजपा के विधायक हैं वहां से उनकी कार्यशैली को लेकर भी चर्चा की जाएगी। भाजपा इस चुनाव में कई विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है।

भाजपा सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों को निराश किया : आप

गुरुग्राम/कुरूक्षेत्र। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता की मौजूदगी में और लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता निशांत आनंद के नेतृत्व में कंपनियों के मालिक, बिजनेसमैन और एडवोकेट समेत सैकड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। डॉ. सुशील गुप्ता ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सचिव उमेश अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष मुकेश डागर और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना मौजूद रहे।

इस दौरान भसीन इंडस्ट्री के ऑनर कोमल भसीन, एंटरप्रेन्योर संजीव चोप ?ा, रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन गुरुग्राम और लंदन के ऑनर कपिल गुलाटी, सदर बाजार व्यापर मंडल के वाइस प्रेसिडेंट मंसूर, स्टेट सेसा फुटबाल क्लब प्लेयर गिरीश पर्ब, लेंसकार्ट के मैनेजर जितिन, बॉलीवुड डायरेक्टर स्वर्गीय सतीश कौशिक के भतीजे सिद्धार्थ वत्स, बीजेपी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जगमोहन, ऐधा रियल टेक कंपनी के ऑनर पीयूष सालदी, ईवाई कंपनी के डायरेक्टर अमन, बीपी टूल कंपनी के ऑनर मनोज साहु, शिवम रावत, राहुल साहु, रोहित शर्मा, साक्षी, तान्या,रिया, रीतिक, बाने सिंह सिरोहिया, भोरे लाल, मोहित भाटिया, रोहित शर्मा, सुंदर अवाना, सोनू चोपड़ा, बिजनेसमैन नरेंद्र और अवनीत आम आदमी पार्टी में शामिल हुए।

सार्वजनिक सूचना

जनता को यह सूचित किया जाता है की नीचे उल्लिखित दस्तावेज खो गया है:

• मूल रजिस्ट्री: चौहान रेसिडेन्सी में सेक्टर 45, गांव सदरपुर के दो दुकानों के मूल रजिस्ट्री से जुड़े कागजात

22/07/2024 को नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से गांधी दर्शन राजघाट की ओर जाते समय ऑटो रिक्षा में यह कागजात खो गए है. शिकायतकर्ता अंजली टिक्कू (एस/डी/डब्ल्यू/ओ अनिल कुमार चोपडा, SO No: 430/2014 दिल्ली पुलिस) अपनी बैग ऑटो में भूल गई जिस बैग में यह कागजात, साथ ही सोने की चेन और पेंडेंट तथा उनके फ्लैट की फोटो कॉपी थी.

इस नुकसान के संबंध में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई है. अगर किसी को उपरोक्त कागजात मिले तो कृपया उन्हें वापस सौंप दे या अंजली टिक्कू को 9310971140 इस नंबर पर संपर्क करें.

हस्ताक्षर/–
स्थल : नई दिल्ली
अंजली टिक्कू

NOTICE

TATA ELXSI LIMITED

Registered Office: ITPB Road, Whitefield, Bengaluru 560048

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/mislaid and the holder(s) of the said securities has/have applied the Company to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

Names of holders	Kind of Securities and Face Value	Number of Securities	Distinctive number(s)
ROOPA DUA & RAMJI DASS DUA	Equity Shares of face value Rs 10/- each.	200	31225061 - 31225260
Place: New Delhi	Date: 24 July , 2024	Names of holder(s) /Applicate(s): Roopa Dua/Roopa Sareen & Ramji Dass Dua	

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मनीष नलिनी, श्वेता ठाकुर, केरोल इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड और राजीव कुमार सिंह (गारंटर)** को **15.12.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOI00285956** की राशि **रू.11,09,034.78 /- (रुपए ग्यारह लाख नौ हजार चौंतीस और अठहत्तर पैसे मात्र)** और **12.12.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरिटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्तद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.11,09,034.78 /- (रुपए ग्यारह लाख नौ हजार चौंतीस और अठहत्तर पैसे मात्र) 12.12.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.1606, जिसका सुपर एरिया 1495 स्के.फीट, सोलहवी मंजिल पर, सिक्का किरात ग्रीन्स नाम से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, टॉवर मंगोलिया, प्लॉट नं.जीएच-4सी पर निर्मित, सेक्टर-10 में स्थित, ग्रेटर नोएडा -201305, उत्तर प्रदेश ।

सही/-
दिनांक :19.07.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान :ग्रेटर नोएडा — **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि हमारा ग्राहक (ए) पूर्ण ब्लॉक-सी (वेयरहाउस) माप लगभग 4,39,032.95 वर्ग फीट भूतल स्ट्रक्चर, और (बी) ड्राईवर्स ब्लॉक माप लगभग 2,915 वर्ग फीट भूतल और प्रथम तल स्ट्रक्चर, ब्लॉक-सी में मेजेनाईन तल से युक्त पूर्ण स्पेस के साथ प्रथम तल स्ट्रक्चर (**"लीज्ड परिसर"**), (i) ट्रक एवं कारों की पार्किंग के उद्देश्य हेतु ट्रक पार्किंग एरिया के एक्सक्लुसिव उपयोग के अधिकार(**"एक्सक्लुसिव पार्किंग एरिया"**) (ii)कथित भूमि के भाग एवं पार्सल के एक्सक्लुसिव उपयोग के अधिकार, जिसमें साईड मार्जिन रोड, लोडिंग/अनलोडिंग बेज, एक्सेस रोड आदि शामिल है (**"एक्सक्लुसिव एरिया"**) (iii) लीज किए गए परिसरों से जुड़े हुए 12 मीटर चौडे रोड के ऊपर मार्ग के अधिकार (कथित भूमि पर परियोजना के अन्य निवासियों के साथ कॉमन और नॉन एक्सक्लुसिव आधार पर)(**"एक्सेस रोड"**), गांव कुलाना, तहसील एवं जिला-झज्जर, हरियाणा-124108 (**"कथित भूमि"**) पर स्थित खसरा संख्या 12//16/2 (4-8); 12//17 (8-0), 12//18 (5-18), 12//22/1 (0-8), 12//22/2 (3-2), 12//22/3 (1-9), 12//23/1 (1-11), 12//23/2 (4-16), 12//23/3 (1-13), 12//24/1 (1-11), 12//24/2 (4-13), 12//24/3 (1-16), 12//25/1 (0-17), 12//25/3 (4-13), 12//25/4 (1-16); खसरा सं. 13//21/2 (5-11); खसरा सं. 26//1/1 (7-1), 26//2/2 (0-9), 26//10 (8-0), 26//9 (2-0), 26//8 (8-0), 26//3/1/2 (5-11); खसरा सं. 27//1 (2-14), 27//2 (8-0), 27//3 (8-0), 27//4 (8-0), 27//5 (8-0), 27//6 (8-0), 27//7 (8-0), 27//8 (8-0), 27//9 (8-0), 27//10 (7-5), 27//11/1 (2-4) एवं खसरा सं.28//15 (5-0)में सम्मिलित भूमि माप 166 कनाल 6 मरले पर अनुमोदित नॉन एग्रो वेयरहाउसिंग परियोजना के भाग के तौर पर, में सम्मिलित निर्मित नॉन-एग्रो वेयरहाउसिंग स्पेस माप 4,41,947.95 वर्ग फीट की लीज से संबंधित प्लाट सं. 1093, सेक्टर-46, गुरुग्राम-122003 (**"मालिक"**)पर व्यवसाय के मुख्य स्थान वाली भागीदारी फर्म ग्रास वेयरहाउसिंह कारपोरेशन(Graas Warehousing Corporation) के साथ ट्रांजिक्शन में प्रविष्ट होने का इच्छुक है। लीज किए गए परिसर, एक्सक्लुसिव पार्किंग एरिया, एक्सक्लुसिव एरिया एवं एक्सेस रोड संयुक्त तौर पर (**"विषयगत संपत्ति"**) पर संदर्भित है। विषयगत संपत्ति की घिराव निम्नानुसार है:

उत्तर: कृषि भूमि
दक्षिण: कृषि भूमि
पश्चिम: कृषि भूमि
पूर्व: एनएच-71/ (नया एनएच 352)

यदि कोई व्यक्ति या कोई कानूनी संस्था विषयगत संपत्ति या उसके किसी भाग में बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय, असाइनमेंट, वसीयत, रिलीज, त्याग, किसी न्यायालय के आदेश, ऋणग्रस्तता, बंधक, पट्टा, ग्रहणाधिकार, प्रभार, लाइसेंस, उपहार, उत्तराधिकार, अविभाजित हिस्सा, कब्जा, सुखभोग, ट्रस्ट, वसीयत, पट्टा, किरायेदारी, उप-किरायेदारी, त्याग और लाइसेंस, लिस पेंडेंस, सुखभोग, विकल्प, पहले इनकार का अधिकार या पूर्व क्रय या ऋणभोग जो भी प्रकृति का हो या अन्यथा, या किसी समझौते, कार्य, दस्तावेज, या पावर ऑफ अटर्नी या किसी भी तरह की किसी भी आपत्ति के तहत किसी भी प्रकार का अधिकार, शीर्षक, दावा, लाभ, मांग या हित रखती है या दावा करती है, तो इसके समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण की नोटरीकृत/प्रमाणित सत्य प्रतियों के साथ लिखित रूप में इस सूचना कि तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना आवश्यक है, अनुसूचित संपत्ति और प्रस्तावित संपत्ति स्पष्ट, वैध और विक्रय योग्य है और अनुसूचित संपत्ति और प्रस्तावित संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार/शीर्षक/हित/दावा/मांग नहीं है। बिना सहायक दस्तावेजों के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। **कृपया अपने लिफाफे पर उपरिलेख [CN-JHJ] अंकित करें।**

दिनांक : 25 जुलाई 2024
लेक्सनेगोटियम एडवोकेट्स
ध्यानार्थः- विकास पंत, मुख्य भागीदार
3-डी, रो हाउस ,सूर्य विहार अपार्टमेंट्स, डुंडाहेडा गुड़गांव, 122016, हरियाणा
दूरभाषः- +91 124 400 8001, +91 989911 5125, +91 987386 5125

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **आदी डान्स अकादमी और फिटनेस स्टूडियो थ्रु इट्स प्रोप्राइटर आदित्य चौधरी और वीरमती** को **24.01.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HLAPMAT00407297** की राशि **रू.25,29,439.12 (रूपये पच्चीस लाख उनतीस हजार चार सौ उनतालीस और बारह पैसे मात्र)** और **20.01.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **23.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.25,29,439.12 (रूपये पच्चीस लाख उनतीस हजार चार सौ उनतालीस और बारह पैसे मात्र) 20.01.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 235/1, तल मंजिल पर स्थित, मौजा बाद, खसरा नं. 1467 से 1469 और 1475 से 1490 और 1503, 1504 से 1518 से 1522 और 1523, 1524,1525, 1527 और 1528, मौजा बाद, श्री राधा टाउन के अंदर, तहसील और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश ।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23.07.2024 — **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
स्थान : मथुरा — **(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड से जाना जाता था)**

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")
CIN : U65993DL2002PLC115769
पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,वेबसाइट: www.acreindia.in
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051. फोन: 022 68643101

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड (CIN:U65993DL2002PLC115769) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **विश्वनाथ प्रसाद केसरी और सारिका केसरी** को **19.02.2024** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00210378** की राशि रू. **61,16,352.33 (रूपये इकसठ लाख सोलह हजार तीन सौ बावन और तैंतीस पैसे मात्र)** और **14.12.2023** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **22.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 61,16,352.33 (रूपये इकसठ लाख सोलह हजार तीन सौ बावन और तैंतीस पैसे मात्र) 14.12.2023** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

कैपटाउन से पहचाने जानेवाले टॉवर CV -8 में, दसवीं मंजिल पर, फ्लैट नं. 1007, जिसका सुपर एरिया 930 स्क्वे. फीट, एक कवर्ड हुई कार पार्किंग के साथ, प्लॉट नं. जीएच-1/ए पर स्थित , सेक्टर-74, नोएडा-201301, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 22.07.2024 — **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.**
स्थान : गौतम बुद्ध नगर — **(102- ट्रस्ट)**

किसी भी शिकायत के लिए आप **श्री मोहम्मद शारिक मलिक,** शिकायत निवारण अधिकारी, फोन नंबर 011-66115609, ईमेल: complaint@acreindia.in से संपर्क कर सकते हैं। संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र विस्तृत रुप से https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है।

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **जयवंत बिष्ट प्रॉपराइटर फ्रेंड्स मेडिकोज एवं वीना बिष्ट** को **16.11.2018** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOI00303288** की राशि **रू.15,20,132 /- (रुपए पंद्रह लाख बीस हजार एक सौ बत्तीस मात्र)** और **16.11.2018** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरिटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्तद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.15,20,132 /- (रुपए पंद्रह लाख बीस हजार एक सौ बत्तीस मात्र) 16.11.2018** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अपार्टमेंट नं.सन 8-1804 , जिसका सुपर एरिया लगभग 113.805 स्के.मीटर्स, कवर्ड एरिया लगभग 86.030 स्के.मी., जिसमें 65.770 स्के.मी. का कारपेट एरिया भी शामिल है, टॉवर सन-8 में, अठारहवीं मंजिल, मिगसन विन पर स्थित, हाउसिंग प्लॉट नं.जीएच -1बी(1), सेक्टर -ईटा -II, ग्रेटर नोएडा, नोएडा-201308, उत्तर प्रदेश, एक आरक्षित बेसमेंट कार पार्किंग जगह के साथ।

सही/-
दिनांक :19.07.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान :नोएडा — **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **राज कुमार और सुनीता** को **29.04.2024** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDMT00418692** की राशि **रू.18,46,440.93 /- (रुपए अठारह लाख छियालीस हजार चार सौ चालीस और तिरानवे पैसे मात्र)** और **26.04.2024** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरिटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2024** को संपत्ति पर सांकेतिक **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्तद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.18,46,440.93 /- (रुपए अठारह लाख छियालीस हजार चार सौ चालीस और तिरानवे पैसे मात्र) 26.04.2024** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.एफएफ -2 (एम.आई.जी.) जिसका कुल एरिया 500 स्के.फीट यानि 46.45 स्के.मी., पहली मंजिल पर, (सामने दाहिने हाथ की ओर), (रूफ राइट्स के बिना) प्लॉट नं.एफ 13 पर निर्मित, एस.एल.एफ.वेद विहार में स्थित, गाँव लोनी,गाज़ियाबाद -201102, उत्तर प्रदेश और जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व: 9 मी.चौड़ा रोड — **पश्चिम: फ्लैट नं.एफएफ3 (एल.आई.जी.)**
उत्तर: प्लॉट नं.एफ 12 — **दक्षिण: कॉमन पैसेज और फ्लैट नं.एफएफ-01 (एल.आई.जी.)**

सही/-
दिनांक :19.07.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान :गाज़ियाबाद — **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **उमाकांत उर्फ उमाकांत शर्मा और अनिता उर्फ अनिता शर्मा** को **23.01.2020** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOD00354007** की राशि **रू.13,38,493 /- (रुपए तेरह लाख अडतीस हजार चार सौ तिरानवे मात्र)** और **23.01.2020** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरिटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्तद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.13,38,493 /- (रुपए तेरह लाख अडतीस हजार चार सौ तिरानवे मात्र) 23.01.2020**के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय अपार्टमेंट नं.ए -1103, ग्यारहवीं मंजिल, जिसका सुपर एरिया लगभग 1095 स्के.फीट , महालक्ष्मी ग्रीन मेंशन से पहचाने जाने वाले ग्रुप हाउसिंग में, एचआरए-14 पर निर्मित, झेटा-1 के सामने, सूरजपुर, साइट-सी, ग्रेटर नोएडा -201308, उत्तर प्रदेश ।

सही/-
दिनांक :19.07.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान :ग्रेटर नोएडा — **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

मांग सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेंट्रल और पंजीकृत कार्यालयः एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड के पास, कलिना, मुंबई 400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग नोटिस जारी किया है जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं (उधारकर्ताओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है जो नीचे दी गई है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ताओं को एक बार फिर से इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर ईएआरसी का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, नीचे दी गई राशि, उक्त मांग नोटिस में विस्तृत ब्याज के साथ, अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, यदि कोई हो तो उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा क्रमश निम्नलिखित परिसम्पत्तियां ईएआरसी को गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम/ऋण खाता नं.	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	ट्रस्ट और असाइनर का विवरण
1.	1. विपिन चोपड़ा (उधारकर्ता) 2. सोनिया चोपड़ा (सह–उधारकर्ता) LAN: NHNOD00000798115	25.06.2024 और ₹ 3,19,46,243.84/-	**EARC** ट्रस्ट एससी **448** और ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

सम्पत्ति का विवरण : अचल सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अपार्टमेंट नं. 01B106, विंग बी, 10वां तल, साथ में पार्किंग स्पेस नंबर–पीसीबी–21 (खुला/कवर्ड) बहुमंजिला इमारत नं. 01 में जिसे डीएलएफ ओकवुड एस्टेट के नाम से जाना जाता है, भूमि के प्लॉट पर निर्मित, ग्रुप हाउसिंग स्कीम का हिस्सा, क्षेत्रफल 6.46 एकड़ या उसके आसपास, गांव सरहुल के रेवेन्यू ईस्टेट में, शाहपुर, नाथुपुर, सिकंदरपुर घोसी, तहसील और जिला–गुड़गांव (हरियाणा) ग्रुप हाउसिंग में, रिहायशी कॉलोनी जिसे अब डीएलएफ सिटी (पहले डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था) फेज।।, सुपर एरिया 162.57 वर्ग मीटर (1750 वर्ग फीट) और निम्नानुसार चौहद्दीः उत्तर की ओर – कॉरिडोर/लिफ्ट लॉबी, दक्षिण की ओर – 106, पूरब की ओर – खुला, पश्चिम की ओर – कॉरिडोर/बी–105 पार्किंग (खुला/कवर्ड), उत्तर की ओर – ड्राइववे, दक्षिण की ओर – सीबी–19, पूरब की ओर – सीबी–20, पश्चिम की ओर – सीबी–22

यदि उक्त उधारकर्ता पूर्वोक्त के रूप में ईएआरसी को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ईएआरसी अधिनियम की धारा 13 (4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, पूरी तरह से उक्त उधारकर्ता(ओं) के जोखिम पर लागत और परिणामों के रूप में। अधिनियम के अंतर्गत उधारकर्ताओं को ईएआरसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के रूप में उपर्युक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक 25/07/2024 — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः दिल्ली/एनसीआर — **कृते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

Edelweiss Asset Reconstruction

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")
CIN : U65993DL2002PLC115769
पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,वेबसाइट: www.acreindia.in
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051. फोन: 022 68643101

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ("आईएचएफएल") प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **विवेक चंद्रा और निधि चंद्रा** को **18.10.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. V024XII (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता नं. HHLNOI00163717)** की राशि **रू. 35,34,138 (रूपये पैंतीस लाख चौंतीस हजार एक सौ अड़तीस मात्र)** और **14.10.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । इसके अलावा **आईएचएफएल ने इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में **इंडियाबुल्स एआरसी –XII ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज **31.12.2019**. को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौपा है, इसके अलावा **इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबुल्स एआरसी –XII ट्रस्ट के ट्रस्टी** ने दिनांक **26.04.2021** के असाइनमेंट करार के माध्यम से **एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")** के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज सौंपा है, जिसे दिनांक **26.08.2021** के सुधार समझौते के साथ पढ़े और कर्ज खाता जिसे **एसीआरई** की पुस्तकों में कर्ज खाता नं.**V024XIII** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है, सौंपा है ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **22.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 35,34,138 (रूपये पैंतीस लाख चौंतीस हजार एक सौ अड़तीस मात्र) 14.10.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

क्रिस्टल कोर्ट प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट बेअरींग यूनिट रेफरेंस नंबर- केआरआई-01-202, जो जेपी ग्रीन्स पर डेवलपर- जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित / निर्माण होनेवाले टावर- 1, सेक्टर- 128, नोएडा- 201301, उत्तर प्रदेश, जिसका लगभग सुपर एरिया 250.8361 स्क्वे. मीटर्स (2700.00 स्क्वे.फीट), 1 (एक) कार पार्किंग स्लॉट के साथ, जिसे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर रेफरेन्स 43943/373335/ केआरआई0010202 के तहत आवंटित किया गया है। (ग्राहक आईडी:जेजीएनकेआरआई 010202) दिनांक 15.05.2013.

सुरक्षित संपत्ति का डाक पता इस प्रकार है :

यूनिट नं. 202, दूसरी मंजिल, टावर- 1, जेपी "क्रिस्टल कोर्ट", विशटाउन नोएडा, 'जेपी ग्रीन्स", सेक्टर- 128, नोएडा- 201301, उत्तर प्रदेश।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 22.07.2024 — **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.**
स्थान : नोएडा — **(102- ट्रस्ट)**

किसी भी शिकायत के लिए आप **श्री मोहम्मद शारिक मलिक,** शिकायत निवारण अधिकारी, फोन नंबर **011-66115609**, ईमेलः **complaint@acreindia.in** से संपर्क कर सकते हैं। संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र विस्तृत रुप से **https://www.acreindia.in/compliance** पर देखी जा सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण

उम्मीद से भरपूर

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत की प्रगति व विकास के प्रति उम्मीदों से भरपूर है। हालांकि, केन्द्रीय बजट के एक दिन पहले पेश सर्वेक्षण में चिन्ताजनक क्षेत्रों की ओर संकेत करते हुए केन्द्र सरकार से इनमें प्राथमिकता से काम करने का अनुरोध किया गया है। बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की परंपरा है क्योंकि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख कर इससे बजट का माहौल बनता है। इस वर्ष अच्छी आर्थिक वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के 6.5-7.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण एक समग्र रिपोर्ट है जिसने पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की समीक्षा कर विभिन्न क्षेत्रों में तेज वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। इस आशावाद के अनेक आयाम हैं जिनमें मजबूत घरेलू उपभोग, बढ़ता निवेश तथा लाभदायक सरकारी नीतियां शामिल हैं। मजेदार बात है कि ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थायें जीडीपी का इससे काफी निचला स्तर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सर्वेक्षण ने ढांचागत विकास पर सरकार की सक्रियता को रेखांकित किया है जो आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक है। सड़क, रेल और बंदरगाह विकास की वर्तमान समय में जारी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और क्षमता में वृद्धि होगी तथा सहज व्यापार एवं वाणिज्य में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास आर्थिक वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आलोचनाओं के बावजूद सर्वेक्षण का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' पहल के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, निर्यात व खासकर उच्च वृद्धि दर वाले फार्मास्यूटिकल्स, एलेक्ट्रानिक्स व टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने से भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समस्याग्रस्त क्षेत्रों की बात भी की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाने वाली कृषि प्राथमिकता बनी हुई है। सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने तथा टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों का सुझाव दिया है। तकनीकों में खोज तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण ने उचित ही विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया है जो अर्थव्यवस्था को नीचे धकेल सकते हैं तथा राष्ट्रीय वृद्धि में बाधा बन सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी बाधा मुद्रास्फीति है। सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए बिना वृद्धि को प्रभावित किए मुद्रास्फीति पर लगाम लगाई जा सकती है। बेरोजगारी एक और बाधा है जिसे प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण ने ऐसी नीतियों का समर्थन किया है जो कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन दें तथा आर्थिक विकास के उपयुक्त परिवेश का निर्माण करें ताकि बढ़ती हुई युवा जनसंख्या की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के उपयुक्त परिवेश बनाने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पुन: दुहराई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में आर्थिक सर्वेक्षण के अनेक सुझावों को शामिल किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोडमैप पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने नौ प्राथमिकतायें परिभाषित की हैं। इनमें कृषि, रोजगार, मानव विकास, ऊर्जा सुरक्षा, विनिर्माण, खोज, ढांचागत संरचना तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। इनसे बेरोजगारी घटाने, मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने तथा अर्थव्यवस्था को समावेशी व टिकाऊ बनाने में सहायता मिलेगी।

एमएसएमई हेतु आयकर संशोधन

छोटे उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा विलंबित भुगतान बड़ी समस्या है। इसके कारण कार्यकारी पूंजी में आने वाली कमी से उत्पादन प्रभावित होता है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

वित्त कानून, 2023 के अंतर्गत आयकर कानून में संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हो गया है। इसमें वस्तुओं व सेवाओं के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों-एमएसएमई को 45 दिन से अधिक भुगतान के विलंब तथा कर छूट की मांग करने पर रोक लगाई गई है। एमएसएमई सहायक इकाइयां हैं जो बड़े उद्यमों या प्रमुख इकाइयों को वस्तुओं और अधिकांशत: सहायक वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण में सहायता करती हैं। ये इकाइयां छोटे पैमाने पर काम करती हैं और इनको सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के रूप में पुन: परिभाषित किया जाता है जो उनके 'निवेश' और 'टर्नओवर' से तय होता है। इसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम विकास कानून, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

सूक्ष्म उद्यम का अर्थ ऐसा उद्यम है जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरणों में निवेश 10 मिलियन रुपये से अधिक न हो तथा उनका टर्नओवर 50 मिलियन रुपये से अधिक न हो। लघु उद्यम में प्लांट और मशीनरी में निवेश 100 मिलियन रुपये से कम होना चाहिए तथा टर्नओवर 500 मिलियन से अधिक न हो। मझोले उद्यम के लिए यह सीमा निवेश हेतु 200 मिलियन तथा टर्नओवर 1000 मिलियन परिभाषित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए में एमएसएमई का हिस्सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत है। अखिल भारतीय विनिर्माण में विनिर्माण एमएसएमई का हिस्सा और अधिक लगभग 36 प्रतिशत है।

कामर्शियल इंटेलीजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स महानिदेशालय-डीजीसीआईएस के अनुसार, अखिल भारतीय निर्यातों में एमएसएमइ-विशिष्ट उत्पादों के निर्यात का हिस्सा पिछले दो वर्ष में 44 से 50 प्रतिशत के बीच रहा है। जहां तक रोजगार का सवाल है, मैक्किन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट-एमजीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई का योगदान कुल में 52 प्रतिशत है। 'अनौपचारिक' क्षेत्र में एमएसएमई के अलावा पारिवारिक संपत्ति व साझेदारी वाले उद्यम शामिल हैं। इनका रोजगार में योगदान 75 प्रतिशत से अधिक है, जबकि जीडीपी में इनका हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है। इस प्रकार एमएसएमई अर्थव्यवस्था की संभावनायें निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही ये 'समावेशी' विकास में अपनी भूमिका अदा करते हुए खासकर रोजगार बढ़ाने, आय बढ़ाने व आय असमानता घटाने का काम करती हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में उन पर आर्थिक निर्णयों का बोझ पड़ा है।

इनमें 2016 में नोटबंदी, 2017 में वस्तु एवं सेवाकर-जीएसटी लागू करना तथा 2020 में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी का विनाशकारी प्रभाव शामिल हैं। सरकार ने इनकी समस्यायें दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिनमें 500,000 करोड़ रुपये की बिजनेसों व एमएसएमई के लिए आपातकालीन कर्ज गारंटी योजना-ईसीएलजीएस तथा एमएसएमई सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान शामिल है जिससे उनको सरकारी ठेके लेने में सहायता मिली है। इसके अलावा एमएसएमई के वर्गीकरण में रियायतें, गैर-टैक्स लाभों का 3 साल तक विस्तार, खुदरा एवं थोक व्यापारों को एमएसएमई में शामिल करना, उद्यम सहायता प्लेटफार्म-यूएपी शुरू करना, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज योजना-पीएसएल के अंतर्गत लाभ दिलाना, ई-गवर्नेंस के विभिन्न आयामों को शामिल करने वाले आनलाइन पोर्टल 'चैम्पिन्स' को शुरू करना तथा एमएसएमई की शिकायत निवारण व सहायता की व्यवस्थायें शामिल हैं।

इन सारी पहलों का उद्देश्य कर्ज की उपलब्धता, तकनीक के समावेशन, बाजार सहायता, आदि प्रदान करना है, पर इन उद्यमों के समक्ष बड़े उद्यमों द्वारा बकाया देर में भुगतान करने की समस्या बनी हुई है। सप्लाई की गई वस्तुओं का भुगतान न मिलने पर उनके पास कार्यकारी पूंजी की भारी कमी हो जाती है जिससे 'उत्पादन जारी रखने की क्षमता' पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

इस समस्या के समाधान के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 15 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लिखित अनुबंध की स्थिति में 45 दिन में भुगतान करना जरूरी है, जबकि लिखित अनुबंध न होने की स्थिति में यह अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है। 2019 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने विशिष्ट कंपनी आदेश जारी कर कहा था कि बड़ी फर्मों को हर 6 महीने में रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही एमएसएमई को 45 दिन की सीमा में कोई भुगतान बकाया न हो। लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी हुई है और अनेक फर्मों को बंद करना पड़ा है। इसके बाद केन्द्र सरकार ने आईटी एक्ट, 1961 के अंतर्गत समाधान खोजने का प्रयास किया। वित्त कानून, 2023 ने आईटी एक्ट, 1961 में नई धारा 43बीएच जोड़ी।

इसके अनुसार यदि बड़ी कंपनी लिखित अनुबंधों की स्थिति में 45 दिन में एमएसएमई को भुगतान नही करती है तो इस खर्च को उसके वित्त वर्ष की कर योग्य आय में काटा नहीं जा सकता है। एमएसएमई से खरीदी वस्तुओं का भुगतान खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए इसे राजस्व से काटा जा सकता है। यदि कोई बड़ी फर्म एमएसएमई को 45 दिन की निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करती है तो धारा 43बीएच के अनुसार वह इस धनराशि को कर योग्य आय से काट नहीं सकती है। इससे उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यह एक बड़े प्रतिरोधक का काम करता है जिससे बड़े उद्यमों द्वारा एमएसएमई का भुगतान रोकना संभव नहीं होगा। लेकिन इस अतिरिक्त कर का कंपनी की बैलेंसशीट पर प्रभाव हमेशा के लिए नहीं पड़ता है। इस अतिरिक्त कर को अगले साल एडजस्ट किया जा सकता है जब कंपनी एमएसएमई को भुगतान करे।

इस प्रकार यह धारा सभी पक्षों के बीच अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इससे बड़े उद्यमों को एमएसएमई के भुगतान को प्राथमिकता देने के साथ ही उनके वित्तीय स्वास्थ्य व आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसके साथ ही वह बड़े उद्यमों को अनावश्यक दंड नहीं देती है। लेकिन इस बीच कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 2019 के आदेश में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में राहत दे दी है। 15 जुलाई, 2024 को जारी एक आदेश के अनुसार इसकी आवश्यकता केवल उन कंपनियों को है जिन्होंने किसी एमएसएमई को अनिवार्य 45 दिन के भीतर भुगतान न किया हो। इसका निर्धारण वस्तुओं या सेवाओं को स्वीकार करने की तिथि के आधार पर होगा। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 की धारा 9 के अनुसार उस बड़े उद्यम को यह सूचना देनी होगी जिसने एमएसएमई से वस्तु एवं सेवा प्राप्त की है और उसे निर्धारित 45 दिन में भुगतान नहीं किया है।

लेकिन यह आदेश जारी होने के पहले बड़े उद्यमों को यह सूचना उस स्थिति में भी देनी होती थी, जब एमएसएमई को कोई भुगतान निर्धारित 45 दिन की अवधि में बाकी न हो। इससे बड़े उद्यमों को कानून के क्रियान्वयन से थोड़ी राहत मिली है और उन पर एमएसएमई भुगतान का दबाव घटा है। लेकिन इसके बावजूद उद्योगों और बिजनसों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आईटी एक्ट में संशोधित इस धारा का क्रियान्वयन एक साल यानी अप्रैल, 2025 तक टाल दिया जाए।

इसके साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बड़े उद्यम छोटी फर्मों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वे एमएसएमई से कोई सप्लाई न लें। इसके बजाय वे केवल ऐसी एमएसएमई से व्यवहार करें जिनका पंजीकरण 'उद्यम पोर्टल' पर न हो या वे गैर-एमएसएमई से सामान खरीदें। 'उद्यम पोर्टल' केन्द्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई पंजीकरण के लिए बनाया गया है। बड़े उद्यमों के इन अनुरोधों को अस्वीकार कर सरकार को आईटी एक्ट की धारा 43बीएच को स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करने देना चाहिए।

भारत में अस्तित्वमान तीन नये कानून

जहां कुछ कानूनी निकायों ने नए कानूनों की आलोचना की है, वहीं अन्य इन कानूनों को आधुनिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखते हैं।

मनोज वर्धीस
(लेखक मीडिया जगत से जुड़े हैं)

1 जुलाई को शुरू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के साथ, कुछ कानूनी निकायों और अन्य नागरिक संगठनों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि इसे संसद में 'बहुत चर्चा' के बिना पेश किया गया है। जबकि, कुछ कानूनी विशेषज्ञ इसे एक 'नया अवतार' मानते हैं जो देश को पसंदीदा औपनिवेशिक कानूनों से समकालीन भारत में बदलाव करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कानूनों ने लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किए गए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) के कानूनों की जगह ले ली है। नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लाएंगे, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। करीब 20 नए अपराध जोड़े गए, 40 अपराधों में संशोधन किया गया, 83 नए जुर्माने लगाए गए और छह सामुदायिक सेवाएं शुरू की गईं, नए कानून जनहित में त्वरित न्याय देने के लिए तैयार हैं।

नए कानून 'नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले' की तर्ज पर बनाए गए हैं। आम धारणा यह है कि पुलिस को अब 'डंडे' की जगह 'डेटा' से काम करना होगा। सार्वभौमिक रूप से, किसी भी प्रणाली में बदलाव लाना और उसे लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे बढ़कर, कानूनी प्रणाली में बदलाव अनुकूलन के लिए एक जटिल तंत्र है। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा कहते हैं, परिवर्तन अपरिहार्य है, और प्रगतिशील कानून किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छे हैं।

पुलिस को यह समझने की जरूरत है कि वे अधिकार क्षेत्र की कमी या विवादित अधिकार क्षेत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते। उनके लिए इसे व्यवहार में लाना कठिन है क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज मामलों की संख्या उनके संबंधित पुलिस स्टेशन की बदनामी लाएगी। अब वे कानूनी रूप से (शून्य एफआईआर) दर्ज करने और ऐसे मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हैं। बीएनएसएस की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखने और प्रमुखता से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एल मेहता कहते हैं, कानून लोगों के कल्याण के लिए राज्य द्वारा अनुकरण किए जाने वाले मानदंडों का एक समूह है। कानून कानूनी व्यवस्था के लिए प्रभावी उपाय है। कानूनी व्यवस्था में देरी अपरिहार्य तंत्र है। केवल 20 प्रतिशत मामले ही अदालत तक पहुँचते हैं, पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह एक कठिन कार्य है और इन लंबित मामलों का निपटारा करने में 300 साल से अधिक का समय लगेगा। बीएनएसएस के अनुसार, नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता देते हैं, सूचना दर्ज करने के दो महीने के भीतर समय पर पूरा करना सुनिश्चित करते हैं (धारा 193)। समन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जा सकते हैं (धारा 64, 70, 71)। मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन दे सकते हैं (धारा 346)।

नए कानून में सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना (धारा 398) लागू करने का आदेश दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों (अध्याय 5) और छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरूआत (धारा 4, 202, 209, 226, 303, 355, 356) के लिए विशेष रूप से बीएनएस में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, और पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक, फोरेंसिक कर्मियों के साथ-साथ आम जनता सहित सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सरकार ने कई दौर के अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नए शुरू किए गए तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में कानूनी प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नए आपराधिक कानूनों के साथ प्रौद्योगिकी अनुकूलता की सुविधा के लिए मौजूदा सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पुलिस, जेलों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में तीन नए आपराधिक कानूनों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह नए कानूनों का मसौदा तैयार करने में शिक्षाविदों की भूमिका की सराहना करते हैं। उनका सुझाव है कि आने वाले दिनों में देश को पर्याप्त संख्या में फोरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत, जितने अधिक नए कानून सामने आएंगे, उतनी ही अधिक इसकी कमियों के उजागर होने की संभावना है। क्या अपराध की बढ़ती घटनाएं पुलिस और वकीलों के लिए अच्छी हैं, यह एक बड़ा सवाल है!

आप की बात

राहत देने वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट 03 राहत देने और सबको साधने वाला है। इसमें युवाओं को रोजगार देने पर अत्यधिक जोर दिया गया जो कि आवश्यक था। महिलाओं के कल्याण के लिए बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन खटकने वाली बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी के बजाय उल्टे सात प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। यह फैसला उचित नहीं लगता है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र को भी और अधिक धन दिया जाना था क्योंकि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय युद्धग्रस्त परिस्थितियों और चीन पाकिस्तान के नापाक इरादों के चलते रक्षा क्षेत्र में और अधिक सुधार कर सेनाओं को अत्याधुनिक तकनीक से लेस करना अब अत्यधिक जरूरी हो गया है। चांदी सोने की ड्यूटी में कटौती करने की कोई तुक नजर नहीं आई और शेयर बाजार में करों का बोझ बढ़ाना भी उचित नहीं है। इससे निवेशक अपना निवेश शेयर बाजार से निकलकर चांदी-सोने में करेंगे जो आर्थिक विकास की गति को धीमा करेगा। अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा बजट देना भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन कुल मिला कर बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा। सरकार के इस कदम से उम्मीद बढ़ी है।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

रोजगारोन्मुख बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार रोजगार उन्मुख बजट पेश किया है जो कि देश की युवा शक्ति के लिए अत्यावश्यक था। रोजगारों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था एक अच्छा कदम है। लेकिन पहली बार नौकरी करने वालों को एक माह की पगार देना समझ से परे है। जिनकी नौकरी लग ही गई है, उन्हें एक माह की मुफ्त पगार देने के बजाए युवकों को नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए धन खर्च किया जाना चाहिए था। कृषि को भी महत्व दिया गया है। देश की बढ़ती खाद्य जरूरतों को देखते हुए जेनेटिक फसलों पर अधिक शोध कर और उन्हें मानव स्वास्थ्य के अनुकूल बनाकर उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। इससे दालों व खाद्य तेल के आयात पर लगाम लग सकती है। नौकरी व पेशेवर वर्ग को करों में जो राहत दी गई, वही राहत मध्य मार्ग के व्यापारियों को भी मिलनी चाहिए थी। कर मुक्त टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया जाना था। शेयर का काम करने वालों के लिए पहले से ही लागू भारी टैक्स को और भारी बनाना शेयर होल्डर्स को निराश करेगा। सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त चिकित्सा और कारों में विशेष राहत भी दी जानी चाहिए थी। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाना चाहिए।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

इंटर्नशिप का स्वागत

वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट को विपक्षी दलों ने कुर्सी बचाओ बजट बताया है। बजट का सबसे खूबसूरत पहलू युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास है। बजट में की गई पांच वर्ष में एक करोड़ इंटर्नशिप एवं छात्रों के लिए 10 लाख रुपए शिक्षा लोन की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। बजट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बिहार को 56 हजार करोड़ की और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की परियोजनायें हैं। लेकिन देखना होगा कि कहीं यह धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। बिहार में थोड़े ही समय में अनेक पुलों के गिरने की खबरें सुर्खियों में रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। इस बजट में विष्णुपद मंदिर एवम बौद्ध गया हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है। इन महत्वपूर्ण स्थलों के विकास से अंतरराष्ट्रीय पर्यटक बिहार में बड़ी संख्या में आएंगे। इससे बिहार समृद्ध होगा, विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा बजट व अपने राज्यों के लिए आबंटन पर खुशी जाहिर करने से उन मोदी-विरोधी विपक्षियों की उम्मीदें टूट गई हैं जो सरकार गिरने का राग अलाप रहे थे।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

सोना-चांदी सस्ता

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश करते हुए सारी महिलाओं की प्रमुख चाहत पूरा करने के लिए साने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत कर दी है। इससे अनेक महिलाओं को खुशी मिली है क्योंकि आभूषणों के प्रति उनका आकर्षण सभी जानते हैं। इससे जहां छोटे-बड़े सर्राफा कारीगरों को लाभ होगा, वहीं समाज के निम्न मध्य वर्ग व गरीब तबके को भी लाभ होगा जो शादी-विवाह या अन्य मंगल अवसरों पर घर की महिलाओं को कोई न कोई आभूषण देना चाहते थे। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से इसकी स्मगलिंग पर भी लगाम लगेगी तथा अमीर भारतीयों को विदेशों से सोना खरीद कर लाने का रास्ता खुलेगा। मध्यम वर्ग व सर्विस क्लास को खुश करने के लिए आयकर में राहत दी गई जिससे उन्हें 17,500 रुपये तक का लाभ हो सकेगा। निर्मला सीतारमण ने आठ महीने तक लागू होने वाले बजट में काफी नरमी दिखाई है। इस बजट से लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी व देश भी प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाले बजट जनता को और राहत देंगे।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

अयोध्या को जल्द मिल सकती है 110 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीर्थ विकास परिषद की बैठक कर योजनाओं को दे सकते है हरी झंडी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ अयोध्या

भले ही अयोध्या में मां सरयू प्रवाहमान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार रामनगरी में विकास की गंगा का अवतरण कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हाल ही में गठित हुए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद भी योजनाओं का पिटारा खोलने जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर 110 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दे सकते हैं।

रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से कई योजनाओं पर काम शुरू होने जा रहा है। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के पास 11 प्रोजेक्ट भेजे गए हैं। 110 करोड़ की इन परियोजनाओं पर परिषद की बैठक में मंजूरी मिलना तय है। इसी महीने सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तीर्थ विकास परिषद की बैठक संभावित है। बता दें कि अयोध्या में 32 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अब कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू करने तैयारी हो रही है। रामनगरी की पौराणिकता की गवाह मणिपर्वत का भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मणिपर्वत भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यहां हर साल सावन माह में मेला लगता है। रामनगरी में झूलनोत्सव का शुभारंभ मणिपर्वत मेले के साथ ही होता है।

श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के सीईओ संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि अयोध्या के नियोजित विकास के लिए विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के प्रस्ताव तीर्थ विकास परिषद को मिले हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के 8 और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 3 प्रस्ताव हैं। इन सभी योजनाओं की कुल कीमत करीब 110 करोड़ होगी। इन योजनाओं के मूर्त रूप लेने से रामनगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इन परियोजनाओं को मिलेगी स्वीकृति

- सभी प्रमुख स्थलों पर साइनेज लगवाने की योजना
- सरयू तट पर शिल्पकला एवं फाउंटेन व सौंदर्यीकरण का कार्य
- आचार्य नरेंद्र देव विवि के परिक्षेत्र में स्थित गुलाबबाड़ी का सौंदर्यीकरण
- राम की पैड़ी कैनाल से एनएच-27 तक सोतिया नाला का निर्माण
- मणि पर्वत के चारों तरफ एएसआई क्षेत्र छोड़ कर पाथवे का निर्माण
- फ्लोरिंग, बेच, साइनेज, लाइट एवं लेजर, पारदर्शी स्क्रीन, फूड क्योस्क का निर्माण
- अयोध्या के विभिन्न स्थलों का सौंदर्यीकरण

यात्रियों के रुकने व विश्राम की व्यवस्था का कार्य
- अयोध्या के कौशलेश सदन के जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण
- संत निवास का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण

फिटनेस प्रमाण पत्र न देने पर आरआई निलंबित एआरटीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम योगी का एक्शन जारी है। ताजा घटनाक्रम में योगी सरकार ने जनपद चित्रकूट के अंतर्गत स्कूली बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही पर एक्शन लेते हुए जिले के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की हीलाहवाली न की जाए। खासतौर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों पर सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। दरअसल, मंगलवार 23 जुलाई को जनपद चित्रकूट के श्रीजी इंटर कॉलेज, खोह के छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आ रही दो बसों को वाहन की फिटनेस समाप्त हो जाने के कारण सहायक संभागीय परिहन अधिकारी (प्रवर्तन) चित्रकूट की टीम द्वारा सीज कर बच्चों सहित 10 किमी दूर पुलिस लाइन ले जाया गया था। वाहन को 11.15 बजे सीज कर फायर सर्विस परिसर पुलिस लाइन में दाखिल किया गया व 13.05 बजे छोड़ा गया। इसके चलते करीब दो घंटे तक बस को खड़ा रखा गया। जानकारी के अनुसार, चित्रकूट जनपद के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) गुलाब चंद्र को संबंधित स्कूलों में जाकर स्कूली बसों के फिटनेस चेक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा आदेशों की अवहेलना की गई, जिसके कारण दोनों वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पाया। ऐसे में वाहनों को सीज करना पड़ा, जिससे बच्चों को भी तकलीफ हुई।

बुधवार को मामला संज्ञान में आने के बाद योगी सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। इसके तहत संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) गुलाब चंद्र को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विवेक कुमार शुक्ला के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है। साथ ही, प्रदेश में परिवहन विभाग से जुड़े समस्त कर्मियों को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के पहले वाहन परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र का उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

परिवहन विभाग द्वारा बुधवार को लखनऊ में वाहन परीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र का उद्घाटन किया गया। उक्त केन्द्र पर वाहनों की फिटनेस के साथ-साथ चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा मुहैया होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि चालकों के स्वास्थ्य परिक्षण से बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुचने में मदद होगी। साथ ही चालक भी सुरक्षित होगें। परिवहन मंत्री ने बताया कि उक्त फिट्नेस सेन्टर के खुलने से लखनऊ में और अधिक संख्या में वाहनों की जांच हो सकेगी। साथ ही चालकों की सामान्य बीमारियां जैसे- ब्लड प्रेशर, सुगर आदी के साथ उनका नेत्र परीक्षण भी हो सकेगा। चालकों को निशुल्क चश्मा भी मुहैया कराया जायेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि जांचोंपरान्त चालकों की कॉउन्सलिंग भी की जायेगी। चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ में इस तरह का पहला केन्द्र खोला गया है जहां नियमित जांच की सुविधा उपलब्ध होगी।

भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया: अखिलेश यादव

● सपा अध्यक्ष ने कहा, केन्द्र सरकार ने यूपी को बजट में कुछ विशेष देना तो छोड़िए उसका नाम तक नहीं लिया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने दस साल में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है। जनता का शोषण किया है। यह बजट नहीं चपत है। इस बजट ने लोगों को चपत लगा दिया। बजट से उत्तर प्रदेश की जनता निराश है। डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश की आस पूरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के पास नौकरी का संकट है। यह सरकार युवाओं को सम्मान जनक रोजगार नहीं दे सकती है। भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया। जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता है उसके साथ भेदभाव हुआ। यादव ने कहा कि सरकार को जानकारी है कि कैंसर की बीमारी बढ़ रही है लेकिन भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के दौरान लखनऊ में बनाये गये कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बजट नहीं दे रही। सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं चला पा रही है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार से बजट में कुछ मांगा ही नहीं। केन्द्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ विशेष देना तो छोड़िए उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जहां तक बनाया था आज भी वहीं तक रह गया। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को गाजीपुर बलिया से बक्सर तक जोड़ दिया जाता तो देश में भागलपुर से दिल्ली तक पूरा एक्सप्रेस-वे मार्ग मिल जाता लेकिन सरकार ने उसके लिए बजट नहीं दिया। यादव ने सुप्रीमकोर्ट के फैसले को लेकर शीर्ष कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि सौहार्द की जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत फैलाती है। जनता नफरत के खिलाफ एकजुट है। भाजपा अब नफरत फैलाने में सफल नहीं होगी। भाजपा का कम्युनल मुद्दा खत्म हो गया है। सम्प्रदायिकता का दिया आखिरी समय में फड़फड़ा रहा है।

यादव ने कहा कि केन्द्र की सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। यह बहुमत की सरकार नहीं है।

गरीबों के पक्के मकान का सपना होगा पूरा: केशव

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहा कि गरीब कल्याण व समग्र विकास पर केंद्रित केन्द्रीय बजट में ग्रामीण विकास व ग्रामोन्मुखी योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खोला गया है।

बजट में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में दो करोड़ आवास आवंटित करने का प्राविधान किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश में पहले से चिन्हित 60 हजार से अधिक पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किए जायेंगे, उसके बाद भी सर्वे कराया जायेगा, सर्वे के आधार पर जो पात्र पाये जायेंगे, उन्हें आवास आवंटित कराने की व्यवस्था की जायेगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यूपी के लिए 2020 करोड़ रूपए की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

पार्क का अवैध कब्जा हटाने के लिए दें पुलिस फोर्स: हाईकोर्ट

विधि संवाददाता। लखनऊ

रायबरेली रोड स्थित एल्डिको उद्यान टू के एक पार्क पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने जिलाधिकारी व सम्बंधित पुलिस अधिकारी को आदेश दिया है कि वो नगर आयुक्त व नगर निगम के उद्यान अधीक्षक को पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मुहैया कराएं। ताकि वो उक्त अवैध कब्जे को हटाने के लिए यथोचित कार्रवाई कर सकें। पीठ ने इसके साथ ही नगर आयुक्त और उद्यान अधीक्षक को छह हफ्ते में कार्रवाई का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवम जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश स्थानीय वकील हेमंत कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूरे पार्क पर अवैध निर्माण कर अवधेश प्रताप सिंह व उसकी पत्नी ने कब्जा कर लिया है। वो पार्क के गेट पर ताला लगाकर रखते हैं और अपनी सुविधानुसार ही उसे खोलते हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त पार्क में बच्चों तक को खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त और उद्यान अधीक्षक की ओर से वकील अमित कुमार द्विवेदी पेश हुए। उनका कहना था कि उक्त अवैध कब्जे को हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स के अभाव में यह संभव नहीं हो सका। पीठ ने इस पर उपरोक्त आदेश पारित किया।

किसानों को मिलेगी 12 घंटे निर्बाध बिजली

● ऊर्जा मंत्री ने कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति में की दो घंटे की बढ़ोत्तरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किसानों को और सुविधायें देने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कृषि पोषकों (एग्रीकल्चर फीडर) पर 10 घण्टे के स्थान पर अब 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की रोपाई, सिचाई और अन्य कृषि कार्यों में कोई समस्या न हो, इसके लिए कृषि फीडरों के निर्धारित 10 घंटे विद्युत आपूर्ति के शिड्यूल में 2 घंटे और बढ़ाकर अब 12 घंटे बिजली दी जायेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कम वर्षा होने से किसानों को धान की रोपाई और अन्य कृषि कार्यों को करने तथा फसल को सूखने से बचाने के लिए परेशानी हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में जहां फसलों की सिंचाई के लिए नहरे नहीं हैं तथा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हो रही है, वहां पर किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कृषि पोषकों को मिल रही बिजली में 2 घंटे की बढ़ोत्तरी की गयी है। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये है कि प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि फीडरों को 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। साथ ही सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता (वितरण) व मुख्य अभियन्ता (पीएमसी) द्वारा नियमित इसकी मॉनीटरिंग की जाए। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति सामान्य होने पर निर्धारित रोस्टर के आधार पर ही विद्युत आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों की सिंचाई की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों की ओर से कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति में बढ़ोत्तरी की लगातार मांग की जा रही थी।

दुबई में फंसे यूपी के नागरिकों की त्वरित सहायता के लिए मंत्री एके शर्मा ने पीएम को दिया धन्यवाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) में फंसे उप्र के नागरिकों की मदद की है। उन्होंने यूएई में फंसे प्रदेश के मऊ एवं कानपुर देहात के 2 नागरिकों की त्वरित सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से सम्पर्क कर उनकी सुरक्षा और शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए आग्रह किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री के आदेश पर उनके कार्यालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय काउंसलेट को निर्देश दिये गये। इस पर भारतीय काउंसलेट ने वहां फंसे इन भारतीय नागरिकों से तुरंत संपर्क किया और उनसे उस स्थान पर जाकर मुलाकात की। जहां पर उन्हें रखा गया था। इस त्वरित कार्यवाही से संदिग्ध ट्रवेल एजेंटों के चंगुल में फंसे प्रदेश के नागरिकों को काफी राहत मिली है। जिसकी मऊ और कानपुर जिलों में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही।

शर्मा ने बताया कि मऊ जिले के रहने वाले विशाल सिंह पुत्र संजय सिंह और कानपुर देहात ज़िले की सर्वेश कुमारी पत्नी मनोज यादव अच्छे और बेहतर जीवन की तलाश में दुबई गए। लेकिन उनके एजेंटों एवं संभावित नियोक्ता द्वारा धोखा दिया गया। इतना ही नहीं उनके नियोक्ता ने भारतीय नागरिकों पर दबाव डालकर उनसे ऋण के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और उनके नाम पर स्वयं ऋण प्राप्त कर लिया। इस कारण यह लोग दुबई में कानूनी एवं आर्थिक मामलों के केस में फंस गए और उनको कोई नौकरी भी नहीं मिली। ऋण न चुका पाने के कारण उनके दुबई छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अत: वह भारत वापस भी नहीं आ सकते थे। उन्होंने बताया कि अब से कुछ दिन पहले मऊ निवासी विशाल के पिताजी ने मुझसे इस विषय में संपर्क किया।

उन्होंने बताया कि दुबई में उनके बेटे और एक महिला का जीवन संकट में है। इस समस्या को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करके उनसे इस मामले में सहायता करने का आग्रह किया। शर्मा ने बताया कि भारतीय काउंसलेट ने इन भारतीय नागरिकों को अपने एजेंट एवं नियोक्ता के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने में भी सहायता की। भारतीय काउंसलेट ने इस मामले को विदेशी मामलों के मंत्रालय, दुबई, के समक्ष भी रखा है और इस संबंध में उनके सामने औपचारिक निवेदन भी प्रस्तुत किया है।

बजट में चीन को आयात शुल्क में भारी कटौती दिए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

● देशवासी जानना चाहते हैं, आरएसएस, बीजेपी और एनडीए सरकार का चाइना के साथ क्या रिश्ता: डॉ. सीपी राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मीडिया विभाग चेयरमैन पूर्व मंत्री डा.सी पी राय ने कहा कि 'स्टार्ट अप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' का शिगूफा छोड़ने वाली मोदी सरकार ने बेतहासा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के दौर में पेश किये गये बजट में चीन के साथ अत्यंत नरमी बरतते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट पर 'आयात शुल्क' या तो समाप्त कर दिया है या ना के बराबर कर दिया है। डॉ. राय ने कहा कि देशवासी जानना चाहते हैं मौजूदा 'भारत चाइना सीमा विवाद' के बीच आरएसएस, बीजेपी और एनडीए सरकार का चाइना के साथ क्या रिश्ता है? एनडीए सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. राय ने कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि इस आर्थिक लाभ का प्रयोग चीन भारत के ही खिलाफ हमारी सीमाओं पर कब्जे और षड्यंत्र के लिए कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण में स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2023-24 में भारत व चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118 अरब डॉलर के करीब है। जिसमें भारत से चीन को होने वाला निर्यात सिर्फ तकरीबन 17 अरब डॉलर का है। इस तरह से भारतीय व्यापार घाटा 84 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। वहीं आज चीन हमारी भारतीय सीमाओं के अंदर करीब 6000 किलोमीटर जमीनों पर जबरन कब्जा भी कर चुका है, जहां पर चीन पुल सड़क बना रहा है और बस्तियां बसाने के साथ ही अपनी फौजी छावनी बनाने में लगा हुआ है। डा. राय ने कहा कि मौजूदा बजट में चीन को आयात शुल्क में भारी कटौती दे कर भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया गया है।

गुड गवर्नेंस को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

अपनी तहसील में ही निवास करें एसडीएम व तहसीलदार

● मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य यह है कि उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत उसका निराकरण करने का प्रयास करें। इससे न सिर्फ अधिकारियों की, बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव की ओर से मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार जनसमस्याओं का ससमय निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें। इस निर्देशन व पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं निवास करें। तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है। संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं, वहीं निवास करें। सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर 7 दिन के अंदर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे।

उन्नत किस्मों की पहचान कर किया जा रहा मानकीकरण: डॉ. संजय सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) द्वारा बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिसमें महानिदेशक डॉ. संजय सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियो को परिषद की हालिया उपलब्धियों और आगामी रणनितियों पर प्रकाश डाला। डॉ. सिंह ने विश्व बैंक पोषित सोडिक लैण्ड परियोजना और कृषि विविधीकरण परियोजना के प्रभावी परिणामों का उल्लेख किया, जो उपकार के माध्यम से संचालित की गई थीं। उन्होंने बाह्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित आत्मा परियोजना, मैक्रोमोड परियोजना और आर.के.वी.वाई. की गतिविधियों पर भी चर्चा की। राज्य औद्यानिक मिशन परियोजनाओं के संचालन में उपकार के योगदान का भी जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि परिषद की स्थापना जून 1989 में द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत की गई थी। अनुसंधान के क्षेत्र में उपकार द्वारा किये जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर क्षेत्र विशेष की शोध प्राथमिकताओं पर परियोजनाओं का सतत वित्त पोषण किया जा रहा है।

हाथरस हादसे से सबक लेकर डीजीपी ने भीड़ प्रबंधन को लेकर जारी की एसओपी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीते दिनों हाथरस जिले में प्रवचन के दौरान भगदड़ मचने से हुई हृदयविदारक घटना में सौ से अधिक लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। हाथरस से पहले भी लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी और प्रयागराज (इलाहाबाद रेलवे स्टेशन) आदि जिलों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेते हुए राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने ऐसे कार्यक्रमों के दौरान भीड़ नियंत्रण और पुलिस व्यवस्थापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित कर दी है। डीजीपी ने बुधवार को फील्ड में तैनात पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एसओपी जारी करते हुए इसमें निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: पालन करने के आदेश दिए हैं।

एसओपी में जिन प्रमुख बिन्दुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं उनमें किसी भी भीड़ जनित आपदा के दृष्टिगत जनपद/ कमिश्नरेट/ परिक्षेत्र और जोन स्तर पर एक एकीकृत प्रणाली विकसित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों तथा स्थानीय पुलिस के स्तर पर नियमित रूप से उसे विकसित व अपडेट किया जाए। आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त विभागों को सम्मिलित करते हुए नियमित पूर्वाभ्यास किया जाए। स्थानीय परिस्थितियों का समावेश करते हुए उक्त योजना को नियमित रूप से प्रतिवर्ष अपडेट/ अपग्रेड किया जाए।

जनपद की पुलिस लाइन में विशेष आयोजनों में सुरक्षा, भीड़ नियन्त्रण तथा सुव्यवस्थित यातायात संचरण के दृष्टिगत आवश्यक संसाधनों व उपकरणों की नियमित देखरेख व कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। सभी स्तरों पर समस्त राजकीय व निजी अस्पतालों को चिन्हित कर लिया जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय मजिस्ट्रेट व अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुमतिकर्ता अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस द्वारा यह पूर्णरूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्यक्रम स्थल पर किसी प्रकार का कोई खतरा विद्यमान नहीं है तथा उस स्थल पर आगन्तुकों का सुरक्षित आवागमन सम्भव है। विशिष्ट अतिथियों के आगमन का मार्ग, जोन सेक्टर स्कीम प्रबन्धन तथा कन्टिनजेन्सी प्लान के सम्बन्ध में कार्ययोजना पहले से बना ली जाए। कार्यक्रम से सम्बन्धित थ्रेट प्रेसकेप्शन के अनुसार अन्य सम्भावित खतरों यथा-अग्निजनित दुर्घटना, विद्युत जनित दुर्घटना, मार्ग दुर्घटना, श्वास अवरोध आदि के सम्बन्ध में समुचित आकंलन करते हुए आपात कालीन योजना के अनुसार यथोचित व्यवस्थापन हो। समस्त सम्बन्धित विभागों यथा- नोडल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सुरक्षा एजेन्सी, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, एयरपोर्ट सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त एजेन्सी तथा प्रोटोकॉल / जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाए। आयोजन के दौरान प्रबन्धन व व्यवस्थापन एसओपी में जिन बिन्दुओं को इंगित किया गया है उनमें राजपत्रित अधिकारी व स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रभारी नियुक्त किया जाना। ड्यूटी पर लगाये गये समस्त पुलिस, पीएसी, सीएपीएफ, अग्निशमन अधिकारियों की समुचित ब्रीफिंग व डीब्रीफिंग। पब्लिक एड्रेस सिस्टम यथा- लाउड हेलर, आदि का प्रयोग करते हुए ड्यूटी पर लगाये गये समस्त बल को सक्रिय किया जाना।

अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था करना। अफवाह फैलाने वाले तथा असामाजिक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखा जाना। आवश्यकतानुसार पुलिस बल के साथ-साथ विभिन्न अनुपूरक बलों यथा- सिविल डिफेन्स, एसपीओ, होमगार्ड, ग्राम चौकीदार, पुलिस मित्र, एस-10 सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मियों व सी-प्लान ऐप के सदस्यों आदि का भी समुचित प्रयोग। भीड़ नियंत्रण योजना के अनुरूप व्यक्तियों व वाहनों का आवागमन तथा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना। श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्राप्त तथा विशिष्ट अतिथियों के आवागमन का मार्ग आम जनमानस के मार्ग से पृथक रखा जाना अथवा उनके आवागमन का समय अलग- अलग रखा जाना। जनपदीय अभिसूचना तन्त्र, सोशल मीडिया सेल तथा कण्ट्रोल रूम को सतर्क करते हुए सोशल मीडिया पर विशेष रूप से निगरानी रखा जाना। इस संबंध में किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना।

वृक्षारोपण महाभियान के दौरान रोपित एक भी पौधा सूखना नहीं चाहिए: डॉ. अरुण कुमार सक्सेना

लखनऊ। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जन्तु उद्यान राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरूण कुमार सक्सेना ने दिनांक 20 जुलाई को रोपित हुए 36.50 करोड़ से अधिक पौधों के स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अपर्याप्त वर्षा के कारण पौधों की सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही रोपण स्थलों की सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया जाये। विभागीय अधिकारी रोपित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करते रहें। डॉ. सक्सेना बुधवार को वन विभाग के मुख्यालय स्थित पारिजात हॉल में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मुख्य वन संरक्षक व प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण महाभियान के दौरान रोपित पौधे हर हाल में जीवित रखे जाने चाहिए। यदि कोई पौधा सूखता है तो उसके स्थान पर दूसरे पौधे का रोपण कराया जाये। सड़कों के किनारे जो पौधे रोपित हुए हैं उनकी सुरक्षा और सिंचाई का नियमित प्रबंध होना चाहिए।

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024

जिला सड़क सुरक्षा समितिः डीएम ने ली बैठकए दिए निर्देश

● चालक परिचालकों के लिए लगवाएं नेत्र परीक्षण शिविर ●भीड़ भाड़ वाले एरिया में जमीन चिन्हित कर पार्किंग को ईओ बनाए व्यवस्थित ●मानक के अनुरूप संचालित हो स्कूली वाहनए कराए स्कूली वाहनों का फिटनेसः डीएम

लखीमपुर खीरी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं जाने, यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक का संयोजन, संचालन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड (तृतीय) के अधिशाषी अभियंता अनिल कुमार यादव और एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने जिले में घटित दुर्घटनाओ का विश्लेषण करते हुए नए ब्लैक स्पॉट एवं बनरेबल लोकेशन चिन्हित करने के निर्देश दिए।

जेब्रा क्रॉसिंग का रंग जहां हल्का पड़ गया, वहा पुनः पेंट करवाएं। परिवहन विभाग ट्रांसपोर्टर के समन्वय से चालक परिचालकों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर लगवाएं। ईओ को निर्देशित किया कि भीड़.भाड़ वाले इलाकों में उपयुक्त जमीन चिन्हित कर पार्किंग को व्यवस्थित करने का काम करें। सीजन के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चीनी मिल वाहनों में रिफ्लेक्टरए लाल कपड़ा अनिवार्य रूप से लगाया जाए।

डीएम ने निर्देश दिए कि स्कूली वाहन मानक के अनुरूप होने पर ही संचालित हो। बीएसए .डीआईओएस विद्यालयों से समन्वय करते हुए शत प्रतिशत वाहनों का फिटनेस सुनिश्चित कराए। बैगर फिटनेस वाले वाहनों का संचालन कदापि न हो। जिले में जहां पर घुमावदार स्थान तथा ब्लाइंड स्पॉट हैए वहां से सौ मीटर पूर्व में साइनेज लगाने के दिशा निर्देश दिया। सुझाव दिया कि लिंक मार्ग, मुख्य मार्ग को कनेक्ट करने वाले स्थानों के पास संकेतांक के साथ मानक के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। बैठक में डीएम.एसपी ने जनपद में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषणए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (वनरेबल लोकेशन), स्कूली वाहनों के मानकों अनुरूप होने पर ही संचालन, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा सड़कों की मरम्मत/गड्ढामुक्ति, वर्षाऋतु से पूर्व कास ड्रेनेज वर्क (पुल, पलिया, रपटा आदि) एवं तटबंध की सड़कों की सुरक्षा संबंधी कार्यवाहीए विभिन्न चीनी मिलों पर वाहन प्रबन्धन की चर्चा, सकरे/जर्जर सेतुओं के संबंध में चर्चा, शहरी क्षेत्र में चौराहेध्तिराहों पर स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण एवं रोड साइड सुधार, सड़क सुरक्षा एवं गुड समेरिटन श्लाए के प्रचार.प्रसार एवं जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों की योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड तृतीय (पीडब्लूडी) अनिल कुमार यादव ने बताया कि जिले में वर्ष 2024 में मात्र 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैए जिनका स्वामित्व निर्धारण किया जा चुका है। जिस पर सुधारात्मक कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।

डीएम ने अफसरों की टीम संग तीन परिषदीय विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण

लखीमपुरखीरी। परिषदीय विद्यालयों की शिक्षण कार्य की गुणवत्ता, शिक्षक शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पुस्तक एवं ड्रेस वितरण, आधार फीडिंग, विद्यालय परिसर की साफ सफाई का जायज़ा लेने के उद्देश्य से बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अफसरों की टीम संग ब्लॉक लखीमपुर के तहत संविलियन विद्यालय आधाचाट, पीएस चिमनी व यूपीएस पिपरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से डीपीआरओ विशाल सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी, बीडीओ (सदर) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। डीएम ने शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में भी बच्चों से ही पूछताछ की। हेडमास्टर ने डीएम को विद्यालय में नामांकित बच्चों के सापेक्ष उपस्थित बताई। कक्षा में छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

सभी के विकाश से ही गांव का विकास संभवः मीणा

● संपूर्णता अभियान को लेकर पीरामल फाउंडेशन की ओर से बैठक आयोजित

फतेहपुर। किसी भी जेल का विकास तभी हो सकता है जब हम मिलकर किसी भी काम को आगे बढ़े सरकार की ओर से जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें पीरामल फाउंडेशन की अहम भूमिका है। जिले में चल रही संपूर्णता अभियान में भी फाउंडेशन की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। लगभग सभी पंचायत के प्रधान से भी सहयोग मिल रहा है। बातें मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा ने पीरामल फाउंडेशन द्वारा आयोजित संपूर्णता अभियान को लेकर हुई बैठक में कही। इस मौके पर 40 पंचायत के प्रधानों और सचिवों के साथ स्वास्थ्य पंचायत और उसके घटकों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में जिला विकास अधिकारी वीडियो प्रमोद सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी और सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, एडीपीआरओ, पिरामल से संजय सिंह, रोहिनी, स्मिता सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे।

मीणा ने ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए गांव में आयुष्मान कार्ड सीएचएसएनडी और छोटे-छोटे उद्योगों को सभी सदस्यों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया उसके अलावा प्रधानों को आंगनबाड़ी गांव स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस और स्कूल का दौरा करने की सलाह दी ताकि सभी कार्यक्रमों का बेहतर कार्य सुनिश्चित हो सके। बैठक में सुजानपुर की प्रधान मिलता पटेल और टांडा के प्रधान ने अपनी सफलता की कहानियों को सरकारी अधिकारियों के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वीएचएसएनडी सत्र में 100 प्रतिशत परसेंट प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित की। बैठक में स्वास्थ्य पंचायत की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की गई ग्राम पंचायत के प्रधानों ने अपनी पंचायत में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने के विभिन्न उपायों पर अपने अनुभव साझा किया प्रधानों ने बताया कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन इकाइयों को शक्ति रूप से शामिल कर स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों टीकाकरण कार्यक्रम और पोषण सत्रों का सफल आयोजन किया है।

महिला ने यमराज के पंजे से बचाया अपना सुहाग

फतेहपुर। सुहाग बचाने के लिये एक महिला ने अपनी जान की परवाह किये बिना मौत के पंजे से अपने पति को वापस लाते हुए अपने ही सुहाग की रक्षा कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया। किशनपुर थाना क्षेत्र के इटरौरा गांव निवासी पति पप्पू-पत्नी केसिया में मामूली बात को लेकर आपस मे झगड़ा हो गया। बात बिगड़ने पर पति हाई टेंशन की लाइन पर चढ़ गया। काफी देर मान मनव्वल के बाद भी जब पति टावर से नीचे नही उतरा तो पत्नी भी टावर पर चढ़ गई और पति को समझाकर आखिर नीचे उतरने में कामयाब हो गयी। पति और पत्नी के नीचे उतरने के बाद मौजूद गांव वालो के साथ साथ विद्युत व विद्युत विभाग के अफसरों ने भी राहत की सांस ली। महिला के जज्बे की हर जगह जमकर सराहना हो रही है।

किशनपुर थाना क्षेत्र के संगोलीपुर मंडैयन गांव निवासी पप्पू निषाद अपनी ससुराल परान का डेरा मजरा लोधौरा गया था जहां किसी बात को लेकर पत्नी केसिया देवी से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद पप्पू ने जमकर शराब पी और नशे में इटरौरा बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया और इन्सुलेटर पर बैठ गया। विद्युत लाईन चालू देखकर पत्नी केसिया पहले तो पति को समझाती रही इसी बीच गांव के और लोग भी आ गये और पप्पू को समझाने लगे। उधर पत्नी केसरिया भी रोती चिल्लाती मनुहार करती रही। काफी देर हाई वोल्टेज ड्रामा देख राहगीरो ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी काफी समझाती रही लेकिन पप्पू उतरने का नाम नही ले रहा था। शराब के नशे की हालात में पति को इंसुलेटर पर बैठा देखकर पत्नी केसिया से रहा नही गया और वह भी टावर पर चढ़ गई और पति पप्पू को समझाने लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ खागा सीओ बृजमोहन राय भी मौके पर पहुँचे व उतारने की कोशिश में लग गये।

मुख्यमंत्री से मिल विधायक ने अवैध भट्ठों के संचालन की करी शिकायत

● हिन्दू बहुल परिसीमित वॉर्डों में विकार्य कार्यों में अनदेखी का चेयरमैन पर लगाया आरोप

सीएम से मिल शिकायती पत्र सौंपती विधायक

संडीला (हरदोई)। क्षेत्रीय विधायक ने क्षेत्र में चल रहे अवैध भट्ठों के संचालन और नगर पालिका परिषद द्वारा हिन्दू बहुल वॉर्डों में विकास कार्य न कराने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से मिल लिखित शिकायत की है। क्षेत्रीय विधायक अलका अर्कवंशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके कार्यालय में 22 जुलाई को भेंट करके उनसे लिखित रूप से शिकायत की कि विधानसभा क्षेत्र संडीला में लगभग 100 से अधिक ईंट भट्ठे संचालित हैं। इन ईंट भट्ठों के द्वारा पहले तो आसपास के इलाकों से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया गया जिससे उन क्षेत्रों में विशेष रूप से वर्षा के मौसम में भीषण जलभराव के कारण तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैंए जिनके शिकार ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा इन भट्ठों की चिमनियां निर्धारित मानकों के अनुरूप ऊंचाई की नहीं हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है और लोग सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा इन भट्ठों पर ईंट की सप्लाई लेकर अंधाधुंध भागती ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रकों के कारण क्षेत्र की सड़कों का भी कचूंमर निकाल दिया गया है। इनमें से कई सड़कें उन्होंने स्वंय मुख्यमंत्री से मिल धनराशि जारी कराकर विभिन्न विभागों को दिलाई थीए जिनसे इनका निर्माण हुआ था। उन्होंने इन अवैध भट्ठों को तत्काल बंद कराने की मांग शिकायती पत्र में की। मुख्यमंत्री योगी से की दूसरी शिकायत में विधायक अलका अर्कवंशी ने कहा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा परिसीमन वाले नवीन हिन्दू बहुल वॉर्डों में विकास कार्यों के प्रति पूर्ण उपेक्षा बरती जा रही हैए जबकि उनसे हर वर्ष मनमाना टैक्स वसूला जाता है। उन्होंने नगर पालिका का दोबारा परिसीमन कराने और वॉर्डों में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

एएनएम के गलत इलाज से जच्चा-बच्चा की मौत एफआईआर दर्ज

फतेहपुर। सरकारी अस्पताल में सेवारत एएनएम के गलत इलाज के चलते जच्चा व बच्चा की मौत हो गई। प्रसूता के पति ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग किया है। नई तहसील के निकट स्थित पाल नगर निवासी कमलेश कुमार की पत्नी सोनी देवी 28 वर्ष 08 माह की गर्भवती थी। घर के पास स्थित श्रद्धा मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीने के दौरान कोराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एएनएम गीता उत्तम के सम्पर्क में आने व प्रसव कराने की बात कही गयी। 22 जुलाई को प्रसूता सोनी देवी गीता उत्तम को दिखाने पहुंची जिस पर एएनएम गीता उत्तम ने प्रसूता की हालत नाजुक होने व तत्काल भर्ती करने को कहा। प्रसूता के पति कमलेश ने बताया कि एएनएम के कहने पर श्रद्धा मेडिकल स्टोर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 23 जुलाई को एएनएम ने आकर बताया कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है।

क्विक न्यूज

रिक्शाचालक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत

फर्रुखाबाद। बीती रात ट्रेन की चपेट में आनें से रिक्शा चालक की मौत हो गयी। पुलिस नें शव क पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लुकटपुरा निवासी 35 वर्षीय रंजीत उर्फरिकू बीती रात ग्राम नगला अमृत के निकट पोल संख्या 1307/7 व 1307/8 के बीच ट्रेन की चपेट में आ गया। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए निकले तो रंजीत का शव रेलवे के निकट पड़ा मिला। सुबह परिजनों को सूचना मिली। रंजीत फर्रुखाबाद में रिक्शा चला कर परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक की पत्नी अर्चना आदि परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। बीती रात रंजीत नशे की हालत में घर से विवाद करके निकला था। दारोगा चमन सिंह नें शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

नाली में गिरने से शराबी की मौत

फर्रुखाबाद। शराबी की नाली में गिरने से मौत हो गयी। परिजनों में कोहराम मच गया। राजेपुरथाना क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर सोमवंशी 32 वर्षीय दुर्वेश पुत्र मंगली शराब पीने का आदी था। बीती रात वह अपनी ससुराल पलिया हरदोई से घर वापस लौटा था। उसने शराब के नशे में पड़ोसी सोनू पुत्र नेकराम से गाली-गलौज किया। जिसके बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पंहुची। वह समझाकर लौट आयी। मंगलवार सुबह से ही वह नशे में घूम रहा था। जिसके बाद नाली में गिरने से उसकी मौत हो गयी। मृतक की पत्नी रीना व माँ मुन्नी देवी का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। दारोगा उदय सिंह बताया के तहरीर नहीं मिली है। सूचना आने पर कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

चार ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन निश्चित, एक पर्चा खारिज

फर्रुखाबाद। ग्राम पंचायत सदस्यों के उपचुनाव में नामाकंन पत्रों की जाँच में एक नामांकन पत्र निरस्त किया गया। चार के पर्चे वैध पाये गये। सहायक निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य रतनपुर पमारान के बार्ड संख्या चार सरस्वती, सबासी के वार्ड संख्या 6 से शिल्पी देवी, बार्ड संख्या 10 लज्जाराम, कमालुद्दीनपुर के वार्ड संख्या 5 से सुभद्रा के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए कमालुद्दीनपुर से मीना देवी पत्नी अमर सिंह के नाम निर्देशन पत्र में आधार कार्ड तथा फोटो संलग्न न होने के कारण निरस्त कर दिया गया। अब प्रत्येक वार्ड से एक-एक उम्मीदवार मैदान में होने के कारण इनका निर्विरोध निर्वाचित होना निश्चित हो गया है।

सर्प दंश से महिला की मौत

राठ (हमीरपुर)। बुधवार की तड़के कमरे में सो रही महिला को सर्प ने काट लिया। स्वजन इलाज के लिए पनवाड़ी तात्रिक के पास झाड़.फूंक के लिए ले गए। हालत गंभीर होने पर सीएचसी पनवाड़ी ले गए। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। स्वजनों ने राठ में आकर शव का पोस्टमार्टम कराया है। कोतवाली के मवई गांव निवासी जगतराम कुशवाहा ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन कुशवाहा (38) बुधवार की सुबह करीब चार बजे कमरे में सो रही थी। तभी उसकी दाहिने हाथ की उंगली में सर्प ने काट लिया। जिसे आनन.फानन में झाड़.फूंक के लिए तांत्रिक के पास पनवाड़ी ले गए। जहां आराम न मिलने पर उसे सीएचसी पनवाड़ी ले। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया कि उसके पिता के पास 11 बीघा जमीन है। खेती व मजदूरी कर परिवार का भरण.पोषण करता है। मृतका अपने पीछे एक पुत्र दीपकए दो पुत्री दीक्षाए दीपिका छोड़ गई है।

करंट की चपेट में आकर वृद्ध की मौत

फतेहपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में पंखे में उतर रहे करंट की चपेट में आ जाने से 61 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर गांव निवासी रविकरन का पुत्र पिथरी लाल मंगलवार की रात लगभग नौ बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। तभी पंखा चालू करते समय वह करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत

फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के औरेई गांव निवासी प्रकाश नारायण की पत्नी सविता देवी अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गौरइया माता मंदिर दर्शन के लिए गई थी। वापस लौटते समय जैसे ही वह बाइक से चलने लगी तभी तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को विच्छेदन गह भेज दिया।

युवक ने फांसी लगाकर दी जान

फतेहपुर। ललौली थाना क्षेत्र के ग्राम ओती में मानसिक तनाव के चलते 40 वर्षीय युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। ओती गांव निवासी राम आसरे का पुत्र अशोक सिंह ने मंगलवार की देर शाम मानसिक तनाव के चलते घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया।

एक दर्जन ने अपहरण करके जरदोजी कारीगर को बुरी तरह पीटा, एक गिरफ्तार

फर्रुखाबाद। जरदोजी कारीगर को घर से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया गया। जिसके बाद हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बेहरमी से पिटाई कर दी। पुलिस नें पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली के मोहल्ला गढ़ी अब्दुल मजीद खां निवासी सलीम पुत्र नसरुद्दीन जरदोजी कारीगर है। सलीम ने दर्ज करायी गयी एफआईआर में कहा है कि 21 जुलाई को अपने परिवार के साथ वह घर पर टीवी देख रहा था। उसी दौरान सुनार वाली गली निवासी जीतू यादव पुत्र राकेश, सूरज यादव, अन्नू तिवारी व टीना यादव निवासी निवासी कटरा बु अली खां, दीपू गुप्ता निवासी तिकोना मंडी, सिक्कू यादव बजरिया फिल्ड, अमित चौरसिया निवासी सुनार वाली गली व 8 लोग अज्ञात आ गये। पत्नी रौनक, भाभी अच्छी बेगम के साथ मारपीट की और सलीम का अपहरण करके आरोपी दीपू गुप्ता के घर तिकोना लेकर गये।

रेलवे क्रासिंग के ऊपर गाटर रखे जाने का काम शुरू हुआ

रूरा, कानपुर देहात। कडी मशक्कत व मैराथन प्रतीक्षा के बाद रूरा कस्बे की पश्चिमी क्रासिंग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज की दिल्ली-हावडा रेलवे लाइन के ऊपर भारी क्रेन मशीनों के माध्यम से गाटर रक्खे जाने का काम शुरू किया गया। रेलवे लाइन सीमा पर गाटर रक्खे जाने के दौरान चैयरमैन रामजी गुप्ता सहित भारी संख्या में स्थानीय व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।

रूरा कस्बे में उत्तरी व दक्षिणी दिशा के मध्य में स्थित दिल्ली-हावडा व डीएफसी लाइनों पर करीब साढे चार वर्षों से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम ने रेलवे सीमा के बाहर दोनों ओर करीब 90 फीसदी कार्य पूरा कर लिया है। रेलवे लाइनों के ऊपर रेलवे को निर्माण कार्य करना है। रेलवे लाइनों के ऊपर गाटर रक्खे जाने के लिये चार-पॉच दिन पूर्व ही भारी अत्याधुनिक क्रेन मशीनें आ गयी थी, बुद्धवार को रेलवे द्वारा ब्लाक मिलने पर गाटर रक्खे जाने का काम शुरू हुआ, बुद्धवार को दो गाटर रक्खे गये, शीघ्र ही शेष गाटर रख कर पुल के अवशेष कार्य कराये जायेगे, गाटर रक्खे जाने के बाद पश्चिमी केबिन क्रासिंग को भी आवागमन के लिये खोलने की शीघ्र सँभावना बलवती हो चुकी है। गाटर रक्खे जाने के दौरान डीएफसी, रेलवे के अभियन्ता, अधिकारी सहित रूरा नगर पँचायत के चैयरमैन रामजी गुप्ता, सभासद हिमाँशू गुप्ता, आशुतोष मिश्रा, सुरेश कुमार, नगर पँचायतकर्मी राजेश रावत, सैनूर अहमद सहित भारी सँख्या में स्थानीय व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।

थाना अध्यक्ष समस्त पुलिस स्टाफ ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी को किया घायल

बांदा। प्रदेश के बांदा जनपद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला बांदा के तत्वाधान में कल रात्रि तिंदवारी थाने में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी के साथ लव जेहाद प्रकरण को लेकर बातचीत के दौरान तिंदवारी थाना अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी के साथ अभद्रता मारपीट की घटना के विरोध में प्रांतीय अधिकारियों की मौजूदगी में सैकड़ो की संख्या में मौजूद पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का रामलीला मैदान में एकत्रीकरण हुआ तत्पश्चात प्रांतीय पदाधिकारी के नेतृत्व में रामलीला मैदान प्रांगण से सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पैदल कूच किया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और अंदर घुसने को लेकर प्रशासन से गहमागहमी भी हुई तब अंदर प्रवेश मिला कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार नारेबाजी करते हुए तिंदवारी

थाना अध्यक्ष पुलिस के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया तदोपरांत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल द्वारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर तिंदवारी थाना अध्यक्ष सहित समस्त स्टाफको निलंबित करने तथा उनके विरोध आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से तिंदवारी थाने के थाना अध्यक्ष सहित समस्त पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा उनके विरोध आपराधिक मुकदमा आज ही पंजीकृत करने का आश्वासन दिया गया है जांच 3 दिवस के अंदर पूरी कर निलंबन की कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की है कि हम लोग तब तक बांदा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे जब तक संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाता और हमें थ्स् की प्रति नहीं प्राप्त हो जाती साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि यदि हमारी जायज मांगों पर हिला हवाले की जाती है तो संगठन पुनरू तीन दिन बाद जोरदार आंदोलन को बाध्य होगा।

नाबालिग से झूठे बयान दर्ज कराने पर महिला एसआई व चौकी इंचार्ज पर दर्ज हुआ मुकदमा

कानपुर देहात। थाना सजेती क्षेत्र के एक मामले अनुसूचित जाति की एक 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण व रेप के आरोपियों के साथ ही उन्हें बचाने में व रेप पीड़िता के जबरन झूठे बयान लिखने वाली थाना सजेती की महिला उप निरीक्षक व बीबीपुर चौकी इंचार्ज के खिलाफ न्यायालय ने मुकद्दमा पंजीकृत कर विवेचना के आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की न्यायालय ने पीड़िता पक्ष की तरफ से धारा 156;3द्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रार्थना पत्र पर पारित किए है। यह जानकारी पीड़िता पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने दी।

अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान

अधिवक्ता जितेन्द्र चौहान ने बताया कि पीड़िता व उसके पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप अनुसार लगभग 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को आरोपीगण आदर्श सचान उर्फ केशव शिव बदनएराजकिशोर व राजकुमार 23.4.2024 को रात उसके घर से जबरियां उठा कर अपहरण कर ले गए और उसके साथ आरोपी आदर्श सचान दो अज्ञात लोगों के साथ मिल जंगल में रेप करता रहा।जिसकी रिपोर्ट थाना सजेती में लिखने हेतु पीडिता के पिता ने प्रार्थना पत्र दिया किन्तु थाना पुलिस ने आरोपियों से मिल रिपोर्ट न लिख थाना सजेती की पूजा नाम की पुलिस सब इंस्पेक्टर व बीबीपुर चौकी इंचार्ज विनोद यादव ने पीड़िता को जातिसूचक गलियां देते व धमकाते हुए उसके जबरन झूठे बयान लिख बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर नारी निकेतन भिजवा दिया। पीड़िता ने नारी निकेतन से उसके माता पिता की सुपुर्दगी में आने पर उसके अपहरण के बाद की व उसके साथ लम्बे समय से हो रहे यौन उत्पीड़न की जानकारी अपने माता पिता को दी।जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखे जाने हेतु थानाध्यक्ष सजेती व पुलिस आयुक्त कानपुर को प्रार्थना पत्र देने के बवाजूद मुकदमा न लिखे जाने पर अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

विद्यायिका ने कार्यकर्ताओं का कोतवाली से कराया परिचय

● कोतवाली में बैठक लेकर सुनी भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्यायें

कार्यकर्ताओं को कोतवाल से परिचय करातीं विद्यायिका।

गुरसहायगंज (कन्नौज)। बीते काफी समय से विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी समस्याओं को पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से न लेनें की शिकायत को संज्ञान में लेकर छिबरामऊ विद्यायिका अर्चना पाण्डेय नें स्थानीय कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार दुवे के साथ बैठक लेते हुये कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। साथ ही उनकी समस्यायें सुनी और निस्तारण के लिये निर्देर्शित किया। पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को अनसुनी किये जानें से आहत भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां किया था। जिसपर बुधवार को स्थानीय कोतवाली परिसर में छिबरामऊ विद्यायिका अर्चना पाण्डेय नें प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार दुवे से परिचय कराया साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुननें व निस्तारण करनें के निर्देश दिये। वरिष्ठ भाजपा नेता रामकुमार पाठक, भाजपा नगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र कौशल, पूर्व नगर अध्यक्ष दीपू शर्मा, शिवमराज वर्मा, नीरज मिश्रा, डा. शरद दुवे, विजय दुवे, सुमित सक्सेना, भूरा कठेरिया, विकास गुप्ता, राकेश तिवारी, अनुराग गुप्ता, अजीत सिंह वर्मा, दीपक गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, संजीव गुप्ता उर्फ टीटू सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गैर मान्यता प्राप्त मदरसो की जांच के नाम पर की खाना पूरी

● शासन के आदेश का नही किया गया पालन, मदरसों की वित्तीय सहायता कहा से प्राप्त होती है न दे सके संचालक कोई जवाब

मौदहा (हमीरपुर)। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित व उज्वल बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी जिलाधिकारीयों को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिये थे जिस के सम्बन्ध में हमीरपुर मे जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है एसडीएम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लेकिन जब आज मौदहा क्षेत्र में जांच की गयी तो उस में उपजिलाधिकरी मौजूद नही रहे उनकी जगह नायब तहसीलदार व उनके साथ तीन सदस्यीय टीम के अतिरिक्त मदरसों के अध्यापक मौजूद रहे जिससे जांच प्रभावित होना स्वाभाविक है।

बुधवार को की गयी छह मदरसों की जांच मे कुछ छात्रों को छोड़कर ज्यादातर छात्रों का किसी सरकारी स्कूल में प्रवेश नही कराया गया जो शासन के आदेश की खुली अवहेलना है। आधा दर्जन मदरसे बिना पंजीकरण के संचालित हैं, फैजाने बदरुल आलिया चिश्तिया निजामी मदरसा कम्हरिया, जामिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसा बड़ा चौराहा कम्हरिया रोड, दाता गरीब नवाज मदरसा मकतब कमरिया रोड, फैजाने करीमिया अरबिया मदरसा चौधराना मौदहा, दावते इस्लामिया मदरसा कजियाना मौदहा व मदरसा माहिर उलूम काशीराम कॉलोनी छमोली रोड बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाए गए किसी भी मदरसे में न कोई रिकार्ड है और न ही पंजीकरण और न ही बैंक खाता आदि जबकि मदरसों में देश विदेश से फंडिंग होती है जिसका कोई रिकार्ड मदरसा संचालक नही दिखा सके। मदरसा शेख अब्दुल कादिर जीलानी कम्हरिया रोड मौदहा मौलाना सिद्दीक अमद एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी मौदहा हमीरपुर के अन्तर्गत अवैध रूप से चल रहा है उक्त संस्था का 1997 में सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज एंव चिटस झांसी में रजिस्टर्ड करायी गयी थी जिस का नवीनीकरण भी नही है। उक्त संस्था के नाम सन 1998 में रागौल में भूमी खरीदी गयी थी और 2010 में संस्था की भूमी पर लगभग 50 लाख रू की लागत की बिल्डिंग बनाई गयी।

कानून की जानकारी न होना उसे तोड़ने का बहाना नहीं हो सकता है : बंबई उच्च न्यायालय

भाषा। मुंबई

प्रतिबंधित सामग्री घोषित किए जा चुके एक रसायन का बिना जरूरी प्रमाणपत्र के कथित रूप से निर्यात करने को लेकर एक दवा कंपनी के निदेशक के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून की जानकारी नहीं होना उसे तोड़ने का बहाना नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि इस अनभिज्ञता को बचाव के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए तो कानून प्रवर्तन मशीनरी ठप्प पड़ जाएगी। विवालविता फार्मास्यूटिकल्स नामक एक कंपनी के निदेशक अजय मेलवानी ने उच्च न्यायालय से मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत 2019 में दर्ज की गई प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध किया था।

अपनी अर्जी में आरोपी ने यह दावा करते हुए इस मामले को खारिज करने का अनुरोध किया कि 2018 में जारी की गई अधिसूचना में संबंधित रसायन को प्रतिबंधित सामग्री की सूची में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उनकी कंपनी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके निर्यात से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने 22 जुलाई को यह अर्जी खारिज कर दी और यह कहते हुए मामला रद्द करने से इनकार कर दिया कि यह स्थापित कानूनी रुख है कि कानून की जानकारी नहीं होना किसी आपराधिक आरोप के सिलसिले में बचाव नहीं हो सकता है। हालांकि इस पीठ ने मेलवानी के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर उच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में लगाए गए स्थगन को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा, कानून की जानकारी नहीं होना उसे तोड़ने का कोई बहाना नहीं है, यह न्यायशास्त्र के आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि यदि अज्ञानता को एक बहाना मान लिया गया, तो किसी अपराध के आरोपी या उसमें शामिल व्यक्ति बस यह दावा कर अपनी जवाबदेही से बच निकलेगा कि उसे संबंधित कानून की जानकारी नहीं थी, भले ही वह कानून तोड़ने के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ क्यों न हो। पीठ ने कहा कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि दवा उत्पादों एवं संबंधित चीजों के आयात-निर्यात में लगी कंपनी को कारोबार से संबंधित नियमों एवं विनियमों की जानकारी नहीं है। मामला यह है कि रसायन बनाने वाली कंपनी सैम फाइन ओ केम लिमिटेड ने मेलवानी की कंपनी विवालविता के मार्फत बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के एक इतालवी कंपनी को 1000 किलोग्राम एन-फेनइथाइल-4 पिपेरिडोन (प्रतिबंधित सामग्री) का निर्यात किया था।

एसएनडीपी का न तो भगवाकरण होने दूंगा और न ही लाल रंग में रंगने दूंगा: वेल्लापल्ली नटेसन

तिरुवनंतपुरम। भाजपा पर श्री नारायण धर्म परिपालना (एसएनडीपी) के भगवाकरण की कोशिश करने का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद एसएनडीपी महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन ने कहा है कि वह इसका न तो भगवाकरण होने देंगे और न ही इसे लाल रंग में रंगने देंगे। एसएनडीपी अच्छी खासी संख्या वाले इझावा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। एसएनडीपी योगम महासचिव ने माकपा पर पलटवार करते हुए यह आरोप भी लगाया कि वह आम आदमी को भूल गई जिसके कारण इस साल लोकसभा चुनाव में उसकी इतनी बड़ी हार हुई। नटेसन ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को तुष्ट करने के लिए माकपा जो कुछ कर सकती है, वह कर रही है और उसे तिहरा प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनके लिए पार्टी उससे भी बढ़कर कर रही है। उन्होंने दलील दी कि पार्टी के इन्हीं कृत्यों से उसके उन कार्यकर्ताओं के मन में निराशा की भावना घर कर गई जिन्होंने पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया था। वह माकपा के प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन के हाल की इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि भाजपा ने एसएनडीपी का राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया और उसका भगवाकरण करने का प्रयत्न किया। गोविंदन ने आरोप लगाया था, भाजपा की नीति जाति के आधार पर बांटने की है।

सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए, सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, एक जुलाई, 2024 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स (एआर) में रिक्तियों की संख्या 10,45,751 की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले 84,106 है।

राय ने कहा कि मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल परीक्षा में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है। कांस्टेबल के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करने की खातिर कट-ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकें (विशेषकर उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है)।

मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 67,345 लोगों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, 64,091 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि बलों के आकार की तुलना में प्रभावी रिक्तियों की संख्या कम होने के कारण ओवरसाइज का सवाल ही नहीं उठाता। मंत्री ने कहा कि कांस्टेबल पद पर जल्द भर्ती के लिए एसएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए कांस्टेबल, उप-निरीक्षक और सहायक कमांडेंट (सभी सामान्य ड्यूटी) के रैंक में भर्ती के लिए प्रत्येक को एक नोडल बल नामित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि रिक्तियों को भरने के लिए, सभी सीएपीएफ और एआर को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैर-सामान्य ड्यूटी कैडरों में रिक्त पदों के लिए समयबद्ध तरीके से भर्ती करें और पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें का समय पर आयोजन करें। जून 2022 में, सरकार ने सेना के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना में साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है और उनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है।

वाराणसी में गंगा प्रदूषण: अधिकरण ने उप्र के पर्यावरण सचिव को नोटिस जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने तीन साल के भीतर जलमल शोधन संयंत्र स्थापित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सचिव से जवाब मांगा है। अधिकरण वाराणसी में कई स्थानों पर गंगा नदी में सीवेज और घरेलू एवं अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़े जाने के मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने आठ जुलाई को एक नई रिपोर्ट दाखिल की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी नगर निगम के अंतर्गत आंशिक रूप से बंद किए गए तीन वे नाले हैं जो गंगा नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल गिराते हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य बंद नहीं किए गए नालों में चंदौली जिला पंचायत के अंतर्गत घुरहा नाला और नगर पालिका परिषद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली के अंतर्गत रेलवे नाले शामिल हैं।

रिपोर्ट के साथ संलग्न नालों की कुछ तस्वीरों पर गौर करते हुए अधिकरण ने कहा कि इनसे नालों की दयनीय स्थिति का पता चलता है, जहां वे गंगा नदी में अनुपचारित जलमल बहा रहे हैं। अधिकरण ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तीन साल के भीतर सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं तथा निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव की है। इसने कहा, उच्चतम न्यायालय ने 22 फरवरी, 2017 को उपरोक्त निर्णय पारित किया था और तीन वर्ष की समयसीमा समाप्त हो गई है। फिर भी कार्वाई पूरी नहीं हुई है।

नीतीश के फिर बिगड़े बोल: अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं होउ

भाषा। पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में अपना आपा खो बैठे और राजद की महिला विधायक रेखा देवी पर भड़कते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं होउ उनके बयान को लेकर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है... लोग जानते हैं कि उनके (नीतीश) मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने विधानसभा में जो कुछ किया है, वह सरासर एक महिला का अपमान है। जद(यू) नेताओं और राजग के अन्य गठबंधन सहयोगियों के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं का सम्मान केवल राजद और इंडिया गठबंधन के नेताओं में ही है। राजद विधायक रेखा देवी ने पीटीआई-भाषा से कहा, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में जो कुछ कहा, वह एक महिला का अपमान है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया... ए पहली बार नहीं हुआ है। हम आज यहां अपने नेता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद की वजह से हैं...नीतीश कुमार की वजह से नहीं। उन्होंने (नीतीश कुमार) ने आज (बुधवार) सदन में एक दलित विधायक का अपमान किया है। ऐसा लगता है कि उनका (मुख्यमंत्री) अपने दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं रहा।

बिहार विधानसभा में बुधवार को राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करने के लिए उठे। उस समय राजद की मसौढी से विधायक रेखा देवी कुछ कह रही थीं। सत्तर वर्षीय मुख्यमंत्री ने रेखा देवी की ओर उंगलियां दिखाते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। इन लोगों (राजद) ने किसी महिला को आगे बढ़ाया था। क्या आपको पता है कि मेरे सत्ता संभालने के बाद ही बिहार में महिलाओं को उनका हक मिलना शुरू हुआ। 2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। बोल रही हो, फालतू बात... इसलिए कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। उनके इतना कहते ही सदन में हंगामा और बढ़ गया।

एक महिला विधायक से इस तरह मुखातिब होने का विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, अरे क्या हुआ... सुनोगे नहीं... हम तो सुनाएंगे और अगर नहीं सुनिएगा तो यह आपकी गलती है। बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री से आसन को संबोधित करने का अनुरोध किया तो नीतीश ने विपक्षी सदस्यों के बारे में कहा, आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक-एक चीज को लागू कर दिया है। हम चाह रहे थे कि यह लोग समझते एक-एक चीज को।

बाद में बिहार विधानसभा परिसर में राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कहा कि हम लोगों की मांग केवल आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर थी।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पता नहीं महिलाओं को क्या-क्या बोलने लगे। महिलाओं से उन्हें प्रेम या नफरत है, यह बात हमें समझ ही में नहीं आती। इतिहास बताना शुरू कर देते हैं। अगर विजय कुमार चौधरी जी नहीं रोकते तो ना जाने वह और क्या-क्या बोल देते। इससे पहले भी नीतीश कुमार के कई बयानों को लेकर सियासी बवाल हो चुका है। पिछले साल बिहार विधानसभा में जातिगत गणना के दौरान हुए आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला पुरूष के शारीरिक संबंधों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ए टिप्पणी आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं की बढ़ रही साक्षरता और प्रजनन दर के संदर्भ में की थी।

पाक से भारत लौटी गीता ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की आठवी कक्षा, सरकारी नौकरी मांगी

इंदौर (मध्यप्रदेश)। पड़ोसी देश पाकिस्तान से वर्ष 2015 में अपने देश भारत लौटीं गीता ने आठवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है। इसके बाद 33 साल की इस मूक-बधिर महिला ने सरकार से नौकरी की मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की आठवीं कक्षा की परीक्षा में गीता को 600 में से 411 अंक मिले हैं और उन्हें सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में विशेष योग्यता भी हासिल हुई है। इंदौर की गैर सरकारी संस्था आनंद सर्विस सोसायटी , पाकिस्तान से गीता की वापसी के बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के जतन में जुटी है। संस्था के सचिव और सांकेतिक भाषा के जानकार ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बुधवार को पीटीआई-भाषा को बताया, अपने परीक्षा परिणाम से गीता बेहद उत्साहित हैं और अपने भविष्य की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं। पुरोहित के मुताबिक वीडियो कॉल पर इशारों की जुबान में बातचीत के दौरान गीता ने उन्हें बताया कि वह सरकारी नौकरी करने के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास तय की गई है। इस लिहाज से गीता इस वर्ग की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की पात्र हो गई हैं। पुरोहित ने बताया कि गीता का असली नाम राधा है और वह इन दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अपनी मां मीना पांढरे के साथ रह रही हैं। गीता का परिवार गरीब है और वह आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए नौकरी करना चाहती हैं। पुरोहित ने कहा, गीता के मुताबिक अभी वह शादी नहीं करना चाहती। गीता बचपन में गलती से रेल में सवार होकर सीमा पार करने के कारण करीब 23 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गई थीं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गीता को लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में अकेले बैठा हुआ पाया था। मूक-बधिर लड़की को पाकिस्तान की सामाजिक संस्था ईधी फाउंडेशनै की बिलकिस ईधी ने गोद लिया और अपने साथ कराची में रखा था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (अब दिवंगत) के विशेष प्रयासों के कारण गीता 26 अक्टूबर 2015 को स्वदेश लौट सकी थीं। इसके अगले ही दिन उन्हें इंदौर में एक गैर सरकारी संस्था के आवासीय परिसर भेज दिया गया था। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र में अपने परिवार का पता चलने के बाद गीता इस राज्य में रह रही हैं।

संत कबीर नगर में डूबने से पांच लड़कियों की मौत

संत कबीर नगर। संत कबीर जिले में दो घटनाओं में पांच लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने बुधवार को बताया कि पहली घटना बखिरा थाना क्षेत्र के बड़गो गांव में हुई, जहां चार लड़कियां अर्चना (15), पायल (13), मीनाक्षी (17) और काजल (16) बखिरा झील में नाव से जा रही थीं। इसी दौरान नाव डगमगा कर अचानक पलट गई। अर्चना, पायल और मीनाक्षी की डूब कर मौत हो गई जबकि काजल को ग्रामीणों ने बचा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। दूसरी घटना थाना दुधरा क्षेत्र के खतियवा गांव की है जहां दो लड़कियां प्रमिला (18) और उसकी सगी बहन उर्मिला (15) की डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें खेत जा रही थीं तभी रास्ते में उर्मिला का पैर फिसला और वह तालाब में गिर गई। प्रमिला ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह भी तालाब में गिर गई और दोनों की डूबने से मौत हो गई। सिंह ने बताया कि पांचों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस साल 201 भारतीय हजयात्रियों की मौत हुई: मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को कहा कि इस साल हज के दौरान कुल 201 भारतीय हज यात्रियों की मौत हुई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि अधितर मौतें सांस संबंधी दिक्कत और दिल का दौरा पड़ने के कारण हुईं। सजदा अहमद ने सवाल किया था कि इस बार हज में कितने भारतीय नागरिकों की मौत हुई ? रीजीजू ने कहा, 21 जुलाई 2024 तक, हज यात्रा-2024 के दौरान 201 भारतीय हजयात्रियों की मृत्यु हुई है। उनमें से अधिक मौतें सांस संबंधी कारणों और दिल का दौरा पड़ने के कारण हुईं।

आरक्षित श्रेणी के 1195 उम्मीदवार पांच वर्षों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस नियुक्त किए गए

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को लोकसभा में कहा पिछले पांच वर्षों में आरक्षित श्रेणियों के 1,195 उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में 233, 2019 में 231, 2020 में 223, 2021 में 250 और 2022 में 258 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में भर्ती प्रासंगिक नियमों के अनुसार यूपीएससी के माध्यम से की जाती है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की दर से आरक्षण प्रदान किया जाता है।

फैसला सार्वजनिक मंच से हटाने संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों में एक व्यक्ति के बरी होने के बाद मामले से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक मंचों से हटाने के उसके अधिकार से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हुआ। यह मुद्दा आरोपी के उस अधिकार से संबंधित है जिसमें सार्वजनिक मंचों से उसके नाम वाले फैसलों को हटाने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि फैसला हटाने के गंभीर प्रभाव होंगे।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें उसने एक विधि पोर्टल को अपनी वेबसाइट से उस निर्णय को हटाने के लिए कहा था कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी बरी हो गया है। सीजेआई ने कहा, फैसले सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं और अदालतों की ओर से उन्हें हटाने के आदेश का गंभीर असर पड़ेगा।

पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि कोई व्यक्ति बरी हो गया है, उच्च न्यायालय उसे (विधि पोर्टल को) फैसला वापस लेने का निर्देश कैसे दे सकता है ? एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। उच्चतम न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ इंडिया कानून पोर्टल द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पोर्टल को अपनी वेबसाइट से फैसला हटाने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय ने कार्तिक थ्योडोर नामक व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला दिया था।

मुडा घोटाला को लेकर भाजपा कर्नाटक विधानसभा में दिन-रात धरना देगी

बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को घोषणा की कि वह मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़े के संबंध में चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में दिन-रात धरना देगी। भूखंड प्राप्त करने वालों में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं। विपक्ष को आज दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। विधानमंडल का सत्र शुक्रवार को समाप्त होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं। जब हम मुडा घोटाले में 4,000 करोड़ रुपए की लूट के बारे में स्थगन प्रस्ताव लाए, तो सरकार डर गई और चर्चा से भाग रही है। उन्होंने वित्त विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया है। यह सरकार डरपोक है, उनके पास सदन में मुडा के आरोपों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। यदि सरकार में थोड़ा भी आत्मसम्मान है तो उसे सदन में यह कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 14 भूखंड को कानूनी तरीके से लिया है और उनके समर्थकों ने भी ऐसा ही किया है। यह 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। दलितों की एक लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन लूट ली गई है.....हम इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, हमें इसकी अनुमति नहीं दी गई...सत्ता पक्ष के पक्ष में स्पीकर का आचरण निंदनीय है.. सत्ता पक्ष और स्पीकर द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने के इस आचरण की निंदा करते हुए हम दिन-रात प्रदर्शन की घोषणा करते हैं। हमारे सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य इस सरकार के खिलाफ दिन-रात विरोध प्रदर्शन करेंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक बी वाई विजएंद्र ने भी विधानसभा और विधान परिषद में कहा, हम रातभर विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दलितों के साथ अन्याय न हो, मुख्यमंत्री के परिवार को दी गई जमीन और 5,000 से अधिक अवैध रूप से आवंटित भूखंड को वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री पर मुडा घोटाले पर चर्चा का अवसर न देकर इस पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। यदि उनमें हिम्मत होती तो उन्हें स्पीकर से कहना चाहिए था कि चर्चा की अनुमति दें, चर्चा की अनुमति न देकर विपक्ष को दबाया जा रहा है। विधानसभा में विपक्ष द्वारा मुडा घोटाले को लेकर चर्चा कराए जाने पर जोर दिए जाने के शोरगुल के बीच, मुख्यमंत्री द्वारा पेश चार विधेयक 8573.72 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव संबंधी वित्त विधेयक, जीएसटी (संशोधन) विधेयक, सिंचाई (संशोधन) विधेयक और नगर पालिका एवं अन्य कानून विधेयक पारित कर दिए गए।

पेज 1 का शेष

बजट पर...

किए गए अंतरिम बजट या मंगलवार को संसद में पेश किए गए पूर्ण बजट में कई राज्यों का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी योजनाएं राज्यों के लिए काम नहीं कर रही हैं। सीतारमण ने कहा कि वह कई अन्य राज्यों का हवाला दे सकती हैं जिन्हें बड़ी परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, ताकि लोगों को यह आभास दिया जा सके कि 'ओह, हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है, यह केवल दो राज्यों को दिया गया है।' मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती दूंगी उनके द्वारा दिए गए सभी बजट भाषणों के लिए, क्या उन्होंने प्रत्येक बजट भाषण में देश के प्रत्येक राज्य का नाम लिया है ? यह एक अपमानजनक आरोप है, जो स्वीकार्य नहीं है। जैसे ही विपक्षी दलों के सांसद सदन में लौटे, वित्त मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मंगलवार को बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ भी नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया था, लेकिन तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी को राज्य में लागू नहीं किया गया है। उनके बयान का टीएमसी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया, जिन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1 लाख करोड़ रुपये बकाया है।

केंद्र...

दिनों में जम्मू-कश्मीर में 28 आतंकी मारे गए हैं और दुर्भाग्य से कुछ सुरक्षाकर्मियों की भी जान चली गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री के मुताबिक, 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में करीब 900 आतंकियों को मार गिराया है। 2004-2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए का शासन था, तब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की 7,217 घटनाएं हुईं। राय ने कहा, 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी और इस साल 21 जुलाई को यह संख्या घटकर 2,259 हो गई। 2019 में, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। राय ने सदन को बताया कि 2004 से 2014 के बीच 2,829 नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान गई। 2014 के बाद से इस संख्या में 67 फीसदी की कमी आई है। इसके अलावा आतंकी घटनाओं में भी 69 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में लोग अब शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं और सुरक्षा की पूरी गारंटी है।

बिहार...

वाला शब्द है, उन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही चार साल तक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यहां तक कि संपत्तियों की कुर्की भी की जा सकती है। मंत्री ने कहा कि ऐसी परीक्षा आयोजित करने की कुल लागत का एक हिस्सा दोषी सेवा प्रदाता से भी वसूला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक, 'लाखों युवा पुरुषों और महिलाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर लाया गया है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारी 'पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं होंगे।' गौरतलब है कि राज्य हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई 3.0) पेपर लीक मामले को लेकर खबरों में है। नया कानून केंद्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा लागू किए गए कड़े पेपर लीक विरोधी कानूनों की पृष्ठभूमि में भी आया है। वहीं बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। बिहार के ऊर्जा विभाग के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की ओर से यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। हालांकि, विपक्ष ने राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए बहिर्गमन किया।

शंभू बॉर्डर...

अन्य स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकार पूरे साल राजमार्ग को बाधित नहीं रख सकती। मेहता ने कहा कि 500-600 से अधिक टैंक प्रदर्शन स्थल पर खड़े हैं जिन्हें , जिन्हें बख्तरबंद टैंकों के रूप में संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी तक आने की अनुमति दी गई तो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा आवागमन को नियंत्रित कर सकता है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करने से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने अपनी अपील में नाकेबंदी के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से अवरोधक हटाने को कहा था और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। हरियाणा सरकार ने विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन की घोषणा किए जाने के बाद फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक लगा दिए थे। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांग कर रहे हैं।

बाधा मुक्त...

ईटीसी और जीएनएसएस-आधारित ईटीसी दोनों एक साथ काम करेंगे। टोल प्लाजा पर समर्पित जीएनएसएस लेन उपलब्ध होंगी, जिससे जीएनएसएस-आधारित ईटीसी का उपयोग करने वाले वाहनों को स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति मिलेगी। जैसे-जैसे जीएनएसएस आधारित ईटीसी अधिक व्यापक होता जाएगा, सभी लेन अंतत: जीएनएसएस लेन में परिवर्तित हो जाएंगी। भारत में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही में सुविधा होगी और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को कई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जैसे बाधा रहित फ्री-फ्लो टोलिंग जिससे परेशानी मुक्त सवारी अनुभव और दूरी-आधारित टोलिंग होगी। जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से लीकेज को रोकने और टोल चोरों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में अधिक कुशल टोल संग्रह प्रणाली बनेगी। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एनएचएआई द्वारा प्रवर्तित कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) 'भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन' की देखभाल कर रही है। जीएनएसएस तकनीक नेविगेशन और पोजिशनिंग को बढ़ाती है, टोल संग्रह प्रणालियों को आधुनिक बनाने, निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने और हमारी सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमओआरटीएच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने, शासन को अधिक पारदर्शी बनाने और तेज सेवाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

काठमांडू...

सौर्य एयरलाइंस की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी नेपाल में पांच पर्यटक स्थलों के लिए विमानों का संचालन करती है। उसके बेड़े में तीन बमबॉर्डियर सीआरजे-200 विमान शामिल हैं। हाल के वर्षों में खराब हवाई सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए नेपाल की आलोचना की गई है, लेकिन इन दुर्घटना की वजहों में मानवीय भूल के अलावा आंशिक रूप से अचानक मौसम परिवर्तन और दुर्गम चट्टानी इलाकों में स्थित हवाई पट्टियां भी शामिल हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन निकाय के अनुसार, अगस्त 1955 में पहली दुर्घटना के बाद से देश में हवाई दुर्घटनाओं में 914 लोग मारे गए हैं। पिछले साल जनवरी में, यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पांच भारतीयों सहित सभी 72 लोग मारे गए थे। दुर्घटना का कारण मानवीय भूल बताया गया।

आईएनएस...

नौसेना की ओर से कहा गया कि इस दुख की घड़ी में भारतीय नौसेना शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। इसने सोमवार को कहा था कि एक कनिष्ठ नाविक को छोड़कर सभी कर्मियों का पता लगा लिया गया है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र को अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

आयकर की कम दर और छूट साथ-साथ नहीं चल सकते

भाषा। नई दिल्ली

आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने बुधवार को कहा कि आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं, उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है, जबकि छूट पुरानी व्यवस्था में ज्यादा है।

उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अच्छे वेतन वाली नौकरियां बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। सरकार का मकसद युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण देकर बाजार के हिसाब से रोजगार के लिए तैयार करना है। बजट को लेकर सेठ ने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा, आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं, उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है जबकि छूट पुरानी कर व्यवस्था में ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में नई कर व्यवस्था में मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने और कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव किया। बजट में किए गए बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपए तक की कर बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुल करदाताओं में से दो-तिहाई यानी लगभग 68 प्रतिशत नई कर व्यवस्था में आ गए हैं, अन्य पुरानी कर व्यवस्था में है। यह पूछे जाने पर कि क्या पुरानी कर व्यवस्था को छोड़ने की तैयारी है, सेठ ने कहा, हम किसी को नहीं छोड़ रहे। करदाताओं को जो व्यवस्था अनुकूल लगती है, वे उसे अपना सकते हैं। बजट में युवाओं के लिए किए गए उपायों के बारे में सचिव ने कहा, यह बजट रोजगार बढ़ाने वाला है। हमारा प्रयास है कि

युवाओं को प्रशिक्षण मिले। वे बाजार की जरूरत के अनुसार तैयार हों और उन्हें अच्छे वेतन वाली नौकरियां मिले। यह पूछे जाने पर कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए बिना अच्छी नौकरियां सृजित होंगी, उन्होंने कहा, इन उपायों से यह सुनिश्चित करना है कि जो भी युवा एक स्तर तक पहुंच गया है, उसे उसकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाए। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए पांच साल की अवधि में दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूंजी लाभ कर में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सेठ ने कहा, काफी समय से यह सोच रही है कि कर प्रणाली को सरल बनाया जाए। अलग-अलग तरह के निवेश हैं। कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं, कुछ इक्विटी शेयर में। उन्होंने कहा, इक्विटी में अलग कर, सूचीबद्ध संपत्ति में अलग और गैर सूचीबद्ध में अलग कर, यह ठीक नहीं है। कर को लेकर सभी संपत्ति वर्ग में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। बजट में उसे दुरुस्त किया गया है। साथ ही इंडेक्सेशन भी हटाया गया है। इससे पारदर्शिता भी आती है। बजट में प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, सूचीबद्ध शेयर, इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड और एक व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाइयों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रतिभूतियों पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। निवेशकों को सालाना 1.25 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में एक लाख रुपए है। हालांकि, सूचीबद्ध बॉन्ड एवं डिबेंचर के मामले में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड एवं डिबेंचर के मामले में एलटीसीजी को वर्तमान में 20 प्रतिशत की एकसमान दर के मुकाबले लागू होने वाली स्लैब दरों के आधार पर लगाया जाएगा। इस मामले में भी एसटीसीजी दर अपरिवर्तित बनी हुई है। एक अन्य सवाल के जवाब में सेठ ने कहा, एसटीटी (प्रतिभूति लेनदेन कर) में वृद्धि एक संकेत है। नकदी और डेरिवेटिव (वायदा एवं विकल्प) बाजार में संतुलन के लिए यह कदम उठाया गया है...।

एनजीटी ने एम्स के पास कचरा फेंकने को लेकर केंद्र, एमसीडी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पास कचरा फेंके जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया है। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया कि एम्स के गेट नंबर छह के सामने करीब 30 मीटर के क्षेत्र में कचरा फेंका जा रहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने हालिया आदेश में कहा, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि फेंका जा रहा कचरा एम्स के आसपास वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है और इस तरह खुले में कचरा डालने से आसपास के क्षेत्र में भारी वायु प्रदूषण हो रहा है। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।

उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सचिव को पुनर्वास के लिए बैठक का निर्देश दिया

हल्द्वानी अतिक्रमण

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 50,000 से अधिक लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र और रेलवे के साथ बैठक करें। उच्चतम न्यायालय केंद्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसके पिछले साल पांच जनवरी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने हल्द्वानी में उस 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस पर रेलवे ने दावा जताया है।

याचिका में कहा गया कि रेलवे परिचालन को सुगम बनाने के लिए उक्त भूमि तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि पटरियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार पिछले साल मानसून के दौरान ढह गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्ईय पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह योजना बतानी होगी कि इन लोगों का कैसे और कहां पुनर्वास किया जाएगा। अदालत ने कहा कि, यह मानते हुए कि वे अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन वे

भी इंसान हैं और दशकों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने पक्के मकान भी बना लिए हैं, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। पीठ ने कहा, अदालतें निर्दई नहीं हो सकतीं और साथ ही लोगों को अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं कर सकतीं। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां भी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी देरी के राज्य सरकार को बुनियादी ढांचा विकसित करने और रेलवे लाइन के लिए आवश्यक जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया। उसने अतिक्रमण हटाने के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों की पहचान करने का भी निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के शुरुआत में इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि रेलवे ने एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बेदखली का आदेश प्राप्त किया।

पीठ ने सवाल किया, क्या आपने अतिक्रमण करने वालों को कोई नोटिस जारी किया? आप जनहित याचिका की आड़ क्यों ले रहे हैं? अगर वहां पर अतिक्रमणकारी हैं तो रेलवे को अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करना चाहिए। रेलवे की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को सूचित किया कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत भी अतिक्रमकारियों के खिलाफ कार्यवाही लंबित है। भाटी ने अदालत से क्रमिक आधार पर रोक हटाने या इसमें संशोधन करने का उनरोध करते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे के कारण रेलवे की कई विस्तार योजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि मौजूदा समय में 1200 झोपड़ियों को हटाने की जरूरत है और स्पष्ट किया कि रेलवे के पास अतिक्रमकारियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भूमि पर अधिकार का दावा करने वालों को उचित अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही, उसने उत्तराखंड सरकार को ऐसी जगह का सुझाव देने का निर्देश दिया, जहां ऐसे प्रभाविता हटाए गए परिवारों का पुनर्वास किया जा सके। रेलवे के मुताबिक उक्त जमीन पर 4,365 अतिक्रमणकारी हैं जबकि जमीन पर काबिज लोगों का दावा है कि वे जमीन के मालिक हैं। विवादित जमीन पर 4,000 से अधिक परिवारों के लगभग 50,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल पांच जनवरी को हल्द्वानी में रेलवे के दावे वाली 29 एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा था कि यह एक मानवीय मुद्दा है और 50,000 लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता।

स्वदेशी जागरण मंच ने बजट को रोजगार-केंद्रित कृषि-समर्थक बताया

नई दिल्ली। (भाषा) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने केंद्रीय बजट 2024-25 को रोजगार-केंद्रित, कृषि-समर्थक और कारोबार क्षेत्रों के अनुकूल बताते हुए बुधवार को सरकार से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अधिक उपाय अपनाने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जिसमें सरकार की नौ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। इसमें उत्पादकता, नौकरी, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधारों पर जोर दिया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने बयान में कहा, मंच बजट प्रस्तावों की सराहना करता है क्योंकि वे रोजगार-केंद्रित, कृषि-समर्थक और कारोबार खासकर एमएसएमई के अनुकूल हैं। इसके साथ ही एसजेएम ने उम्मीद जताई कि सरकार देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाएगी।

बजट में शिक्षित युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिए जाने की घोषणा पर एसजेएम ने कहा कि यदि इस योजना को ठीक से लागू किया जाता है तो यह युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हो सकता है। एसजेएम के मुताबिक, बजट में निजी क्षेत्र में नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की उनके देश की इच्छा का स्वागत किया। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मिलकर खुशी हुई। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को व्यापक एवं गहरा बनाने के लिए प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर द्वारा दी गई प्राथमिकता की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा, हम संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए समझौता करने की इच्छा का स्वागत करते

I, Afshan Parveen, wife of Sayed Zaki Haider Rizvi, born on 18th March 1990, and residing at Flat No-404, Tower-KM62, Jaypee Kosmos, Sector-134, Noida, Gautam Budhha Nagar, Uttar Pradesh 201304, India, hereby declare that I have legally changed my name to Afshan Rizvi. This change has been formalised through an affdavit dated 23rd July 2024 in Delhi.

Please note that I have previously been known by the names Afshan Parveen and Sayyada Afshan Parveen. Henceforth, I will be known solely as Afshan Rizvi.

This public notice is made to inform all concerned parties of my name change.

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किल श्री बिजेन्द्र पाल सिंह, प्लॉट नंबर 3 पॉकेट-एफ, ग्राम कासना, क्षेत्रफल 280 वर्ग गज के मालिक हैं, आवंटन संख्या KASO1467 ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश, पंजीकृत GPA दिनांक 08.08.2018 के माध्यम से श्री दल्ले द्वारा श्री बिजेन्द्र पाल सिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकरण संख्या 817, SR-नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उपरोक्त संपत्ति को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) के पास गिरवी होने जा रही है। यदि किसी व्यक्ति/बैंक/वित्तीय संस्थान के पास उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा/अधिकार, ग्रहणाधिकार, कोई आपत्ति है, तो उसे अधोहस्ताक्षरी/अधिवक्ता विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092 को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 7 दिनों के भीतर पंजीकृत पते के तहत दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर किसी भी दावे, ग्रहणाधिकार या आपत्ति को माफ कर दिया गया माना जाएगा। विशाल मेहन, अधिवक्ता ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092, मोबाइल नंबर 9811215181

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किल श्री दीपक चौहान पुत्र श्री राजपाल सिंह, ग्राम रायपुर खादर, पनगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित एक फ्रीहोल्ड आवासीय मकान, क्षेत्रफल 315.484 वर्ग गज यानी 263.78 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 19 में से, पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से मालिक है। जो श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह द्वारा श्री दीपक चौहान पुत्र श्री राजपाल सिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकरण संख्या 7391, SR-I, नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। उपरोक्त संपत्ति को फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास गिरवी होने जा रही है। यदि किसी व्यक्ति/बैंक/वित्तीय संस्थान के पास उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा/अधिकार, ग्रहणाधिकार, कोई आपत्ति है, तो उसे अधोहस्ताक्षरी/अधिवक्ता विशाल मेहन, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092 को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 7 दिनों के भीतर पंजीकृत पते के तहत दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर किसी भी दावे, ग्रहणाधिकार या आपत्ति को माफ कर दिया गया माना जाएगा। विशाल मेहन, अधिवक्ता ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092, मोबाइल नंबर 9811215181

PUBLIC NOTICE

To be known to all that **I, SMT. JEEVAN LATA W/o LATE NARENDER KUMAR have applied for conversion of H.NO.275, BLOCK-C-9, YAMUNA VIHAR, DELHI from lease hold to free hold vide File No.F.17(1437)76/LAB(R) in DDA.** The original document i.e. POSSESSION LETTER of the above said plot has been lost. An NCR/LR NO.1963157/2024 dated 24.07.2024 to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch,Delhi.Any person(s) claiming any right, interest,having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No.9654895908 within 15days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to **Deputy Director (Resdl) or Director (Resdl) C Block, 3rd Floor,Vikas Sadan, New Delhi**

कार्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

// ई-प्रोक्ययोरमेंट निविदा सूचना //

क्रं./802/लो.क.वि./न.पा./2024 कुम्हारी, दिनांक 23/07/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

सिस्टम टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	अनु. ला. (लाख में)	निविदा डालने की अंतिम तिथि
156551	स्वच्छता विभाग हेतु कुशल एवं अकुशल 81 श्रमिकों की आपूर्ति बाबत्।	123.78	14.08.2024

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, कुम्हारी

PUBLIC NOTICE

It is informed to all the General public that my client Sh. Rakesh Kumar S/o Late Sh. Jogender Singh. R/O C-133/2, Ground Floor , Near Government school, Sangam Vihar. New Delhi-80, my client's sons namely Nikhil Singhal & his wife Priya Sejwal used to misbehaved with my client & with his family and tried to grab her property by extended threats so my clients have no control over them. Hence, my client has debarred/disowned his son Nikhil Singhal & daughter-in-law Priya Sejwal from her life as well as from her movable / immovable property w.e.f 01.02.2024. Now my clients will not be liable / responsible for any act ot them in future as my clients have no concern or relation with them since 01.02.2024.

Kapil Kumar (Advocate) Ch.No.819, Saket Court Complex New Delhi 110017.

नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का औचित्य नहीं: शिवकुमार

बेंगलुरु, । (भाषा) कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कांग्रेस सरकार द्वारा 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया और उसके हितों की रक्षा नहीं की गई।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा था कि राज्य की मांगों की केंद्रीय बजट में अनदेखी करने के खिलाफ यह फैसला लिया गया है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, जब कोई नीति ही नहीं है तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का क्या औचित्य है? कर्नाटक के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया है। राज्य को कोई

परियोजना नहीं मिली और उसके हितों की भी रक्षा नहीं की गई। हमने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है और इसके बजाय प्रदर्शन करेंगे। सिद्धरमैया ने कहा, कर्नाटक की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाने के मेरे गंभीर प्रयासों के बावजूद, केंद्रीय बजट में हमारे राज्य की मांगों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा, बैठक में शामिल हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के लोगों की चिंताओं की अनदेखी की। हमें नहीं लगता कि कर्नाटक वासियों की बात सुनी गई, लिहाजा नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, शासन और विकास को दलीय राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। भारत सरकार के शीर्ष जन नीति विचारक संस्था की बैठक का बहिष्कार करके मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 6.5 करोड़ कन्नड़ भाषियों और उनके द्वारा कांग्रेस को दिए गए जनादेश का अपमान किया है। अशोक ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कर्नाटक की जनता को आपसे थोड़ी हिम्मत, शासनकला में पारंगत होने और राज्य के हित को अपने कांग्रेस आलाकमान की तुच्छ राजनीति से ऊपर रखने की उम्मीद थी।

भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला कर खुद राज्य के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के बजाय मुख्यमंत्री को उसमें शामिल होकर राज्य के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें राजनीति करने के बजाय बैठक में शामिल होना चाहिए था क्योंकि वह साढ़े छह करोड़ कन्नड़ भाषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बीच, वृहत बेंगलुरु शासन (जीबीए) विधेयक का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर शिवकुमार ने कहा, वे मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैंने केवल उसे सदन में रखा है। उन्हें इस पर विस्तृत बहस करने दें और उसके बाद फैसला किया जाएगा। बेंगलुरु का विस्तार अनियंत्रित तरीके से हो रहा है और यहां सुशासन की जरूरत है।

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Rohit Bansal S/o Late Shri Dev Prakash Agrawal R/o Flat No.933, Second Floor, Sector A, Pocket B and C, Vasant Kunj, New Delhi-110070, allotee/purchaser of Flat No.933, Second Floor, with Scooter Garage, Sector A, Pocket B and C, Vasant Kunj, New Delhi-110070. The original documents i.e. DDA Allocation Letter, Possession Letter, Site Possession Slip, NOC for Water & Electricity, of the above said flat have been lost. An FIR/LR No.1958914/2024 has been lodged to this effect.

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above address/phone no. 7417218507 within 15 days from the date of publication of this notice.

कार्योलय-ग्रा0 पंचा0 मु0 कपसिया वि0ख0-सिकन्दराराऊ जनपद-हाथरस
पत्रांक गीगो/ग्रम पचा0/ घौ0वि0-घ0रा0वि0/टेन्डर/2024-25 दिनांक 24/07/2024

अति अल्पकालीन निविदा

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है 15 वॉं वित्त आयोग / पंचम राज्य वित्त आयोग गद के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 मैं उपलब्ध धनराशि से कराये जाने वाले निम्नांकित कार्यो हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार सामग्री की कार्य स्थल पर आपूर्ति हेतु मुहर बन्द निविदायें दिनांक 31 /07 /2024 दिन के बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन सायं बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधौहस्ताक्षारी कर्यालय उसके द्वारा पजिकृत एवं उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। यदि उक्त निविदा प्राप्त करने एवं खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा प्राप्त एवं खोलने का दिनांक अगला कार्य दिवष होगा। निविदा खोलने, समय एवं वैधता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निविदा की वैधता मूल तिथि मानी जायेगी। निविदा की शर्ते निम्नवत निर्धारित की जाती है

1. निविदा प्रपत्र कार्यालय ग्राम पंचायत मु0 कपसिया से कार्यालय दिवस एवं समय मे निविदा मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है।
2. निविदा प्रपत्र के साथ दो प्रतिशत धरोहर धनराशि की एफ0बी0आर0 / एस0टी0डी0आर0 राष्ट्रीय बधंत पत्र जो अधीहस्ताक्षरी केपक्ष मै बंधक होगी, जमा करनी होगी।
3. निविदा सशर्त अथवा निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत होने पर मान्य नहीं होगी तथा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये श्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
4. निविदा दरों की वैधता 3 माह अधिकतम होगी। इसके लिये निविदा प्रपत्र के साथ सौ रूपये का नॉन जुटीशियल स्टाम्प) पेपर एक रूपये का रिवेन्यु टिकट के साथ होना अनिवार्य है।
5. अनुबन्ध के समय धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुये 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी होगी तथा फुल जमानत राशि पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।
6. बिलो के भुगतान मे नियमानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी।
7. सामग्री की आपूर्ति उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।
8. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि दर कौसिल मे पजीकृत हों निविदा देने से प्रतिबधित होंगे।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य का (सामग्री) रू0 मे	कार्य का धनराशि (रू0 मे)	कार्य का प्रपत्र का मूल्य (रू0 मे)	कार्य का अवधि (माह मे)
1.	निक्की के घर से अनिल के घर तक इ0ला0 एवं नाली निर्माण कार्य	169258	3385	250+GST	3 माह
2.	कासिमपुर में मैडम के घर से आर सी0सी0 तक इ0ला0 एवं नाली निर्माण कार्य	128072	2561	250+GST	3 माह

ग्रम प्रधान
ग्राम पंचायत मु0 कपसिया
विकास खण्ड हाथरस

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड हाथरस

बजट में शहरों में एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए धन का आवंटन : मनोहर लाल

नई दिल्ली। (भाषा) केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को बजट 2024-25 की सराहना करते हुए इसे जन-केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों, खासकर महिलाओं एवं किसानों का ध्यान रखा है। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि बजट में शहरों में एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए भी धन स्वीकृत किया गया है।मनोहर लाल ने कहा, केंद्रीय बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट में बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान

दिया गया है। एक करोड़ घरों के निर्माण के लिए आवंटन किया गया है। सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच साल में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। सरकार के अनुसार, पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।शहरों के लिए बजटीय आवंटन पर मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई परियोजनाओं का प्रावधान किया है।

मेटा एआई हिंदी समेत सात नई भाषाओं में उपलब्ध: नई दिल्ली। कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित कंपनी मेटा एआई अब हिंदी समेत सात नई भाषाओं में उपलब्ध है।कंपनी ने कहा कि यह कदम बहुभाषी खंड में मेटा के एआई असिस्टेंट की क्षमता बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता इन नई भाषाओं में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पर मेटा एआई के साथ बातचीत कर सकेंगे।

राजकोट गेम जोन में फ्रेम शीट, निर्माण सामग्री और वेल्डिंग के कारण निकली चिंगारी से भड़की आग

राजकोट। राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री के कारण लगी थी, जिसने पूरी इमारत को तीन-चार मिनट के भीतर अपनी चपेट में ले लिया था। अपराध शाखा ने आरोपपत्र में यह बात कही है। इस साल मई के महीने में राजकोट के टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एपी दवे की अदालत में बुधवार को गेम जोन के सह-मालिकों और राजकोट नगर निगम (आरएमसी) के अधिकारियों सहित 15 आरोपियों के खिलाफ एक लाख से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया गया।

ICICI Bank **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल शॉल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी

[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय की सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।

सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार (रों)/ सह-कर्ज़दार (रों)/ ज़मानतदार (रों) के नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्तियों का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	सौरभ मलिक (आवेदक), कोमिता सिंह (सह-आवेदक) ऋण खाता संख्या TBGUR00006255766	आवसीय प्लॉट नंबर एफ5/03, द वेस्टरलीज़, सेक्टर-108, ग्राम धरमपुर, तह. कादीपुर, गुड़गाँव, हरियाणा क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर	रु. 1,76,51,002/- (जुलाई 19, 2024 तक)	रु. 3,10,80,000/- / रु. 31,08,000/-	अगस्त 02, 2024 को दो. 12:00 बजे से दो. 02:00 बजे तक	सितंबर 05, 2024 को सु. 11:00 बजे से दो. 12:00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी संस्था **सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट URL Link- https://www.bankeauctions.com पर संचालित होगी। बंधककर्ताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **सितंबर 04, 2024** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस/इन संरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बोलीकर्ता(ओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम **ई** देखें) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल शॉल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005** में **सितंबर 04, 2024** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज (छायाप्रति) **सितंबर 04, 2024** तक **शाम 04:00** बजे से पूर्व जमा करें। यदि संभावित बोलीकर्ता(ओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहते हैं, तो वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल शॉल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **सितंबर 04, 2024** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैड्यूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **दिल्ली** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।

संपत्ति निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक** कर्मचारी के फोन नंबर 8928935040/8584874809 पर संपर्क करें।

कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसी **1. मेसर्स नेक्सझेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 2. ऑगियो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 3. हेक्टा प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न है।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करें।

तिथि : जुलाई 25, 2024
स्थान : दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सैनिक पर हथियार से हमला, व्यक्ति गिरफ्तार

भाषा। लंदन

दक्षिण-पूर्वी ब्रिटेन में एक बैरक के पास मोटरसाइकिल सवार एक नकाबपोश हमलावर ने एक सैन्य अधिकारी पर धारदार हथियार से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह जानकारी पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बुधवार को दी। केंट पुलिस ने बताया कि इस घटना के कुछ ही समय बाद 24 वर्षीय एक व्यक्ति को हत्या के प्रयास के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि इस हमले को हमलावर ने अकेले ही अंजाम दिया और यह हमला आतंकी कृत्य नहीं माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है कि क्या यह हमला संदिग्ध के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित था।

ब्रिटेन की सेना ने कहा कि पीड़ित अधिकारी की उम्र 40 साल के आसपास है और वह इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए हवाई मार्ग से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि अधिकारी की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर है। प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वह स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, हमारी सारी संवेदनाएं सैनिक, उसके परिवार और हमारे सशस्त्र बल समुदाय के साथ हैं, जो हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

रक्षा मंत्री जॉन हीली ने भी हमले को स्तब्ध करने वाला बताया। केंट पुलिस कहा कि मंगलवार शाम को लंदन से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में गिलिंगम शहर में हमले की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। केंट पुलिस बल ने कहा कि अधिकारियों को मंगलवार शाम को लंदन से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में गिलिंगम शहर में हमले की सूचना मिली थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्की मास्क पहने एक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया, उसने सैन्य अधिकारी पर हमला किया और फिर भाग गया। घटनास्थल के पास में रहने वाले एलेक्स रेनॉल्ड्स ने बताया कि जब वह अपने घर से बाहर निकले तो देखा कि एक व्यक्ति सैन्य वर्दी में सड़क पर पड़ा हुआ है और उसमें कोई हरकत नहीं है।

रेनॉल्ड्स ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने हमलावर को बाइक पर तेजी से भागते देखा। पुलिस ने कहा कि आधे घंटे के भीतर एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन की पुलिस संदिग्धों का नाम तब तक नहीं बताती जब तक उन्हें आरोपित नहीं किया जाता। पुलिस ने कहा कि जिस सड़क पर हमला हुआ, वह ब्रिटिश सेना के। रॉयल स्कूल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग रेजिमेंट के मुख्यालय ब्रॉम्पटन बैरक के करीब है। बुधवार की सुबह, पुलिस की गाड़ियों और अपराध स्थल टेप से सड़क के दोनों छोर को घेर दिया गया।

सेना ने एक बयान में कहा, हमारी संवेदनाएं सैनिक और उनके परिवार के साथ हैं और हम अनुरोध करते हैं कि इस कठिन समय में उनकी निजता का सम्मान किया जाए। हम केंट पुलिस के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे ताकि यह समझा जा सके कि क्या हुआ और जांच का समर्थन किया जा सके। ब्रिटेन में सैनिकों पर हमले दुर्लभ हैं। 2013 में, अल-कायदा से प्रेरित दो लोगों ने लंदन की एक सड़क पर सैनिक ली रिग्बी की कार से कुचल कर और फिर चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। दोनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

उत्तर कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया भेजा गया कचरे से भरा गुब्बारा राष्ट्रपति कार्यालय परिसर में गिरा

सियोल। उत्तर कोरिया ने बुधवार को दक्षिण कोरिया की ओर कचरे से भरे गुब्बारे भेजे, जिसमें कम से कम एक गुब्बारा राष्ट्रपति कार्यालय परिसर में जा गिरा। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने एक बयान जारी कर कहा कि मध्य सियोल स्थित राष्ट्रपति कार्यालय परिसर पर गिरे गुब्बारे में कोई खतरनाक पदार्थ नहीं था और इसे कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया को अगली बार सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे गुब्बारों को मार गिराना होगा क्योंकि क्या पता उत्तर कोरिया भविष्य में इसमें खतरनाक वस्तुएं भेज दे। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को सियोल की ओर कचरे से भरे और गुब्बारे भेजे। सियोल के अधिकारियों ने भी बताया कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को दक्षिण कोरिया की ओर संभवत: कचरे से भरे और गुब्बारे उड़ाए। कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने जवाबी कार्वाई करते हुए सीमा पर उत्तर कोरिया के संबंध में दुष्प्रचार संदेश प्रसारित किए थे। सुरक्षा सेवा ने यह बताने से इनकार कर दिया कि जब कचरे से भरा गुब्बारा परिसर में गिरा तो उस समय राष्ट्रपति यून सुक एओल कार्यालय में मौजूद थे या नहीं। यून के कार्यालय ने पहले कहा था कि बुधवार को उनका कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है।

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से भेजे गए कचरे से भरे गुब्बारे बुधवार को सीमा पार करके सियोल के उत्तर में उड़ रहे थे। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

एससीओ में शामिल सभी सदस्य देशों ने पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया

भाषा। बीजिंग

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने चीन में पहले संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें आतंकवादी समूहों के उन्मूलन जैसे विशेष अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चीन के जन सूचना मंत्रालय ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी चीन के झींजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में हाल ही में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास इंटरैक्शन-2024 आयोजित किया गया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंगलवार को खबर दी कि यह अभ्यास पहली बार आयोजित किया गया और इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों की संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया।

ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक, आतंकवादी खतरे अक्सर दूसरे देशों तक पहुंच जाते हैं और दुनिया इससे अछूती नहीं है, इसलिए आतंकवाद विरोधी अभियानों में सदस्य देशों की क्षमताओं और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एससीओ संयुक्त अभ्यास का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। जन सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित एजेंसियों द्वारा संयुक्त अभ्यास के लिए एक नया मॉडल स्थापित किया गया है और इसने एससीओ सदस्य देशों के अधिकारियों की संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ाया है।

मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के अहम खतरों की प्रतिक्रिया में, अभ्यास में आतंकवादी समूहों के उन्मूलन जैसे विशेष अभियान शामिल थे। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में दिख रहा है कि सैनिक और पुलिस अधिकारी असॉल्ट राइफल, पिस्तौल और दंगारोधी उपकरणों से लैस हैं। इस दौरान बख्तरबंद और अन्य वाहन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और रोबोट कुत्तों को भी अभ्यास में तैनात किया गया था। एससीओ सदस्य देशों, एससीओ सचिवालय और एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों ने अभ्यास का अवलोकन किया। इस महीने की शुरुआत में बेलारूस आधिकारिक रूप से एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया, जिसमें पहले से ही चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

ताइवान ने तूफान से निपटने की तैयारी की, फिलीपीन में 13 की मौत

भाषा। ताइपे

शक्तिशाली तूफान की आशंका के मद्देनजर ताइवान ने बुधवार को पूरे द्वीप में कार्यालय, स्कूल और पर्यटन स्थल बंद कर दिए। इस तूफान के कारण फिलीपीन में मौसमी बारिश से हालात और खराब हो गए हैं और कम से कम 13 लोगों की जान चली गई जबि छह लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान गेमी अभी ताइवान की मुख्य भूमि में दाखिल नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ही ताइवान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा हो रही है। तूफान के बुधवार शाम को उत्तरी काउंटी यलान में सीधे दस्तक देने की आशंका है।

अशांत समुद्र के कारण मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह पर वापस बुला लिया गया, जबकि हवाई यात्री कई उड़ानों के रद्द होने के कारण तूफान आने से पहले विदेश जाने वाली उड़ानों को पकड़ने की जल्दी में दिखे। केंद्रीय मौसम प्रशासन ने बताया कि बुधवार सुबह तूफान ताइवान के पूर्व में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था तथा हवा की अधिकतम गति 183 किलोमीटर प्रति घंटे थी।

राजधानी ताइपे में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन तेज हवाएं अभी तक नहीं चली थीं। फिलीपीन में इस तूफान को करीना नाम दिया गया है। गेमी हालांकि द्वीपसमूह में नहीं पहुंचा है लेकिन इसने मौसमी मानसून की बारिश को बढ़ा दिया। फिलीपीन की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बारिश के कारण पांच दिनों में कम से कम एक दर्जन भूस्खलन और बाढ़ आईं, जिससे कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 600,000 लोग विस्थापित हो गए, जिनमें 35,000 लोग आपातकालीन आश्रयों में चले गए हैं।

बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो रही है स्थिति

भाषा। ढाका

बांग्लादेश में एक सप्ताह से अधिक समय तक हिंसा के दौर के बाद अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। वहीं, बुधवार को देश में इंटरनेट उपयोग और कार्यालयों के समय को सीमित कर दिया गया। ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालय के छात्रों ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसने हिंसक रूप ले लिया था और इसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी। देश के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट शुरू नहीं किया गया, हालांकि अधिकारियों ने कर्फ्यू में सात घंटे की ढील दी, जिस दौरान राजधानी की सड़कों पर हजारों गाड़ियां नजर आईं।

बांग्लादेश में बुधवार को कार्यालय और बैंक कुछ घंटों के लिए खोले गए, जबकि अधिकारियों ने ढाका और दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव के कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहाल कर दिया। बंगाली भाषा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र प्रथम आलो में बुधवार को प्रकाशित हुई खबर में बताया कि 16 जुलाई से अब तक हिंसा में कम से कम 197 लोग मारे गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस किसी भी आधिकारिक स्रोत से मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सका।

देश में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बांग्लादेश में 15 जुलाई से आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी द्वारा छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन दिए जाने के बाद इसने हिंसक रूप ले लिया और पूरे देश में हिंसा फैल गई। ढाका में कई सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए।

बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने रविवार के अपने फैसले में कहा कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाएं, पांच प्रतिशत 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों तथा अन्य श्रेणियों के लिए दो प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएं। बांग्लादेश की सरकार ने बुधवार को परिपत्र जारी कर उच्चतम न्यायालय के सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में सुधार किए जाने वाले फैसले को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वह फैसले को लागू करने के लिए तैयार है।

डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा- सबकुछ ठीक हो जाएगा

वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि सबकुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शुक्रवार को होने वाली मुलाकाात का बेसब्री से इंतजार है और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए और भी अधिक तत्पर हूंउ इसके साथ ही उन्होंने अब्बास द्वारा उन्हें लिखा गया एक पत्र भी संलग्न किया। फलस्तीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान 13 जुलाई को हुए हमले के एक दिन बाद यह पत्र लिखा था। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 14 जुलाई को ट्रंप को लिखे पत्र में कहा, आप पर हुए हमले की खबर सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने इसका वीडियो भी देखा।

कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत नीति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं: मुकेश अघी

वाशिंगटन। भारत केंद्रित अमेरिकी व्यापार एवं रणनीतिक पैरोकार समूह के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो उनके प्रशासन में भारत-अमेरिका नीति एवं रणनीति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अघी ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, मुझे नहीं लगता कि नीति में या रणनीति में कोई बदलाव होगा खासतौर पर भारत के संबंध में। राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनावी दौड़ से हटने के बाद कमला हैरिस तेजी से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के 50 घंटे से भी कम समय में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक धनराशि जुटाना उनके पक्ष में बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडन के चुनावी दौड़ से हटने से पार्टी में और पार्टी समर्थकों में ऊर्जा भर गई है। आप पिछले 24 घंटों पर नजर डालें तो 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का चंदा मिला है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े दानदाता अब फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी और उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं। अघी ने कहा, अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका-भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ? मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा....। चीन का उदय, चीन का आक्रामक रुख दुनिया के लिए खतरा है। यह अमेरिका के हितों के लिए खतरा है और भारत पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात से असहमति जताई कि हैरिस प्रशासन के तहत भारत-अमेरिका संबंध ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा, कमला हैरिस की आलोचनाएं हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वह एक समझदार महिला हैं, वह बुद्धिमान महिला हैं। उनके पास अनुभव है। उनके पास एक अच्छी टीम होगी जो सही मार्गदर्शन करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नीति में या रणनीति में कोई बदलाव होगा, खासतौर पर भारत के संबंध में।

कमला हैरिस नेतन्याहू से मुलाकात में कहेंगी कि युद्ध समाप्त करने का वक्त आ गया है: हैरिस के सहयोगी

वाशिंगटन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के एक सहयोगी ने बताया कि हैरिस इस सप्ताह व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगी और उनसे कहेंगी कि युद्ध समाप्त करने का वक्त आ गया है। हालांकि, वह नेतन्याहू द्वारा संबोधित किए जाने वाले अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार हैरिस के एक सहयोगी ने पीटीआई से कहा, उपराष्ट्रपति इस सप्ताह व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर रही हैं। यह बैठक राष्ट्रपति बाइडन की नियोजित बैठक से अलग होगी। उपराष्ट्रपति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई को इंडियानापोलिस जा रही हैं और वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कांग्रेस के संयुक्त सत्र के पहले से निर्धारित संबोधन में भाग नहीं ले पाएंगी। हैरिस के सहयोगी ने कहा, अनुमान है कि उपराष्ट्रपति नेतन्याहू से कहेंगी कि युद्ध को इस तरह से समाप्त करने का समय आ गया है कि इजराइल सुरक्षित हो, सभी बंधक रिहा हों, गाजा में फलस्तीनी नागरिकों की पीड़ा का अंत हो और फलस्तीन के लोग सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का आनंद ले सकें। नेतन्याहू का बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है। यह अमेरिकी संसद में नेतन्याहू का चौथा संबोधन है, जो किसी भी विदेशी नेता द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में सबसे अधिक बार दिया जाने वाला संबोधन होगा। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता आम तौर पर उपराष्ट्रपति करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन ने इस संबोधन में भाग न लेने के लिए हैरिस की आलोचना की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपने पहले सप्ताह में हैरिस इजराइली प्रधानमंत्री की वाशिंगटन की आधिकारिक यात्रा के मद्देनजर अमेरिकी विदेश नीति में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा विभाजनकारी मुद्दे का सामना करेंगी।

चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा के मिट्टी के नमूनों में पानी के अणु मिले

बीजिंग। चांग ई-5 मिशन द्वारा चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के नमूनों का अध्ययन कर रहे चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणु मिले हैं। यह जानकारी चाइनीज एकेडमी आफ साइंसेज ने दी। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार, यह अनुसंधान बीजिंग नेशनल लेबोरेटरी फॉर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और सीएएस के भौतिकी संस्थान तथा अन्य घरेलू अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अनुसंधान रिपोर्ट 16 जुलाई को पत्रिका नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुई। सीएएस ने कहा कि 2020 में चांग ई-5 मिशन द्वारा लाए गए चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों के आधार पर चीनी वैज्ञानिकों ने आणविक जल से युक्त एक जलयोजित खनिज पाया है। 2009 में, भारत के चंद्रयान-। अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं के रूप में जलयोजित खनिजों के संकेतों का पता लगाया था। इसके उपकरणों में नासा का मून मिनरलॉजी मैपर (एम3) भी शामिल था जो एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसने चंद्रमा पर खनिजों में पानी की खोज की पुष्टि करने में मदद की।

रूस से युद्ध समाप्त की वार्ता के लिए चीन के साथ साझा आधार तलाश रहे यूक्रेन के विदेशमंत्री

भाषा। बीजिंग

यूक्रेन के विदेशमंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बुधवार को कहा कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अपने चीनी समकक्ष के साथ इस सप्ताह की बातचीत में साझा आधार तलाश रहे हैं। कुलेबा ने दक्षिणी चीन के प्रमुख वाणिज्यिक एवं विनिर्माण केंद्र ग्वांगझोउ में चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय देश के विदेशमंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। यूक्रेन और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। कुलेबा ने शुरुआती टिप्पणी की, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यूक्रेन में शांति चीन के सामरिक हित में है और शांति के लिए वैश्विक ताकत के रूप में चीन की भूमिका अहम है।

चीन के रूस के साथ मजबूत संबंध हैं और उसने दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए युद्ध को समाप्त करने पर जोर दिया है। चीन के इस रुख से न केवल यूक्रेन बल्कि पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका भी असहमत है, जो किसी भी समझौते के आधार के रूप में रूस की यूक्रेन से वापसी की मांग कर रहे हैं। चीन पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति वार्ता में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि रूस को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

कुलेबा चीनी अधिकारियों को अगली शांति वार्ता में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। यह शांति वार्ता नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने की संभावना है। कुलेबा के दौरे से संकेत मिलता है कि यूक्रेन के पक्ष में कोई भी शांति समझौता चीन को भरोसे में लिए बिना संभव नहीं हो सकता। चीन के अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच दोस्ताना और सहयोगात्मक संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि को रेखांकित करते हुए वांग ने कहा कि जटिल और लगातार बदल रही अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों के बावजूद दोनों देशों के संबंध सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुलेबा मंगलवार को चीन पहुंचे और उनके शुक्रवार को यहां से रवाना होने की संभावना है।

स्विट्जरलैंड में संघर्ष विराम वार्ता में शिरकत करेंगे सूडान के अर्धसैनिक बल प्रमुख

जेनेवा। सूडान के अर्धसैनिक बल प्रमुख ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा स्विट्जरलैंड में अगले महीने आयोजित संघर्ष विराम वार्ता में भाग लेने की घोषणा की है। सूडान की सेना से लड़ रही रैपिड सपोर्ट फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागालो ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर कहा कि यह वार्ता सूडान में शांति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। साथ ही उम्मीद जताई कि न्याय, समानता और संघीय शासन पर आधारित एक नया देश बनाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ देश भर में पूर्ण युद्धविराम हासिल करने और सभी जरूरतमंदों तक मानवीय पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को साझा किया है।

वार्ता 14 अगस्त को स्विट्जरलैंड में एक अज्ञात स्थान पर शुरू होने की उम्मीद है। अभी तत्काल सार्वजनिक तौर पर यह संकेत नहीं मिला है कि सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्दल फतेह बुरहान या सेना का कोई अन्य शीर्ष अधिकारी भी शिरकत करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वार्ता का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच पिछले साल के अंत में सऊदी अरब के जेद्दा में हुई बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। इसमें कहा गया है कि डागालो की सेना का समर्थन करने वाला अफ्रीकी संघ, सूडान का पड़ोसी मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को एक बयान में कहा, स्विट्जरलैंड में वार्ता का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी हिंसा को समाप्त करना, जरूरतमंद सभी लोगों तक मानवीय पहुंच को मजबूत करना और किसी भी समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त निगरानी और सत्यापन तंत्र विकसित करना है। 2023 के मध्य में राजधानी खार्तूम में सूडान के सैन्य और अर्धसैनिक प्रमुखों के बीच तनाव शुरू होने और इसके दारफुर समेत अन्य क्षेत्रों में फैलने के बाद से सूडान संघर्ष में फंस गया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 14 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं और 33 हजार घायल हुए हैं। अधिकारिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है।

इथियोपिया में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 229 हुई, कई लापता

अदीस अबाबा। इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 229 लोगों की मौत हो गई है जिनमें से कई ऐसे लोग शामिल हैं जो पीड़ितों को बचाने की कोशिश में जुटे थे। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इसे भयानक क्षति बताया है। एक स्थानीय प्रशासक दागमावी आएले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी प्रांत में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। मलबे से कम से कम पांच लोगों को जीवित निकाला गया है।

गोफा जोन के संचार कार्यालय के प्रमुख कासाहुन अबेयनेह ने बताया कि सोमवार को सबसे पहले 55 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई थी लेकिन बाद में मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी। इलाके में खोज अभियान जारी है। गोफा जोन वह प्रशासनिक इलाका है जहां भूस्खलन हुआ है। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक बयान में कहा कि उसे इस आपदा पर दुख है। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने फेसबुक पर एक बयान में कहा कि वह इस भयानक क्षति से काफी दुखी हैं। अहमद के बयान में कहा गया है कि खोज एवं बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए संघीय आपदा रोकथाम कार्य बल को तैनात किया गया है। अभी यह पता नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। गोफा में एक अन्य अधिकारी मार्कोस मेलीसे ने बताया कि ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए। उस समय बचावकर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। अन्य लोगों को बचाने की कोशिश करते वक्त भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से कई लापता हैं। कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरे परिवार को खो चुके हैं तथा लाशों से लिपट कर रो रहे हैं। इथियोपिया में जुलाई में शुरू होने वाले बारिश के मौसम में भूस्खलन होना आम है। बारिश का यह मौसम सितंबर मध्य तक जारी रहने की संभावना है।

ब्रिटेन के करोबारियों, निवेशकों ने भारत के आम बजट को उत्साहजनक बताया

लंदन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट को ब्रिटेन के कारोबारी और निवेशक समुदाय ने उत्साहजनक करार दिया है। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने और एंजल कर के संबंध में लिए गए निर्णय को सकारात्मक कदम करार दिया है। स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सीतारमण ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। एंजल कर का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। भारत के राजकोषीय घाटे में कमी आने की घोषणा, जो इस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, उन पहलुओं में से एक है जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विदेशी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिलेगा। ग्रांट थॉर्नटन में साझेदार और दक्षिण एशिया के प्रमुख अनुज चंदे ने कहा, कुल मिलाकर, मैं कहूंगा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बजट है। कुछ बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, खास तौर पर बुनियादी ढांचे और कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के मामले में। यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल के सीईओ रिचर्ड मैक्कलम ने कहा, कॉर्पोरेट कर में कटौती ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने के संबंध में एक स्वागत योग्य कदम है।

पेरिस आई ऑस्ट्रेलियाई महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों की जांच कर रहे अभियोजक

भाषा। पेरिस

पेरिस घूमने आई एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले की अभियोजक जांच कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पेरिस में 2024 ओलंपिक की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पेरिस लोक अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में बताया कि 25 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला ने फ्रांस की राजधानी में अधिकारियों को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। बयान के अनुसार अभियोजक इस मामले की सामूहिक दुष्कर्म के तौर पर जांच कर रहे हैं।

फ्रांस की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, पांच लोगों ने महिला से दुष्कर्म किया। बयान में पीड़िता के नाम का जिक्र नहीं किया गया लेकिन बताया गया है कि कथित घटना शुक्रवार 19 जुलाई देर रात को हुई। बयान के मुताबिक, महिला ने पेरिस के एक रेस्तरां में शरण ली, जहां अग्निशमनकर्मियों ने उसे आपात सहायता मुहैया कराई और बाद में उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया।

ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं व्यापार मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि फ्रांस की राजधानी में उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को पेरिस में ऑस्ट्रिलयाई दूतावास ने राजनयिक मदद की पेशकश की है। बयान में कहा गया, हम जानते हैं कि यह एक बेहद दर्दनाक अनुभव है और हम सहायता मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पीड़िता की निजता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की खबर के मुताबिक, पीड़िता ने शुरू में तत्काल ऑस्ट्रेलिया लौटने की योजना बनाई थी लेकिन बाद में उसने फ्रांस में रुकने का फैसला किया। निजता कारणों से खबर में और अन्य जानकारियां नहीं उपलब्ध कराई गई हैं।

इमरान खान का पोलीग्राफ जांच कराने से इनकार

लाहौर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल नौ मई को हुए अप्रत्याशित उपद्रव से जुड़े दर्जनों मामलों की लाहौर पुलिस द्वारा की जा रही जांच के तहत पोलीग्राफ (एक प्रकार की झूठ पकड़ने वाली जांच) और आवाज मिलान परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। बारह सदस्ईय फोरेंसिक टीम क्रिकेटर से नेता बने 71 वर्षीय इमरान खान का पोलीग्राफ परीक्षण करने मंगलवार को अडियाला जेल पहुंची थी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में पिछले साल जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को गिरफ्तार किया था तब नौ मई को देशभर में उपद्रव हुए थे। इमरान खान 200 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और वह पिछले साल अगस्त से जेल में हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी है कि एक पुलिस उपाधीक्षक की अगुवाई में लाहौर पुलिस का एक दल (पोलीग्राफ और आवाज मिलान) परीक्षण करने आडियाला जेल पहुंचा था। इस अखबार के अनुसार उनके साथ पंजाब अपराध जांच विज्ञान एजेंसी (पीएफएसए) के विशेषज्ञ भी थे। इन पीएफएसए विशेषज्ञों को पूर्व प्रधानमंत्री का पोलीग्राफ, आवाज मिलान परीक्षण और फोटोग्रेमेट्री परीक्षण करने थे।

नेशन अखबार की खबर है कि पीटीआई संस्थापक ने 15 मिनट तक पुलिस के प्रश्नों का उत्तर दिया लेकिन उन्होंने पंजाब अपराध जांच विज्ञान एजेंसी के दल के पोलीग्राफ एवं अन्य परीक्षण से गुजरने इनकार कर दिया। इस अखबार के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि विभिन्न संगठनों द्वारा उनकी जांच की जा रही है और पिछली जांच के पूरा हो जाने के बाद ही वह पुलिस को समय देंगे। डॉन अखबार की खबर है कि पुलिस अधिकारियों ने उससे नौ मई के उपद्रव के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की। नौ मई को इस उपद्रव के दौरान लाहौर कोर कमांडर के आवास, सैन्य प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया था। इस अखबार के मुताबिक जेल से लौटने के बाद, पुलिस टीम और पीएफएसए विशेषज्ञों ने लाहौर के डीआईजी (जांच) जीशान असगर को खान के असहयोग के बारे में बताया। अब अगले दौरे की रणनीति बनाने के लिए अभियोजन विभाग से परामर्श लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी।

भारतीय तीरंदाजों का लक्ष्यः ओलंपिक में पहला पदक जीतना

भाषा। पेरिस

स्थान भी अलग होगा और वर्ष भी और एक नया ओलंपिक होगा लेकिन भारतीय तीरंदाजों का लक्ष्य वही पुराना होगा, ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतना।भारत ने ओलंपिक में तीरंदाजी में पहली बार 1988 में भाग लिया था। तब से भारतीय तीरंदाज लगभग हर ओलंपिक खेल में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन अभी तक पोडियम तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज गुरुवार को लेस इनवैलिड्स गार्डन में क्वालीफिकेशन राउंड के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लंदन ओलंपिक 2012 के बाद यह पहला अवसर है जबकि भारतीय टीम में सभी छह खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया जिसका मतलब है कि इस बार भारतीय तीरंदाज पांच स्पर्धाओं में भाग लेंगे।

अनुभवी तरुणदीप राय और दीपिका कुमारी अपने चौथे ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। उनकी अगुवाई में टीम को पसंदीदा ड्रॉ हासिल करने के लिए क्वालिफिकेशन में कम से कम शीर्ष 10 में जगह बनानी होगी। प्रत्एक तीरंदाज 72 तीर चलाएगा और क्वालिफिकेशन दौर में भाग ले रहे 53 देश के 128 खिलाड़ियों के स्कोर के आधार पर रविवार से शुरू होने वाली मुख्य नॉकआउट प्रतियोगिता के लिए वरीयता तय की जाएगी। भारतीय टीम के लिए क्वालीफिकेशन दौर महत्वपूर्ण होगा जो अक्सर निचली वरीयता हासिल करती रही हैं और ऐसे में नॉकआउट चरण में उन्हें दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीम का सामना करना पड़ता है। तोक्यो ओलंपिक में भारत के सभी पुरुष तीरंदाज शीर्ष 30 में जगह नहीं बना पाए थे जिससे भारतीय टीम को नौवीं वरीयता मिली थी। भारत

की एकमात्र महिला तीरंदाज दीपिका ने नौवां स्थान हासिल किया था। भारत को तब अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया से हार का सामना करना पड़ा था। भारत को पुरुष टीम से काफी उम्मीद है जिसने इस साल शंघाई में विश्व कप के फाइनल में कोरिया को हराकर इतिहास रचा था। भारतीय टीम में राय और पिछले ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रवीण जाधव के रूप में अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं जबकि युवा खिलाड़ी धीरज बोम्मादेवरा एक महीने पहले अंताल्या विश्व कप में तोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता इटली के मौरो नेस्पोली को हराकर कांस्य पदक जीत कर उत्साह से लबरेज होंगे। महिला वर्ग में सभी की निगाहें दीपिका पर टिकी रहेंगी। उन्होंने मां बनने के 16 महीने के अंदर शंघाई में विश्व कप के पहले चरण में रजत पदक जीत कर शानदार वापसी की थी। महिला टीम में उनके साथ देने के लिए अंकिता भक्त और भजन कौर हैं। इन दोनों का यह पहला ओलंपिक होगा लेकिन वह वर्तमान ओलंपिक चक्र में भारतीय टीम का हिस्सा रही हैं और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। धीरज और दीपिका अगर रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहते हैं तो फिर रिकर्व मिश्रित टीम में उनसे पदक कीराउंड में शीर्ष पर रहते हैं तो फिर रिकर्व मिश्रित टीम में उनसे पदक की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय तीरंदाज ओलंपिक में अभी तक क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। भारत तीरंदाजी में केवल सिडनी ओलंपिक 2000 में क्वालीफाई नहीं कर पाया था। इसके अलावा उसने सभी ओलंपिक खेलों में भाग लिया लेकिन अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाया। पेरिस ओलंपिक में पुरुष टीम का फाइनल सोमवार को जबकि व्यक्तिगत एलिमिनेशन मंगलवार को शुरू होगा। मिश्रित टीम का फाइनल अगले शुक्रवार को तथा उसी सप्ताहांत में महिला और व्यक्तिगत फाइनल होंगे।

विरोधी से डरना नहीं है, बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखो

हाई जंपर सर्वेश ने नीरज से सीखा

भाषा। नई दिल्ली

गांव में चारे के मैट पर अभ्यास से पेरिस ओलंपिक तक का सफर तय करने वाले हाई जंपर सर्वेश कुशारे को अपनी तैयारियों और भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा से मिले इस मूलमंत्र पर यकीन है कि प्रतिद्वंद्वियों की ख्याति से डरे बिना बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखो। कुशारे ओलंपिक उंची कूद के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अभ्यास के दौरान 2 . 30 मीटर का आंकड़ा पार कर रहे कुशारे को अपनी कड़ी मेहनत और तोक्यो ओलंपिक में भालाफेंक में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स में भारत का खाता खोलने वाले नीरज की सलाह पर पूरा यकीन है।ओलंपिक में उंचे कद और भारी डील डौल वाले प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार पांच फुट नौ इंच के कुशारे ने पोलैंड के स्पाला से भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा , मेरा बस कद ही छोटा है लेकिन हम भी भीतर से बहुत मजबूत हैं। प्रतिद्वंद्वी की कद काठी देखकर कोई डर नहीं लगता। सही समय पर शीर्ष फॉर्म में रहना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के नाशिक से कुछ किलोमीटर दूर देवरगांव के रहने वाले 29 वर्ष के इस एथलीट ने कहा , अभी तो काफी समय से नीरज भाई से मुलाकात नहीं हुई है लेकिन जब पिछली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग पर फोकस करो और विरोधी खिलाड़ियों की ख्याति से डरना नहीं है। वह हमेशा टिप्स देते रहते हैं। उन्होंने कहा , हमारे आदर्श नीरज चोपड़ा ही हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक जीतकर हमारे भीतर भी आत्मविश्वास भरा। हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं और देश का मान बढाना चाहते हैं।

पंचकूला में जून में अंतर प्रांत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 2 . 25 मीटर की रिकॉर्ड कूद के साथ स्वर्ण जीतने वाले कुशारे ने क्वालीफिकेशन प्रक्रिया में 23वां स्थान हासिल करके पेरिस का टिकट कटाया। उन्होंने कहा , जून से पहले मेरी रैंकिंग 36 चली गई थी क्योंकि मई में जब पूरी दुनिया में स्पर्धाएं चल रही थी, मैं नहीं खेल सका था। मुझे डर लग रहा था कि ओलंपिक खेल सकूंगा कि नहीं। मैं काफी दबाव में आ गया था लेकिन फिर मलेशिया, कजाखस्तान और पंचकूला में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके क्वालीफाई किया। उन्होंने कहा , टखने की चोट के कारण बहुत दिक्कतें आई थी लेकिन अब लगातार अच्छा अभ्यास करके मेरा आत्मविश्वास बढा है। अभी फोकस क्वालीफिकेशन दौर पर है जो सात अगस्त को सुबह दस बजे होगा। पहला लक्ष्य फाइनल में जगह बनाने का है। उसके बाद की प्लानिंग बाद में करूंगा। स्पाला में अत्याधुनिक सुविधाओं के बीच तैयारी कर रहे कुशारे ने जब खेलना शुरू किया तो गाय के चारे को मैट के रूप में इस्तेमाल करते थे।उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा , हमारे गांव में उंची कूद का मैट नहीं था तो गाय के लिए जो मक्के का चारा इकट्ठा होता था, उसका मैट बनाया जाता था। उसका एक ही पीस लैंडिंग एरिया की तरह बनाया था और हम उस पर अभ्यास करते थे। उन्होंने बताया, स्कूल के पीटी टीचर आर डब्ल्यू जाधव सर के मार्गदर्शन में खेलना शुरू किया। फिर सैन्य खेल संस्थान में गया और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट (ओजीक्यू) से भी सहयोग मिला जिन्होंने अमेरिका में अभ्यास के लिए भेजा।

जुबिन हमारी मदद कर रहे, श्रीलंका को भारतीय खिलाड़ियों के संन्यास का फायदा उठाना चाहिए

पाल्लेकल (भाषा)। श्रीलंका के अंतरिम मुख्य कोच सनथ जयसूर्या ने बुधवार को खुलासा किया कि आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस निदेशक जुबिन भरूचा ने भारत के खिलाफ आगामी टी20 श्रृंखला की तैयारी में उनके बल्लेबाजों की मदद की है और उन्हें उम्मीद है कि टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों के संन्यास का फायदा उठाएगी। रोहित, कोहली और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने पिछले महीने भारत की विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया था। श्रीलंका के खिलाफ टी20 श्रृंखला 27 जुलाई से यहां शुरू होगी। जयसूर्या ने खुलासा किया कि श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों के लंका प्रीमियर (एलपीएल) लीग से जुड़ा होने के बावजूद भरूचा के साथ छह दिन के शिविर का आयोजन किया गया।

उन्होंने कहा, हमने एलपीएल के तुरंत बाद सत्र शुरू किया। अधिकतर खिलाड़ी

एलपीएल में खेल रहे थे इसलिए वे क्रिकेट में व्यस्त थे और हम चाहते थे कि वे अधिक से अधिक क्रिकेट खेलें। जयसूर्या ने कहा, हम राजस्थान रॉयल्स से जुबिन को लाए और हमने लगभग छह दिन उनके साथ काम किया। एलपीएल में खेलने बाद अन्य क्रिकेटर भी उनके साथ जुड़े। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों ने सीख लिया है कि आप (प्रबंधन) अभ्यास और तकनीक के मामले में उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, तैयारी अच्छी थी और टी20 शुरू होने से पहले कैंडी में हमारे पास दो दिन और हैं। जयसूर्या ने कहा कि भरूचा के साथ सत्र काफी गहन रहे और खिलाड़ियों ने उनसे काफी कुछ सीखा। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए नई तकनीक, नए दृष्टिकोण और नए शॉट मारना सीखना महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रभावी बन सकें। भारत को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए सूर्यकुमार यादव के रूप में नया कप्तान भी मिला है और जयसूर्या ने अपनी टीम से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने को कहा। एसोसिएटेड प्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयसूर्या के हवाले से कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। उनकी प्रतिभा और उन्होंने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसे देखते हुए हम सभी जानते हैं कि वे और जडेजा किस स्थान पर हैं।

भारतीय महिला टीम का सफलता सूत्र, एक बार में एक मैच पर ध्यान केंद्रित करना: दीप्ति

दाम्बुला। (भाषा) सीनियर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने कहा कि महिला टी20 एशिया कप में भारतीय टीम का सफलता का सूत्र एक बार में एक मैच पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब टीम पिछली बार यहां खेली थी तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है।भारत ने ग्रुप ए के अंतिम मैच में मंगलवार को नेपाल को 82 रन से करारी शिकस्त दीजिए। इस मैच में शेफाली वर्मा ने 48 गेंद पर 81 रन की तूफानी पारी खेली थी जबकि दीप्ति ने 13 रन देकर 3 विकेट लिए थे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर

178 रन बनाए और इसके बाद नेपाल को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 98 रन पर रोक दिया था। दीप्ति ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, हम पहले मैच से ही प्रत्एक मैच और प्रत्एक परिस्थिति को लेकर काफी आश्वस्त हैं। अब हमारी निगाह सेमीफाइनल पर है। भारतीय टीम इससे पहले जून 2022 में यहां खेली थी और दीप्ति ने कहा कि तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं बदला है। हमने इसे सरल बनाए रखा है और हमारा ध्यान केवल अगले मैच पर केंद्रित रहता है। मैं पिछली बार भी यहां खेली थी और तब से कोई बदलाव नहीं आया है। हमें खुद पर भरोसा है और परिस्थितियां पहले जैसी हैं। इस ऑफ़ स्पिनर ने अभी तक तीन मैच में 8 विकेट लिए हैं और उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की स्थिति में गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहती हैं।

स्पेन, अर्जेन्टीना के फुटबॉल मैच के साथ पेरिस ओलंपिक में प्रतियोगिताएं शुरू

पेरिस। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को प्रतियोगिताओं की आधिकारिक शुरुआत हुई जब स्पेन और अर्जेन्टीना क्रमश: पेरिस और सेंट एटीने में अपने-अपने फुटबॉल मुकाबलों के लिए मैदान पर उतरे। स्पेन की टीम पश्चिम पेरिस के पार्स डेस प्रिंसेस स्टेडियम में उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरी। स्टार खिलाड़ी काइलियान एमबाप्पे जब पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से खेलते थे तो यह उनका घरेलू मैदान था। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा के अध्यक्ष जियानी इनफेंटिनो ने इस मुकाबले से पहले खिलाड़ियों से मुलाकात की। टूर्नामेंट का पहला गोल स्पेन के राइट बैक मार्क पुबिल ने 29वें मिनट में दागा। दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेस्सी के बिना ओलंपिक में खेल रही अर्जेन्टीना की टीम अपने पहले मुकाबले में मोरक्को के खिलाफ सेंट एटीने के ज्योफ्री गुइचर्ड स्टेडियम में उतरी।

फिर आईओसी सदस्य चुनी गईं नीता अंबानी

नई दिल्ली। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को बुधवार को पेरिस में सर्वसम्मति से दोबारा भारत से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) का सदस्य चुना गया। पेरिस में चल रहे आईओसी के 142वें सत्र के दौरान हुए मतदान में नीता को शत प्रतिशत मत मिले। नीता ने पुन: आईओसी सदस्य चुने जाने के बाद विज्ञप्ति में कहा, मैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं अध्यक्ष (थॉमस) बाक और आईओसी में अपने सभी सहयोगियों को मुझ पर उनके विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने कहा, फिर से (सदस्य) चुना जाना ना केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर है बल्कि वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव की मान्यता भी है। मैं हर भारतीय के साथ खुशी और गर्व के इस पल को साझा करती हूं और भारत तथा दुनिया भर में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हूं। नीता को पहली बार 2016 में रियो डि जिनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान इस प्रतिष्ठित संस्था में शामिल किया गया था। वह आईओसी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला हैं।

भारतीय ओलंपिक टीमों का विवादों से नाता, झगड़ों से लेकर डोपिंग तक

नई दिल्ली (भाषा)। काका पवार और पप्पू यादव को 1996 ओलंपिक तक ज्यादा लोग नहीं जानते थे, दोनों में सिर्फ दो चीजें समान थीं कि दोनों पहलवान थे और दोनों 48 किग्रा वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैट के अंदर और बाहर भिड़ंत को तैयार थे। लगभग 28 साल पहले दोनों के बीच भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए आईजी स्टेडियम में भिड़ंत हुई थी। यादव ने विवादास्पद ट्रायल जीत लिया था लेकिन अटलांटा में वजन मापने की प्रक्रिया में विफलता के बाद उन्हें ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय खेलों और विशेष रूप से कुश्ती ने अपने अतीत से कोई सीख नहीं ली क्योंकि हर चार साल में होने वाले इस महाकुंभ में भाग लेने से पहले हमेशा विवादों का बोझ बना रहता है। छह भारतीय पहलवान सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक जैसे नायकों की विरासत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाए हैं। लेकिन उन्हें पता है कि पेरिस जाने वाली टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना पड़ा है जिसमें एक साल तक विरोध प्रदर्शन भी शामिल है, जिसके कारण उनकी तैयारियों में बाधा पड़ी। पवार और यादव इसी व्यवस्था के शिकार थे जो आज भी मौजूद है। दोनों 48 किग्रा वर्ग में अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संस्था द्वारा दिए गए वाइल्डकार्ड स्थान के लिए भिड़ रहे थे। राजनीतिक दिग्गजों ने दोनों पहलवानों का

समर्थन किया जिससे यह बड़ा विवाद बन गया जिसमें रेफरी को फिक्स करने से लेकर वजन मापने में धांधली करने के आरोप लगे। हालांकि यादव ने विवादास्पद मुकाबला जीत लिया और अटलांटा चले गए, लेकिन वे वजन मापने की प्रक्रिया में विफल हो गए और बिना प्रतिस्पर्धा के ही वापस लौट आए। ऐसा ही नरसिंह यादव के साथ 2016 रियो ओलंपिक से पहले हुआ था, हालांकि कारण अलग था। नरसिंह ने 74 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में भारत को ओलंपिक कोटा दिलाकर सभी को चौंका दिया था। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के भार वर्ग (66 किग्रा) को खत्म कर दिया था जिसके बाद इस पहलवान को 74 किग्रा वर्ग में खेलना पड़ा। सुशील ने ओलंपिक में पदकों की हैट्रिक लगाने की उम्मीद में ट्रायल के लिए अनुरोध किया ताकि यह तय किया जा सके कि उनमें और नरसिंह में से किसे रियो जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने नरसिंह के चयन को चुनौती देने वाली सुशील की याचिका को खारिज कर दिया। इससे नरसिंह को खेलने की अनुमति मिल गई। हालांकि ओलंपिक से तीन सप्ताह पहले नरसिंह को प्रतिबंधित दवा के लिए पॉजिटिव पाया गया। पहलवान ने खुद को फंसाने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया। हालांकि ओलंपिक में भाग लेने का उनका सपना तब टूट गया जब खेल पंचाट ने नाडा द्वारा उन्हें दी गई क्लीनचिट के खिलाफ विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की अपील को बरकरार रखा। पेरिस ओलंपिक से पहले कुश्ती फिर से गलत कारणों से चर्चा में रही, जब छह शीर्ष पहलवानों ने तब डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एक साल तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय संस्था को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और खेल मंत्रालय दोनों ने अलग अलग कारणों से निलंबित कर दिया। अब नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक नया राष्ट्रीय महासंघ स्थापित हो चुका है। इस विरोध और अदालती मामलों ने भारतीय कुश्ती को जो नुकसान पहुंचाया है वह पेरिस के लिए क्वालीफाई करने वाले पुरुष पहलवानों की संख्या से साफ झलकता है। अमन सेहरावत एकमात्र पुरुष पहलवान हैं जो पेरिस में अपनी किस्मत आजमाएंगे। भारोत्तोलन ने भारत को ओलंपिक में काफी गौरव दिलाया है जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और मीराबाई चानू ने तोक्यो 2021 में रजत पदक जीता था। लेकिन सनमाचा चानू और प्रतिमा कुमारी ने 2004 एथेंस ओलंपिक में डोपिंग के कारण भारत को बदनाम किया था जबकि इससे कुछ दिन पहले डबल-ट्रैप निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेलों में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत रजत पदक दिलाया था। बीजिंग ओलंपिक 2008 के लिए एकमात्र भारोत्तोलक मोनिका देवी एनाबॉलिक पदार्थ के लिए पाजिटिव आने के बाद इसमें हिस्सा लेने से चूक गईं। राठौड़ के रजत पदक जीतने और 2008 में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा के देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के बाद से निशानेबाज भारतीय दल का गौरव रहे हैं। पिस्टल निशानेबाज विजय कुमार और राइफल निशानेबाज गगन नारंग ने 2012 लंदन में इसी परंपरा को बरकरार रखा। लेकिन भारतीय निशानेबाज 2016 रियो और तोक्यो 2021 में पदक जीतने में विफल रहे।

शीतकालीन ओलंपिकः फ्रांस को 2030 और अमेरिका को 2034 की मेजबानी

पेरिस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने बुधवार को 2030 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स और 2034 की मेजबानी अमेरिका के साल्ट लेक सिटी को सौंपने का फैसला किया। फ्रांस को मेजबानी कुछ शर्तों के आधार पर सौंपी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आईओसी को आश्वासन दिया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के संपन्न होने के बाद जो भी सरकार गठित होगी वह आयोजन से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करेगी। इन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। फ्रांस में नई सरकार के गठन के बाद जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उन्हें इन शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। आईओसी ने इसके लिए एक अक्टूबर की समय सीमा तय की है।आईओसी के सदस्यों ने उनके आश्वासन को स्वीकार करके फ्रांस को मेजबानी सौंपने के पक्ष में मतदान किया। फ्रांस की मेजबानी के पक्ष में 84 सदस्यों ने जबकि चार सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। सात सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिय।

पेरिस ओलंपिक को निशाना बनाने की साजिश में गिरफ्तार लोगों में रूस का व्यक्ति भी शामिल

पेरिस। फ्रांसीसी अधिकारियों ने 2024 ओलंपिक को बाधित करने की कई साजिशों को नाकाम कर दिया है जिसमें से एक में रूस के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने पेरिस में खेलों के उद्घाटन समारोह से कुछ दिन पहले बुधवार को यह जानकारी दी। ओलंपिक की मेजबानी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचने के कारण पिछले कुछ हफ्तों से फ्रांस में हाई अलर्ट है। शुक्रवार को सीन नदी पर एक भव्य और उच्च सुरक्षा वाले उद्घाटन समारोह के साथ खेलों की आधिकारिक शुरुआत होगी। पेरिस के अभियोजकों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने ओलंपिक खेलों को अस्थिर करने की योजना बनाने के संदेह में मंगलवार को एक 40 वर्षीय रूसी व्यक्ति को पेरिस में उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड,ए-8, सेक्टर-7, जिला-गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)-201301, दूरभाष-01202470700 से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5 ,बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।